www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 10 जून-16 जून 2013 | मूल्य 5 रुपये

नक्सलवाद से माओवाद तक

पेज : 3

पीड़ित परिवारों को दबोचने की कोशिश

पेज : 4

सिज़ोफ्रेनिया : जब ख़ुद की ही ख़बर न हो

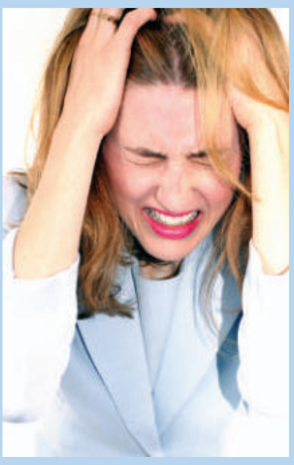

पेज : 7

साईं की महिमा

पेज : 12

चुनावी सर्वे के खेल में

मोदी और राहुल साथ-साथ हैं

देश में होने वाले चुनावी सर्वे न सिर्फ़ भ्रामक हैं, बल्कि उन्हें राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. सर्वे रिपोर्ट्स में नरेंद्र मोदी को एनडीए का ट्रम्प कार्ड और प्रधानमंत्री पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार बताया जा रहा है. साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी. समझने वाली बात यह है कि मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को ही होगा. मोदी की वजह से मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी एवं तमाम सेकुलर पार्टियों को भी फ़ायदा होने वाला है और नुकसान केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा.

मनीष कुमार

लोकसभा चुनाव को अभी क़रीब एक साल बाकी है, लेकिन सर्वे का खेल शुरू हो गया है. चुनाव सर्वे कराने वाली कई पेशेवर एजेंसियां लोगों को यह बताने में जुट गई हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं. सर्वे करने वाली उक्त एजेंसियां यह काम मुफ्त में नहीं करतीं, बल्कि वे सर्वे कराने के पैसे लेती हैं, जिसे टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है. कुछ एजेंसियां टीवी चैनलों के साथ मिलकर सर्वे करती हैं, लेकिन यह सिर्फ़ नाम के लिए होता है. ऐसे सर्वे के बारे में टीवी चैनलों के रिपोर्टरों और एडिटरों को पता भी नहीं होता है कि उनके चैनल द्वारा कोई सर्वे कराया जा रहा है. सबसे पहला सवाल यह उठता है कि अभी से मीडिया में सर्वे का जो खेल शुरू हो गया है, उसे कौन करा रहा है? सर्वे कराने वाली एजेंसियों एवं टीवी चैनलों को पैसे कौन दे रहा है? अगर कोई उन्हें पैसे दे रहा है, तो उसका मकसद क्या है? इनसे किसे फ़ायदा हो रहा है और किसे नुकसान हो रहा है? आख़िर इन चुनावी सर्वे का राज क्या है?

सबसे पहले देखते हैं कि 2014 के चुनाव के लिए किए गए इन सर्वे के निष्कर्ष क्या हैं. एबीपी न्यूज का दावा है कि उसके सर्वे के मुताबिक, देश का मूड मोदी के साथ है और 48 फ़ीसद लोग मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. एबीपी न्यूज पर दिखाया जाने वाला यह सर्वे नेल्शन नामक कंपनी ने किया है. एबीपी न्यूज ने दावा किया है कि उसका यह निष्कर्ष देश के 21 राज्यों में किए गए सर्वे का परिणाम है. हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ़ से भी एक सर्वे आया. वैसे लोगों में यह धारणा है कि यह ग्रुप कांग्रेस पार्टी के नज़दीक है, फिर भी इसमें

> **मीडिया एवं इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी के गुणगान और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर एक आंधी चल रही है. सर्वे रिपोर्ट्स के जरिए कौन इस आग को हवा दे रहा है, ऐसा किस प्रयोजन से हो रहा है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इन सर्वे रिपोर्ट्स का फ़ायदा स्वयं नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी को हो रहा है.**

प्रकाशित सर्वे के मुताबिक, 38 फ़ीसद लोग मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. एक और अहम सर्वे इंडिया टुडे ग्रुप ने देश के सामने रखा है. इस ग्रुप में कई सारे चैनल, समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं शामिल हैं, जिनमें सबसे अहम आजतक न्यूज चैनल है. इनके मुताबिक भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं. इंटरनेट पर भी अगर आप 2014 के चुनाव को लेकर सर्वे ढूंढने जाएं, तो वहां कुकरमुत्ते की तरह फैले सैकड़ों सर्वे मिल जाएंगे. मजे की बात यह है कि हर सर्वे को कई समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं में जगह मिली. इनमें से किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं, यह एक कठिन सवाल है.

कुछ और रोचक सर्वे के बारे में बताता हूं. एक सर्वे लेन्स ऑन न्यूज ने भी कराया. यह सर्वे सिर्फ़ उत्तर प्रदेश

> **नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से कांग्रेस को एक और फ़ायदा होगा. यह फ़ायदा चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन बनाने में होने वाला है. समझने वाली बात यह है कि न तो कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है. अगर किसी को बहुमत मिल भी जाए, तो उसे मिरेकल ही माना जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों को लगता है कि किसी भी सूरत में दोनों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला है.**

में किया गया. इसके मुताबिक, अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को 47 सीटें मिल सकती हैं. कुछ सर्वे ऐसे भी हैं, जो यह बताते हैं कि देश का 70 फ़ीसद युवा मोदी के पक्ष में हैं. अब तक हुए सभी सर्वे का अगर निष्कर्ष निकाला जाए, तो दो बातें मुख्य तौर पर सामने आती हैं. पहली यह कि लोग वर्तमान सरकार से नाराज़ हैं और कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव नहीं जीत सकती. दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह यह कि देश का बहुमत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है. मतलब यह है कि इन सभी सर्वे रिपोर्ट के जरिए भाजपा को संदेश दिया जा रहा है कि कांग्रेस से नाराज़गी का मतलब यह नहीं है कि लोग भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं, बल्कि वे अगली सरकार के रूप में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार चाहते हैं. अब सवाल यह उठता है कि क्या इन सर्वे पर भरोसा किया जाना चाहिए? क्या कोई सर्वे एक साल बाद होने वाले चुनावों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकता है? इन सवालों का सीधा जवाब है, नहीं. यही वजह है कि कोई भी सर्वे सही नहीं साबित होता है और अगर कोई हो भी जाता है, तो वह महज एक अपवाद है या तुक्के में सच साबित हो जाता है. पहला सवाल तो इन सर्वे की विश्वसनीयता पर उठता है. इन सर्वे का परिणाम उसके मुताबिक तैयार किया जाता है, जो इन्हें कराता है और सर्वे करने वाली एजेंसी को पैसे देता है. ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर राजनीतिक दल अपनी रणनीति तय करने के लिए चुनावी सर्वे कराते हैं और कभी-कभी ये चुनावी सर्वे राजनीतिक दलों की रणनीति का हिस्सा होते हैं, जो कि अपने पक्ष में माहौल बनाने और अफवाह फैलाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल होते हैं. अब सवाल यह है कि क्या ये चुनावी सर्वे किसी रणनीति का हिस्सा हैं और अगर हैं, तो ये कहां से संचालित हो रहे हैं?

समझने वाली बात यह है कि कोई भी सर्वे सिर्फ़ सर्वे करने के वक्त जनता का मूड बता सकता है. राजनीति एक गत्यात्मक और सक्रिय प्रक्रिया है. इसमें एक पल में माहौल बदल जाता है. एक बयान से हार और जीत का फ़ैसला हो जाता है. एक छोटी सी भूल चुनाव नतीजे पर प्रभाव डाल देती है. जीत हार में बदल सकती है और कभी-कभी हारा हुआ प्रत्याशी जीत सकता है. राजनीति में किसी एक घटना से न केवल संपूर्ण वातावरण बदल जाता है, बल्कि जनता का मूड बदल सकता है, उसका फ़ैसला बदल सकता है. किस मुद्दे पर जनता का मूड कितना बदलेगा, यह कोई भी सर्वे न तो माप सकता है और न ही इसकी भविष्यवाणी कर सकता है. 2014 में अभी देर है. अभी कई राजनीतिक खेल होने बाकी हैं. 2014 का चुनाव किन-किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, यह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सर्वे
राहुल बनाम

1. एबीपी-निल्सन
- नरेंद्र मोदी — 48 फ़ीसद
- राहुल गांधी — 18 फ़ीसद

2. इंडिया टुडे-ओआरजी
- नरेंद्र मोदी — 24 फ़ीसद
- राहुल गांधी — 17 फ़ीसद

3. हिंदुस्तान टाइम्स-जीएफके
- नरेंद्र मोदी — 38 फ़ीसद
- राहुल गांधी — 23 फ़ीसद

4. ओपेन-सी वोटर
- नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के मुकाबले दस फ़ीसद ज़्यादा लोगों ने पसंद किया

गृह मंत्रालय की यह अनिच्छा सेना कमांडरों के तहत आईपीएस अधिकारियों द्वारा काम करने को तैयार न होने को लेकर है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सेना, गृह मंत्रालय और चीन

चीन के प्रधानमंत्री ली केजियांग की यात्रा ने दिल्ली में कुछ अस्त-व्यस्त माहौल बना दिया था, लेकिन हाल में चीन ने भारतीय सेना और गृह मंत्रालय के बीच इस बात को लेकर रस्साकशी बढ़ा दी है कि भारत-तिब्बत बॉर्डर पुलिस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए. सेना लंबे समय से इस विशेष अर्द्धसैनिक बल पर अधिकार के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन गृह मंत्रालय आईटीबीपी से अपना नियंत्रण हटाना नहीं चाहता. हाल के चीनी अतिक्रमण से एक बार फिर यह मुद्दा सामने आ गया है. सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर जहां सेना को रक्षा मंत्रालय का समर्थन हासिल है, वहीं विदेश मंत्रालय (एमईए) गृह मंत्रालय के साथ है. सचिवों की समिति के इसका हल निकालने में विफल रहने के बाद अब यह मामला मध्यस्थता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के पास भेज दिया गया है. गृह मंत्रालय की यह अनिच्छा सेना कमांडरों के तहत आईपीएस अधिकारियों द्वारा काम करने को तैयार न होने को लेकर है. जाहिर है, मेनन के लिए यह एक मुश्किल काम साबित हो सकता है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अभी तक किसी मंत्री को इस काम के लिए नहीं चुना गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो एंटोनी ही इस काम के लिए पसंद किए जाएंगे. ■

तय हो सकता है कार्यकाल

ऐसे समय में, जबकि सीबीआई निदेशक के कार्यकाल की सीमा तय करने के बारे में बात हो रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संशोधन) नियम, 2006 का कार्यान्वयन रोकने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की है. इसी नियम के तहत देश भर में सभी स्तरों पर अधिकारियों की पोस्टिंग का कार्यकाल तय होता है. अदालत का यह हस्तक्षेप एक पूर्व बाबू एस एन शुक्ला के प्रयासों का नतीजा है. वह इस नियम के तहत आईएएस कैडर के सभी अधिकारियों के लिए एक निश्चित अवधि तय करने और उत्तर प्रदेश एवं 12 अन्य राज्यों में इसे लागू कराने के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे. विडंबना यह है कि आईएएस संवर्ग संशोधन नियम लागू करने का निर्णय 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं. अब अदालत के इस रुख के बाद स्थिति बदल सकती है, क्योंकि यह नियम उस तबादला राज को भी ख़त्म कर सकता है, जिसे नियमित तौर पर सरकारें विशुद्ध प्रशासनिक ज़रूरतों के अलावा अन्य कारणों से भी चलाती रहती हैं. ■

कविता की क़ीमत क्या होगी

अपवाद से अलग, बाबुओं द्वारा साहित्यिक अभिव्यक्ति आम तौर पर सरकारी गलियारों में कम सुनाई देती है. ऐसे में, केरल कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी संध्या ने एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है आई कैन ओनली बी लाइक दिस. इसके लिए उन्हें अपने साथियों एवं नेताओं से आलोचना सुननी पड़ रही है. वे राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों एवं मीडिया पर उनके विचारों से नाखुश हैं. हैरानी की बात यह है कि इस आईपीएस अधिकारी को लेखकों के एक समूह का समर्थन भी हासिल है, लेकिन तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य के पुलिस प्रमुख एवं उनके बॉस के एस बालासुब्रह्मण्यम ने न सिर्फ़ उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या उन्होंने यह कविता लिखने के लिए अनुमति ली थी, बल्कि इस मामले को (सूत्रों के मुताबिक) आगे की कार्रवाई के लिए सरकार को भेज दिया गया है. इस बीच संध्या ने कथित तौर पर एक अन्य कविता भी प्रकाशित कराई है, इसलिए इस मामले का आगे बढ़ना तय है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

जेएस बनने की बारी

1994 बैच के 2 आईएएस अधिकारियों को जल्द ही भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष के रूप में पैनल में शामिल किया जा सकता है. इनके नाम हैं, मनीष जैन (पश्चिम बंगाल) और संतोष कुमार सारंगी (उड़ीसा).

वसुधा एमडी बनीं

आंध्र प्रदेश कैडर एवं 1987 बैच की आईएएस अधिकारी वसुधा मिश्रा को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, कृषि मंत्रालय का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. वर्तमान में वह अपने कैडर में सेवारत हैं.

अश्विनी एनटीआरओ के नए नियंत्रक

1986 बैच के आईआरपीएस अधिकारी अश्विनी कुमार सोनिक को आनंद मिश्रा के स्थान पर राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) का नियंत्रक-प्रशासन नियुक्त किया गया है.

नीलांजन सचिव बने

उड़ीसा कैडर एवं 1979 बैच के आईएएस अधिकारी नीलांजन सान्याल को आयुष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. वर्तमान में वह महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव हैं.

राधाकृष्ण को मिला नया काम

1977 बैच के आईएएस अधिकारी राधाकृष्ण माथुर को रक्षा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है. वर्तमान में वह रक्षा उत्पादन विभाग में सचिव हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मोदी और राहुल साथ-साथ हैं

पृष्ठ एक का शेष

अभी तय नहीं है. अभी तो यह भी तय नहीं है कि किस मुद्दे का कितना असर होगा. सबसे मजेदार बात यह है कि इन सर्वे रिपोर्ट्स में महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दों के असर के बारे में नहीं बताया गया है. जिस तरह से हर दिन घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि देश का राजनीतिक वातावरण बिल्कुल अस्थिर है. इसलिए किसी भी सर्वे में यह क्षमता ही नहीं है कि वह एक साल आगे की भविष्यवाणी कर सके.

जिस तरह से ये सर्वे चुनाव से पहले ही मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करने में लगे हुए हैं, इसमें एक मेथॉडोलाजिकल एरर (प्रणाली संबंधी दोष) है. भारत में मतदाता प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, वे सिर्फ़ अपने सांसद को चुनते हैं. सांसद को चुनते वक्त लोग प्रत्याशियों की प्रामाणिकता आंकते हैं. पार्टी और प्रधानमंत्री साधारण मतदाताओं के दिमाग में नहीं होते हैं. दूसरी बात यह कि जिस तरह से राजनीतिक दल लोगों को शराब देकर, पैसे देकर और दूसरे किस्म के प्रलोभन देकर वोट लेते हैं, यह वास्तविकता सर्वे रिपोर्ट्स में शामिल नहीं होती है. वैसे भी प्रधानमंत्री कौन होगा, यह चुनाव के बाद संसद में पार्टियों की सदस्य संख्या देखकर ही तय होता है. यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय राजनीति का एक चमत्कारिक पहलू भी है. इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह खुद प्रधानमंत्री बनने वाले को भी नहीं पता होता है. मोरारजी देसाई से लेकर मनमोहन सिंह तक कई उदाहरण हमारे सामने हैं. इसलिए जब बड़े-बड़े मीडिया समूह चुनाव से एक साल पहले से ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने पर आमादा हैं, तो इसमें ज़रूर कोई बात है.

इसमें कोई शक नहीं कि मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. वह चाहते हैं कि भाजपा उन्हें जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन पार्टी के अंदर खेमेबाजी है और भविष्य को लेकर चिंता भी है. चिंता की वजह यह है कि भाजपा के रणनीतिकार जानते हैं कि पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है और मोदी को सामने रखकर गठबंधन बनाना भी कठिन है, क्योंकि न तो नए साथी मिलेंगे और जो पुराने सहयोगी हैं, वे भी एनडीए से बाहर चले जाएंगे. इसलिए भारतीय जनता पार्टी मोदी का नाम घोषित करने में झिझक रही है. वहीं, कांग्रेस पार्टी वास्तविकता से वाकिफ है. लोगों में कांग्रेस के प्रति नाराज़गी है, वह चुनाव नहीं जीत सकती. कांग्रेस के रणनीतिकारों को पता है कि 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने का एकमात्र उपाय नरेंद्र मोदी हैं. अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी. इस तर्क में सच्चाई है, क्योंकि मोदी के सामने आते ही मुस्लिम वोटों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण होगा, जिसका फ़ायदा कई राज्यों में सीधे कांग्रेस को मिलेगा और कई राज्यों में उसके साथ जुड़े यूपीए की सहयोगी पार्टियों को मिलेगा. इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए.

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने से कांग्रेस को एक और फ़ायदा होगा. यह फ़ायदा चुनाव परिणाम आने के बाद गठबंधन बनाने में होने वाला है. समझने वाली बात यह है कि न तो कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है. अगर किसी को बहुमत मिल भी जाए, तो उसे मिरेकल ही माना जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों को लगता है कि किसी भी सूरत में दोनों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला है. इसलिए सरकार बनाने के लिए गठबंधन बनाना पड़ेगा. सरकार भी उसी की बनेगी, जो सबसे बड़ा गठबंधन बनाने में सफल होगा. नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं कांग्रेस पार्टी को बैठे-बिठाए समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, मायावती, रामविलास पासवान, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, लालू यादव, नीतीश कुमार एवं शरद यादव के सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होगा.

मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने से एक और परिदृश्य उभर सकता है, लेकिन यह क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की कुशलता पर निर्भर करता है. कांग्रेस यह मान रही है कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का फ़ायदा उसे होगा, लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों ने अपना दम-खम क़ायम रखा, तो वे भी इस ध्रुवीकरण का फ़ायदा उठा सकते हैं. इस ध्रुवीकरण का मकसद मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सारे रास्तों को रोकना होगा. मुसलमान उसी उम्मीदवार को वोट देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है. ऐसे में मुलायम सिंह यादव, मायावती, रामविलास पासवान, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, लालू यादव, नीतीश कुमार एवं शरद यादव को भी फ़ायदा हो सकता है. अगर क्षेत्रीय दलों की कुल सदस्य संख्या 272 से ज़्यादा हो जाती है, जो कि संभव है, तो यह समझना चाहिए कि अगर नेतृत्व को लेकर कोई सहमति बनती है, तो देश में एक बार फिर तीसरे मोर्चे के लिए दरवाजा खुल सकता है.

मीडिया एवं इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी के गुणगान और उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर एक आंधी चल रही है. सर्वे रिपोर्ट्स के जरिए कौन इस आग को हवा दे रहा है, ऐसा किस प्रयोजन से हो रहा है, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इन सर्वे रिपोर्ट्स का फ़ायदा स्वयं नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी को हो रहा है. नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2014 उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मौक़ा है और अगर यह हाथ से चला गया, तो फिर प्रधानमंत्री बनने का मौक़ा शायद ही कभी आए. महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार की वजह से लोग कांग्रेस से नाराज़ हैं, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ना है. कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे अहम चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए यह चुनाव उसके लिए एक अग्नि परीक्षा है. यह भी तय है कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना आवश्यक है, वरना चुनाव जीतना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है. पुलिस जब तहकीकात करती है, तो वह सबसे पहले किसी भी केस में मोटिव, यानी मंशा का निर्धारण करती है. किसी भी तहकीकात का यह उसूल है कि बिना मोटिव के किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दिया जाता है. पुलिसिया तहकीकात की मोटिव थ्योरी को अगर हम वर्तमान राजनीति पर लागू करें, तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करने वाले (फर्ज़ी) सर्वे का प्रायोजन या तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी.■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 14
दिल्ली, 10 जून–16 जून 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
	6452888
	011–23418962
विज्ञापन व प्रसार	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन लगभग कई गुटों में बंटे माओवादी संगठनों के विलय से हुआ. इसमें मुख्य रूप से एमसीसी एवं पीडब्लूजी शामिल हैं.

नक्सलवाद से माओवाद तक

छत्तीसगढ़ में हालिया माओवादी हमले के बाद एक बार फिर से देश में माओवाद और माओवादी केंद्रीय बहस का मुद्दा बन चुके हैं. इसके समर्थन और विरोध में तमाम तर्क-वितर्क किए जा रहे हैं. आइए, इन तर्कों-वितर्कों और समर्थन-विरोध से इतर एक नज़र इसके इतिहास पर डालते हैं.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल का एक गांव, जहां कानू सान्याल के नेतृत्व में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीएम) के एक वर्ग ने 1967 में विद्रोह शुरू किया. 18 मई, 1967 को सिलीगुड़ी किसान सभा एवं भूमिहीनों की सभा ने कानू सान्याल के सशस्त्र संघर्ष को समर्थन देने की घोषणा की. कुछ दिनों के बाद ही नक्सलबाड़ी गांव में एक भूमि विवाद को लेकर लोगों ने जमींदारों पर हमला किया. जब 24 मई को पुलिस दल किसान नेताओं को गिरफ्तार करने पहुंचा, तो आदिवासियों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस निरीक्षक मारा गया. हालांकि, पुलिस गोलीबारी में 9 वयस्कों एवं 2 बच्चों की भी मौत हुई. इस घटना ने आदिवासियों एवं अन्य ग़रीब लोगों को आंदोलन में शामिल होने और स्थानीय जमींदारों पर हमले शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया. इस तरह देश में नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ एक सशस्त्र आंदोलन, यानी नक्सलवाद. 1967 में नक्सलबाड़ी ग़रीब किसानों के विद्रोह स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया. जिस ज़मीन पर यह घटना घटी, वहां पर भाकपा (माले) ने लेनिन, स्टालिन, माओ एवं चारू मजूमदार की प्रतिमाएं लगाई हैं. पुलिस फायरिंग के दौरान जिन लोगों की मौत हुई, उनके नाम पर भी एक स्मारक स्तंभ है.

माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) भारत में दो सबसे बड़े सशस्त्र माओवादी समूहों में से एक था. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन करने के लिए सितंबर 2004 में इसका विलय पीपुल्स वार ग्रुप के साथ हो गया. वैसे तो, एमसीसी 1975 में स्थापित हुआ था, लेकिन इससे पहले एक समूह 1969 में बना, जिसने अलग पहचान बनाए रखने एवं भाकपा (माले) के बाहर बने रहने के लिए अपना गठन किया था और जिसे दक्षिण देश उपनाम दिया गया था. इस समूह को ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं का समर्थन भी हासिल था. दक्षिण देश दक्षिणी भूमि के लिए इस्तेमाल किया गया था. अमूल्य सेन एवं कानाई चटर्जी दक्षिण देश समूह के प्रमुख नेता थे. जंगल महल क्षेत्र में इस समूह की सशस्त्र गतिविधियां चलती थीं. स्थानीय आबादी में एक बड़ा हिस्सा दलितों एवं आदिवासियों का था. गुरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त माने जाने वाले इस इलाके के जंगलों में इनकी गतिविधियां चलती थीं. इनके कई दस्ते थे, जो अनाज भंडारों पर कब्जा करते थे और जमींदारों एवं कथित पुलिस मुखबिरों की हत्या भी करते थे. यह समूह 1973 तक सक्रिय रहा.

1975 में समूह का नाम माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर हो गया. 1976 में एमसीसी देश के अन्य भागों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने लगा. जल्द ही उसने पूर्वी बिहार में अपनी गतिविधियां शुरू कीं और इस उद्देश्य के लिए उसके द्वारा शीर्ष बंगाल बिहार स्पेशल एरिया कमेटी गठित की गई. 1982 में कानाई चटर्जी की मृत्यु हो गई. उनकी मृत्यु के बाद एमसीसी आंतरिक विरोधाभासों से भर गया. चटर्जी के उत्तराधिकारी सिवेजी एवं उनके सहायक रामाधार सिंह कुछ नीतियों पर असहमत थे. सिंह ने पार्टी से नाता तोड़ लिया और वह कानू सान्याल के समूह में शामिल हो गए.

1980 में एमसीसी का नेतृत्व संजय दुसाध एवं प्रमोद मिश्रा ने किया. तब तक एमसीसी का प्रभाव बिहार के मध्य भागों में फैल चुका था. इसके पास 500 पूर्णकालिक कार्यकर्ता और 10,000 सदस्य हो गए थे. एमसीसी के कई विंग थे, जिनमें क्रांतिकारी किसान कमेटी, जनसुरक्षा संघर्ष मंच, क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ एवं क्रांतिकारी छात्र लीग शामिल थे. पार्टी की सशस्त्र इकाई को लाल सुरक्षा बल कहा जाता था. पीपुल्स वार ग्रुप एक भूमिगत पार्टी थी. 2004 में एमसीसी के साथ विलय करके यह भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) में शामिल हो गई. इसकी विचारधारा का आधार मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद था. इस पार्टी की स्थापना कोंडापल्ली सीतारमैया द्वारा 1980 में आंध्र प्रदेश में की गई थी. इससे तेलंगाना क्षेत्र में नक्सली कार्यकर्ता एक बार फिर से सक्रिय हो गए. पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया और उसने चुनावी राजनीति में भागीदारी से इंकार कर दिया. पार्टी शुरू में काफी हद तक तेलंगाना क्षेत्र तक ही सीमित रही, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होता चला गया और यह मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा तक पहुंच गई.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन लगभग कई गुटों में बंटे माओवादी संगठनों के विलय से हुआ. इसमें मुख्य रूप से एमसीसी एवं पीडब्लूजी शामिल हैं. इसका मकसद युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सरकार को अपदस्थ करना है. यह एक भूमिगत संगठन है, जिस पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया जा चुका है. इसकी स्थापना सितंबर, 2004 में की गई थी. तत्कालीन पीपुल्स वार ग्रुप के नेता मुपाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को केंद्रीय समिति का महासचिव बनाया गया था. यह संगठन मध्य भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल के आसपास के वन्य क्षेत्र में जनजातियों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता है. नए संगठनात्मक विस्तार के तहत यह संगठन बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु एवं कर्नाटक तक पहुंच चुका है. इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनिज संसाधन हैं और खनन कार्य होता है, जिसे निजी कंपनियां करती हैं. ■

कब कितने मरे

वर्ष 2004 में अपने गठन से 2011 के बीच भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने क़रीब 300 से अधिक छोटे-बड़े हमले किए हैं. वर्षवार हमलों और मृतकों की संख्या पर एक नज़र:-

वर्ष	हमले की संख्या	मृत्यु	घायल
2004	1	-	-
(लेकिन भारी मात्रा में गोला-बारूद की लूट)			
2005	7	11	21
2006	12	20	14
2007	44	64	36
2008	42	87	40
2009	75	121	27
2010	81	204	29
2011	67	52	54

आंदोलन एक नजर में

- भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन 21 सितंबर, 2004 को हुआ था.
- पीडब्लूजी और एमसीसीआई के विलय से यह अस्तित्व में आई.
- पीपुल्स वार ग्रुप का गठन 1980 में हुआ था.
- कोंडापल्ली सीतारमैया इस ग्रुप के नेता थे.
- नारायण सान्याल के नेतृत्व वाले यूनिटी ग्रुप का अगस्त 1998 में पीपुल्स वार ग्रुप के साथ विलय.
- एमसीसी का गठन 20 अक्टूबर, 1969 को कानाई चटर्जी के नेतृत्व में हुआ. पहले यह ग्रुप दक्षिण देश के रूप में जाना जाता था.
- जनवरी, 2003 में एमसीसी और पंजाब आधारित रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विलय.
- नया नाम माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (एमसीसीआई) हो गया.

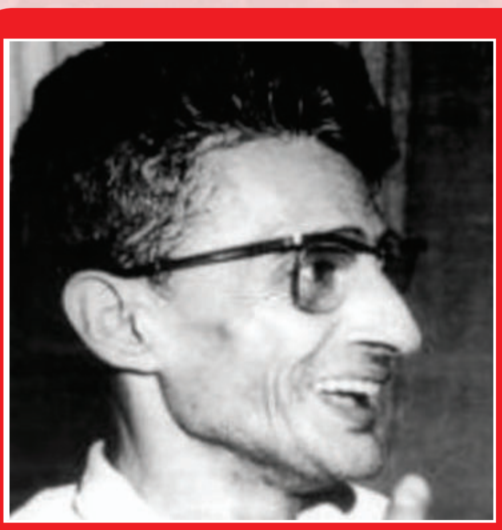
चारू मजूमदार

कानू सन्याल

दक्षिण देश दक्षिणी भूमि के लिए इस्तेमाल किया गया था. अमूल्य सेन एवं कानाई चटर्जी दक्षिण देश समूह के प्रमुख नेता थे. जंगल महल क्षेत्र में इस समूह की सशस्त्र गतिविधियां चलती थीं. स्थानीय आबादी में एक बड़ा हिस्सा दलितों एवं आदिवासियों का था. गुरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त माने जाने वाले इस इलाके के जंगलों में इनकी गतिविधियां चलती थीं. इनके कई दस्ते थे, जो अनाज भंडारों पर कब्जा करते थे और जमींदारों एवं कथित पुलिस मुखबिरों की हत्या भी करते थे. यह समूह 1973 तक सक्रिय रहा.

घटना के बाद सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करके जस्टिस माधवेंद्र शरण को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

बिहार

भजनपुरा पुलिस गोलीकांड

पीड़ित परिवारों को दबोचने की कोशिश

सत्ता का वरदहस्त अक्सर लोगों को बेलगाम बना देता है. यही भजनपुरा में हुआ. ग्रामीणों ने रास्ते की ज़मीन हड़पने का विरोध क्या किया, राजनीतिक दबंगों के इशारे पर पुलिस ने फायरिंग करके एक बच्चे समेत पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया. अफसोस की बात तो यह है कि घटना के दो वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन दोषियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

अशरफ अस्थानवी
feedback@chauthiduniya.com

फारबिसगंज के भजनपुरा में पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार वालों को न्याय मिलना तो दरकिनार, उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने का जाल बुना जा रहा है, जिसके चलते भजनपुरा गांव के लोग दहशत में हैं. पुलिस पर फायरिंग एवं पथराव के आरोप में अब तक 44 लोगों के ख़िलाफ़ वारंट जारी हो चुके हैं. गिरफ्तारी के डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए हैं. उधर पुलिस ने कुर्की-जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है. जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, उनमें से एक को पुलिस ने 3 जून, 2011 को ही गोलियों से भून डाला था. बताया जाता है कि अररिया के सीजीएम की अदालत में पीड़ित परिवारों की ओर से दायर मुकदमे की सुनवाई में ही बेईमानी हो रही है, जबकि सुंदरम ग्लूकोज फैक्ट्री के मालिक और जिला प्रशासन की ओर से दायर मुकदमों की सुनवाई तेजी के साथ करते हुए पीड़ित परिवारों के सदस्यों की गिरफ्तारी के वारंट और कुर्की-जब्ती के फरमान जारी कर दिए गए. लोगों का आरोप है कि सत्ताधारी दल के लोगों के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है. आश्चर्य की बात तो यह है कि विरोधी दलों के नेता भी इस मामले पर खामोश बैठे हैं. पीड़ित परिवारों को जानबूझ कर फंसाने के पीछे मंशा यह है कि जिस जुबान से वे न्याय-न्याय चिल्ला रहे हैं, उसी को छीन लिया जाए. ग़ौरतलब है कि 3 जून, 2011 को भजनपुरा में एक रास्ते के विवाद में पुलिस फायरिंग में एक 2 माह के बच्चे समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी. इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी सुनील यादव ने एक मृत व्यक्ति के शरीर और चेहरे को अपने बूटों से कुचल डाला. हैरत की बात यह है कि सुनील को कुछ महीने बाद ही जमानत मिल गई. जबकि स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि उसकी यह हरकत घृणित है और उसे कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन वह जमानत पाकर आज़ाद हो गया. नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी क़दम उठा रही है, लेकिन भजनपुरा जैसी घटनाएं उनके दावे को बिल्कुल झुठलाती हैं.

घटना के बाद सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करके जस्टिस माधवेंद्र शरण को 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था. आयोग को घटना की जांच कर तथ्य इकट्ठे करने थे, लेकिन उसके कामकाज की रफ्तार इतनी धीमी रही कि बार-बार उसका समय बढ़ाया जाता रहा. अब उसे 31 दिसंबर, 2013 तक रिपोर्ट सौंपने की मोहलत दे दी गई है. आयोग ने अब तक जिस तरीके से काम किया है, उससे दोषियों के ख़िलाफ़ कोई मामला बनने या कार्रवाई की गुंजाइश कम ही लगती है. पीड़ित पक्षों की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय का वकील नियुक्त करने की मांग भी ठुकरा दी गई. इस घटना के केंद्र में रहे भाजपा के विधान पार्षद अशोक अग्रवाल को बचाने की हरसंभव कोशिश की जा रही है. वह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के क़रीबी बताए जाते हैं और अपने प्रभाव के जरिए स्थानीय प्रशासन को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं. धन, बल और पहुंच के सहारे उन्होंने कई गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए मजबूर कर दिया. ग़ौरतलब है कि विवादित क्षेत्र में उनकी सुंदरम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ग्लूकोज फैक्ट्री लगनी है, जिसके समीप एक रास्ते के विवाद को लेकर पुलिस फायरिंग की घटना घटी थी. गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी जब घटना की प्रारंभिक जांच करने पहुंचे, तो उन्होंने इसे क्रॉस फायरिंग का मामला बताया, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था. इसीलिए बीते वर्ष छठ पूजा के दौरान पटना में गंगा के किनारे अदालत घाट पर हुए चचरी पुल हादसे की जांच जब

उन्हें सौंपी गई, तो लोगों ने यह कहते हुए विरोध किया कि वह भजनपुरा की तरह इस मामले की भी लीपापोती कर देंगे.

भजनपुरा के पीड़ितों को भी अब शायद ही न्याय मिल सके. इस आशंका को नीतीश सरकार के रुख से बल मिलता है, क्योंकि घटना के सात माह बाद जिले की एसपी गरिमा मलिक का स्थानांतरण तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें सीनियर एसपी के रूप में प्रोन्नति दे दी गई. इस घटना को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष तीन पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन पीड़ित पक्ष की प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे उनके ख़िलाफ़ वारंट जारी हो गए. हैरत की बात यह है कि उस जलील अंसारी के नाम भी वारंट जारी हो गया, जिसकी मौत पुलिस की गोली से हुई थी और जिसके शरीर को पुलिसकर्मी सुनील यादव ने अपने बूटों से कुचला था. घटना के बाद राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की उपेक्षा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह ने जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने घटनास्थल पर जाना या कोई टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं समझा. राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नौशाद अहमद घटना के दो वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी खामोश हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताते हुए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद नीतीश सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. यही नहीं, पीड़ित परिवारों को आज तक किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी गई, जबकि सभी अत्यंत ग़रीब हैं. ग्रामीणों की ओर से दायर मुकदमों को कमजोर करने का प्रयास भी किया जा रहा है. गांववासी कहते हैं कि उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अररिया की तत्कालीन एसपी गरिमा मलिक की भूमिका की जांच अवश्य होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.

भजनपुरा के पीड़ितों को भी अब शायद ही न्याय मिल सके. इस आशंका को नीतीश सरकार के रुख से बल मिलता है, क्योंकि घटना के सात माह बाद जिले की एसपी गरिमा मलिक का स्थानांतरण तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें सीनियर एसपी के रूप में प्रोन्नति दे दी गई. इस घटना को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष तीन पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन पीड़ित पक्ष की प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टे उनके ख़िलाफ़ वारंट जारी हो गए.

मृतकों की सूची

मो मुस्तफा (18 वर्ष), मुख्तार अंसारी (20 वर्ष), नौशाद अंसारी 3 माह का दुधमुंहा बच्चा, जिसे मां की गोद में पुलिस ने गोली मार दी, फेकन अंसारी (25 वर्ष). साथ ही गर्भवती महिला रशीदा बेगम 28 वर्ष सहित 15 अन्य ग्रामीणों को भी गोली लगी, जिनमें से कई लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है.■

उत्तर प्रदेश

तबादलों की मार से हलकान आईपीएस लॉबी

ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना आज के समय में अपराध जैसा हो गया है. उत्तर प्रदेश के कई आईपीएस अधिकारी आजकल इसी दर्द से दो-चार हो रहे हैं. अगर वे क़ानून के मुताबिक चलते हैं या फिर राजनेताओं की बात नहीं सुनते हैं, तो पलक झपकते ही उनका बोरिया-बिस्तर बांध दिया जाता है, यानी तबादला.

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी इन दिनों नाकारा एवं नाकाम पुलिस अधिकारियों के तबादले करके उन्हें जहां-तहां फेंक रही है, जबकि अच्छे अधिकारियों से काम नहीं लिया जा रहा है. इस मामले में सरकार भले ही कुछ कहे, लेकिन राज्य के गृह विभाग के दस्तावेज़ तो यही कहते हैं कि आईपीएस अधिकारियों को एक जगह कुछ माह तक रुककर काम करने का मौक़ा ही नहीं दिया जाता. ऐसे में अगर क़ानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए आईपीएस अधिकारियों की बजाय सरकार को ज़िम्मेदार माना जाए, तो गलत नहीं होगा. प्रदेश के ऐसे आईपीएस, जिनका तबादला किया जाता रहा है, वे ऑन द रिकार्ड तो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन दबी जुबान से यह स्वीकार ज़रूर करते हैं कि उनके तबादलों के पीछे उनकी कार्यशैली में कमी नहीं है. पूर्व डीजी के के बंसल कहते हैं कि पुलिस अधिकारियों पर तबादलों की मार राजनेताओं को खुश न कर पाने के कारण ज़्यादा पड़ती है. एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के छोटे-बड़े सभी नेता चाहते हैं कि हम उनके आगे सलाम ठोंके, वे जब बुलाएं, तो हम दौड़े चले जाएं, उनके आदमियों को संरक्षण दें और जिसे वे चाहें, उसे जेल भेज दिया जाए. जो अधिकारी ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें किसी जिले में रुकने नहीं दिया जाता है. पुलिस अधिकारियों को अपने हिसाब से काम करने की छूट ही नहीं है.

राजनेताओं को खुश न कर पाने वाले सैकड़ों आईपीएस अधिकारी तबादलों की मार से आहत हैं. पूर्व पुलिस महानिदेशक कन्हैया लाल गुप्ता कहते हैं कि निष्क्रियता अथवा प्रशासनिक अक्षमता के कारण किसी अधिकारी का स्थानांतरण किया जाना तो जायज है, लेकिन जातीय आधार पर अथवा राजनीतिक द्वेष के कारण जनहित के नाम पर तबादला करना कतई उचित नहीं है. यह चलन पिछले एक दशक से तेजी से बढ़ा है, जिससे क़ानून व्यवस्था प्रभावित हुई है. कई अफसरों का तो 40 से अधिक बार स्थानांतरण हो चुका है, जिनमें 16 डीजी, 13 आईजी, 10 डीआईजी और 4 एसपी शामिल हैं. छोटी सी अवधि में अगर कोई एसपी 40 से अधिक बार स्थानांतरित होता है, तो निश्चित ही इसके पीछे सरकार की ईमानदार सोच नहीं है. यही वजह सत्ता की मंशा पर संदेह का एक बड़ा आधार बनती है. ऐसा नहीं है कि तबादलों का यह खेल सपा राज में ही चल रहा है, बल्कि बसपा राज में भी कमोबेश यही हालत थी. तबादले-पोस्टिंग में सेटिंग-गेटिंग का खेल भी जमकर होता है. मलाईदार पदों के लिए रुपया चलता है. पूर्ववर्ती बसपा सरकार तो इस मामले में काफी बदनाम हुई थी. समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर भी इस तरह के कई गंभीर आरोप लगे थे.

आरटीआई कार्यकर्ता एवं समाजसेविका डॉ. नूतन ठाकुर ने इस संबंध में अनेक जानकारियां एकत्र की हैं, जैसे कि आईपीएस कमल सक्सेना का 48 बार तबादला हो चुका है और विजय सिंह का 47 बार. डीजी स्तर के अधिकारी रहे अरुण कुमार गुप्ता का 45 बार तबादला हुआ और विनोद कुमार सिंह का 43 बार. इसके उलट कुछ अधिकारियों के साथ पूरी नरमी बरती गई. गृह विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि डीजी स्तर के अधिकारी रहे राजीव कपूर अपने पूरे कार्यकाल में महज सात बार स्थानांतरित किए गए.

आरटीआई कार्यकर्ता एवं समाजसेविका डॉ. नूतन ठाकुर ने इस संबंध में अनेक जानकारियां एकत्र की हैं, जैसे कि आईपीएस कमल सक्सेना का 48 बार तबादला हो चुका है और विजय सिंह का 47 बार. डीजी स्तर के अधिकारी रहे अरुण कुमार गुप्ता का 45 बार तबादला हुआ और विनोद कुमार सिंह का 43 बार. इसके उलट कुछ अधिकारियों के साथ पूरी नरमी बरती गई. गृह विभाग के दस्तावेज बताते हैं कि डीजी स्तर के अधिकारी रहे राजीव कपूर अपने पूरे कार्यकाल में महज सात बार स्थानांतरित किए गए. उनकी गिनती काम करने वाले अच्छे अधिकारियों में होती थी. एडीजी स्तर के एम के सिन्हा का 9, भगवान स्वरूप श्रीवास्तव का 13, तनुजा श्रीवास्तव एवं डीआईजी भानु भास्कर का 15 बार स्थानांतरण किया गया. एक आईपीएस लगभग 32 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले डीजी बनता है. डीजी रैंक के अफसरों का साल में एक से अधिक बार स्थानांतरण किया गया. एडीजी स्तर के अधिकारी औसतन 35.9 बार, आईजी स्तर के अधिकारी 31.8 बार और डीआईजी स्तर के अधिकारी 29.7 बार स्थानांतरित किए गए.

पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की न्यूनतम दो साल की तैनाती अनिवार्य किए जाने का निर्देश दे रखा है, लेकिन प्रदेश में इसका कभी पालन नहीं हुआ. सरकार कोई न कोई दांव चलकर आईपीएस अधिकारियों को इधर-उधर पटकती रहती है. कई बार सरकार को इसके लिए अदालतों की फटकार भी सुननी पड़ती है. राजनेताओं के कारण तबादलों की मार झेलने वाले आईपीएस अधिकारियों की मुट्ठी हमेशा तनी रहती है. अपने सेवाकाल के दौरान 59 बार तबादलों का दंश झेल चुके पूर्व पुलिस महानिदेशक कन्हैया लाल गुप्ता का कहना है कि निष्क्रियता अथवा प्रशासनिक अक्षमता के कारण अधिकारियों का स्थानांतरण पूरी तरह जायज है, लेकिन जातीय आधार अथवा राजनीतिक कारणों से किसी अधिकारी का तबादला कतई उचित नहीं है. पिछले डेढ़ दशकों से जनहित का नाम देकर अच्छे एवं योग्य अधिकारियों के तबादले का चलन तेजी से बढ़ा है, जिससे क़ानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है. अपने समय के धाकड़ आईपीएस अधिकारी श्रीराम अरुण का कहना है कि जब अफसर ही मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए नेताओं की परिक्रमा करेंगे और ले-देकर प्राइज पोस्टिंग पाएंगे, तो गॉड फादर की नाराज़गी झेलनी ही पड़ेगी.

पूर्व डीजी महेंद्र लालका कहते हैं, मैंने अपने सेवाकाल के दौरान हमेशा जो सही समझा, वहीं निर्णय लिया. दबाव में काम न करने की सजा स्थानांतरण के रूप में ज़रूर मिली, लेकिन तत्कालीन नेताओं ने मेरे बारे में यह प्रचारित कर दिया कि इससे कोई सिफारिश करना बेकार है, क्योंकि यह अफसर सुनेगा नहीं. यही वजह थी कि जब भी किसी बड़े जिले में कोई गंभीर संकट आया, तो मुझे वहां भेजा गया और मैंने अपने ढंग से उस संकट का निराकरण भी किया. दरअसल, आईपीएस अधिकारी तबादलों के कारण अक्सर तनाव में रहते हैं. कुछ अधिकारी तो यहां तक कहते हैं कि वे हमेशा अपने घर की चौखट पर सामान लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें कब और कहां उठाकर फेंक दिया जाएगा, यह तय नहीं है. अंधाधुंध तबादलों के कारण उनका पारिवारिक जीवन काफी तनावपूर्ण रहता है. वे बच्चों को हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए उन्हें किसी बड़े शहर में उनके हाल पर ही छोड़ना पड़ता है. ■

केएल गुप्ता

प्रकाश सिंह

श्री राम अरुण

साब्री सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव गोपाल कृष्ण वर्मा का कहना है कि बालू उत्खनन के कारण नदी का तल धीरे-धीरे गहरा हो रहा है.

बिहार

बाढ़ विस्थापितों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं

सीमावर्ती ज़िले के बाढ़ विस्थापित आज भी अपने पुनर्वास की राह देख रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही है. आख़िर कब और कौन करेगा उनके साथ न्याय?

वाल्मीकि कुमार
feedback@chauthiduniya.com

जब नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है, तब भारतीय क्षेत्र में तबाही का ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि लोगों की जुबां तक नहीं हिल पाती. हंसता-खेलता गांव महज चंद मिनटों में ही बाढ़ के पानी में विलीन हो जाता है. ऐसे में केवल इंसान ही नहीं, पशुओं के लिए भी जान बचाना काफी मुश्किल हो जाता है. भूख से बिलखते बच्चों की टोली, बीमारी से परेशान लोग, प्रसव पीड़ा से कराहती महिलाएं और सड़क के किनारे बेजुबान-बेबस मवेशियों का झुंड...कुछ ऐसा ही नजारा होता है, भारत-नेपाल के सीमावर्ती सीतामढ़ी जिले के तकरीबन आधा दर्जन प्रखंडों में. ऐसा भी नहीं है कि यह अनायास आई कोई आफत हो, क्योंकि ऐसा यहां दशकों से होता रहा है. और तब स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक पीड़ितों के बीच पहुंच कर घड़ियाली आंसू बहाने से बाज नहीं आते हैं.

महीनों तक मुआयने और कागजी कार्रवाई की कवायद चलती रहती है. फिर जैसे ही बाढ़ और बरसात का समय गुजर जाता है, सभी पूर्ववत अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं, जैसे ज़िले में किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं, बल्कि ईश्वरीय वरदान का आगमन लोगों के बीच हुआ हो. सत्ता की कुर्सी पर विराजमान नेताओं की जमात जहां झूठी घोषणाओं के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में वक्त गंवाती है, वहीं विरोधी दल के नेता भी चंद दिनों तक अख़बारों की सुर्ख़ियां बनने के बाद फिर किसी नए मामले को लेकर आंदोलन की तैयारी में लग जाते हैं. कुल मिलाकर बाढ़ से अभिशप्त ज़िले के लोगों के जख्मों पर मरहम रखने में सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि सभी समान रूप से नकारा साबित होते रहे हैं. नतीजा यह कि दशकों पूर्व अपना हंसता-खेलता घर-परिवार गंवा चुके लोग आज तक जैसे-तैसे जीवनयापन करने के लिए विवश हैं. कोई शहर में जीवन गुजार रहा है, तो कोई अपनी बदनसीबी का रोना गांव की झोपड़पट्टी में रो रहा है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है.

चुनाव का समय आते ही सभी को पीड़ितों के दुःख-दर्द याद आने लगते हैं. सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के साथ समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाकर लोगों के वोट अपने पक्ष में करने की तैयारी में जुट जाते हैं. वर्ष 2005 में नेपाली पानी से होने वाले तबाही को लेकर तत्कालीन निर्दलीय विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर एवं संघर्ष यात्रा के संयोजक शशि शेखर के नेतृत्व में भारत-नेपाल सीमा को सील करके आंदोलन का रूप दिया गया था, लेकिन धरना-प्रदर्शन की कवायद कोई खास असर डालने में नाकाम रही. नतीजतन, प्रति वर्ष बाढ़ आती है और लोग पूर्ववत भारी तबाही का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं. वर्ष 2002 में प्रतिपक्ष के नेता रहे वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मेजरगंज के तत्कालीन भाजपा विधायक गौरी शंकर नागदंश समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करके तत्कालीन सरकार से पीड़ितों को मदद दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज एक दशक बाद भी मोदी के हाथ में सत्ता आने के बावजूद ज़िले के सुप्पी प्रखंड के सोनाखान गांव के पीड़ितों को किसी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग नहीं मिल सका है. पीड़ित भी सरकारी सहयोग की आस में वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाकर समय गंवाना बेकार समझते हैं.

2005 में सूबे की एनडीए सरकार के कार्यकाल में रामपुर कंठ गांव के समीप भी कटाव से बांध क्षतिग्रस्त हुआ था, जहां वर्तमान में करोड़ों की लागत से मिट्टी भराई का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन 2002 के पीड़ितों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया. जहां तक बांध की मरम्मत का सवाल है, तो उस पर लोगों का कहना है कि सरकारी स्तर पर महज खानापूर्ति की गई है.

ग़ौरतलब है कि 2002 से लेकर 2005 तक, मात्र तीन वर्षों के सरकारी आंकड़ों ने साबित कर दिया कि बाढ़ के कारण ज़िले में तकरीबन साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की सरकारी एवं ग़ैर-सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ. सड़कों, पुलों एवं पुलियों की भी बड़े पैमाने पर क्षति हुई. सोनाखान के अलावा, सिरसिया, सौली, चंदौली, सुरगाही एवं मझौरा समेत तकरीबन एक दर्जन गांवों के लोगों को खानाबदोश की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी. वर्ष 2002 में सोनाखान गांव के समीप बागमती तटबंध कटाव के चलते ध्वस्त हो गया था. उस समय तेज पानी के बहाव में सोनाखान गांव के काशीनाथ सिंह, राम बहादुर सिंह, किशुन सिंह, शैलेंद्र सिंह, शशि भूषण सिंह, बिगन राउत, भिरज राउत, अकलू राउत, बेला राउत, धनुक साह, भुजंगा साह, उपेंद्र सिंह, गोनौर सिंह, जंग बहादुर सिंह, भुनेश्वर राय, महाराज राय, बाबूलाल महतो, राम बिहारी सिंह, अशोक कुमार सिंह, श्याम बिहारी सिंह, जगन साह एवं कपिलदेव सिंह समेत तकरीबन पांच दर्जन लोगों के घर पानी में विलीन हो गए थे, लेकिन आज तक इन पीड़ितों को किसी भी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग नहीं मिल सका है. हालांकि क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत की कवायद ज़रूर हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि इसमें नेताओं, अधिकारियों एवं ठेकेदारों के लिए लाभ की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन विस्थापित परिवारों को बसाने की दिशा में आज तक कोई पहल ही नहीं की गई.

2005 में सूबे की एनडीए सरकार के कार्यकाल में रामपुर कंठ गांव के समीप भी कटाव से बांध क्षतिग्रस्त हुआ था, जहां वर्तमान में करोड़ों की लागत से मिट्टी भराई का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन 2002 के पीड़ितों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया. जहां तक बांध की मरम्मत का सवाल है, तो उस पर लोगों का कहना है कि सरकारी स्तर पर महज खानापूर्ति की गई है. अगर नदी में पूर्व की भांति पानी आ जाए, तो बांध को पुनः टूटने से कोई नहीं रोक सकता है. कारण यह कि उत्तर दिशा से आने वाली नदी का पानी सोनाखान बांध से टकरा कर पश्चिम से दक्षिण होते हुए सीतामढ़ी जिले के परसौनी, बेलसंड एवं रुन्नीसैदपुर प्रखंड होते हुए मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई प्रखंड में प्रवेश कर जाता है, लेकिन उक्त स्थान पर मजबूती शून्य है. दरअसल, विस्थापितों के प्रति ऐसी संवेदनहीनता कोई नई बात नहीं है. इससे पूर्व भी सैकड़ों परिवार विभिन्न प्रखंडों में बाढ़ के चलते विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक भाग्य भरोसे जीवन बिताना पड़ रहा है. अब एक बार फिर पीड़ितों को आगामी लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों से आस जगने लगी है, लेकिन सवाल तो यह है कि आख़िर कौन उनकी उजड़ी दुनिया संवारने का खाका खींच पाएगा? वैसे, झूठी घोषणाओं की बदौलत वोट बटोरने वालों के काफिलों ने जगह-जगह धूल उड़ाना ज़रूर शुरू कर दिया है. ■

बालू की नीलामी, किसानों की तबाही

एक बड़े ख़तरे का संकेत

मुंगेर और बांका ज़िले में जहां एक ओर बालू की नीलामी के कारण सरकारी राजस्व बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह स्थानीय किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है. क्या है पूरा मामला, पढ़ें चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

वाल्मीकि कुमार
feedback@chauthiduniya.com

बालू की नीलामी मुंगेर और बांका ज़िले के किसानों के लिए तबाही का सबब लेकर आई है. इससे न केवल खेती-किसानी चौपट हो रही है, बल्कि खेती का लागत ख़र्च भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है. सरकार की अव्यवहारिक नीति के कारण नीलामी से मिलने वाले राजस्व से अधिक का भुगतान किसानों को डीजल एवं अन्य अनुदानों के रूप में करना पड़ रहा है. साथ ही यहां कई क्षेत्रों में पेयजल संकट भी गहरा गया है. किसानों में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है, लेकिन उनकी इस पीड़ा से प्रशासन को कोई लेना-देना नहीं है. आश्चर्य की बात तो यह है कि सेवा यात्रा पर निकले राज्य के मुख्यमंत्री भी इससे बेफिक्र दिखे. तारापुर में 122 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण एक साथ किया गया तथा सायरन बजाती, धूल उड़ाती गाड़ियों के बीच बुलेटप्रूफ कार में बैठे राज्य के मुखिया की यात्रा अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ी. एक स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि बटन दबाकर शुरू होती है कार और जिसे धक्का देकर सरकाना पड़ता है, वह है सरकार, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं चलती. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आक्रोश को संगठित ताक़त के रूप में बदलना होगा और सच तो यह है कि लोकशाही में संगठित ताक़त से ही सरकार को झुकाया जा सकता है. इस बुजुर्ग के कथन में सरकार की अव्यवहारिक नीति के ख़िलाफ़ आक्रोश की अभिव्यक्ति है. आक्रोश का लावा कभी भी फूट सकता है. सेवा यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में इन मुद्दों पर अनशन किया जाना, इसी के नतीजे के रूप में देखा जा सकता है.

इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार खेती है. राज्य सरकार भले ही कृषि के रोडमैप की बात करती हो, लेकिन इस क्षेत्र के किसान कहते हैं कि क्या हमारी खेती-किसानी को चौपट करने की क़ीमत पर यह रोडमैप है या फिर इसे बचाने का मुद्दा भी इसमें शामिल होगा? बदुआ नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी मानी जाती थी, लेकिन आज वह अभिशप्त हो गई है. नदी की अविरलता ख़त्म हो गई है. संसाधनों के दोहन के कारण इस जीवनदायिनी नदी का अस्तित्व अब खुद ख़तरे में है. इस जीवनदायिनी नदी की जीवंतता के कारण ही यहां के जलस्रोत रिचार्ज होते रहते थे. कुएं, ताल एवं तलैये हमेशा आबाद रहते थे. बाद में सरकारी खनन विभाग द्वारा नदियों की बालू की नीलामी होने लगी, जिसने इस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था ही चौपट कर डाली. बालू की नीलामी से भले ही अधिकारियों, ठेकेदारों, माफियाओं एवं पुलिस की चांदी हो गई हो, लेकिन इससे यहां पानी का स्तर कम हो गया है. फरवरी माह से ही जलस्रोतों का सूखना आने वाले समय में एक बड़े ख़तरे का संकेत है.

इस नदी से सिंचाई के लिए जगह-जगह ढांड़ और नहर बनाए गए हैं, पानी उनके नीचे से होकर गंगा में बह जाता है. कल तक जो किसान इस नदी की नहर और ढांड़ पर निर्भर रहते थे, आज उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है. अब वे नलकूप का इस्तेमाल कर रहे हैं. नलकूप चलाने के लिए न केवल डीजल की आवश्यकता होगी, बल्कि खर्च भी बढ़ेगा. डीजल के इस्तेमाल के लिए सरकार को सब्सिडी देनी होगी. अव्यवहारिक नीति और लागत ख़र्च बढ़ने के फलस्वरूप खेती स्वावलंबन का आधार न होकर इंद्रजाल बनकर रह गई है. किसानों को नहर और ढांड़ का पानी नहीं मिल रहा है, वहीं भूजल का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है. इसका असर पेयजल की उपलब्धता पर पड़ रहा है. इस नदी के साथ न केवल सरकारी तंत्र ने खिलवाड़ किया, बल्कि जनप्रतिनिधि भी जल का दोहन करने से बाज नहीं आए. एक व्यक्ति ने बताया कि पूर्व विधायक शकुनी चौधरी जब सत्ता में थे, तो अपने प्रभाव से वह नहर का पानी अपने गांव ले गए, जिसके चलते अन्य क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचा. ग़ौरतलब है कि बालू की नीलामी से मुंगेर को 60 लाख और बांका को एक करोड़ रुपये की आमदनी होती है. हालांकि यह नीलामी जनप्रतिनिधियों की भावना के प्रतिकूल है. 1978 में विधान परिषद सदस्य पशुपतिनाथ सिंह प्रबल की अध्यक्षता में गठित समिति ने बालूघाट की नीलामी पर रोक लगाने की अनुशंसा की थी, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए लगातार बालू की नीलामी की जा रही है.

साब्री सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव गोपाल कृष्ण वर्मा का कहना है कि बालू उत्खनन के कारण नदी का तल धीरे-धीरे गहरा हो रहा है. ऐसे में शाखा नहर एवं ढांड़ का मुंह ऊंचा होने के कारण नदी का पानी गंगा में चला जाता है. इस अव्यवहारिक नीति के कारण ज़मीन के बंजर होने का ख़तरा और बढ़ गया है. बकौल वर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं खनन विभाग के अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराकर उनसे यह मांग की कि वे बडुआ और वेलहरनी नदी की बालू की नीलामी रद्द करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. वह कहते हैं कि अब हम सरकार की इस अव्यवहारिक नीति के ख़िलाफ़ या तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करें या फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें. बालू उत्खनन में भी खनन विभाग के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है. लीज में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नहर के आर-पार सौ-सौ फीट जगह छोड़कर उत्खनन किया जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है. जिला पदाधिकारी कुलदीप नारायण जब इस क्षेत्र में गए थे, तो लोगों ने उत्खनन से हो रहे ख़तरे से उन्हें अवगत कराया था और उन्होंने इसके लिए खनन विभाग के अधिकारियों को न केवल फटकार लगाई थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उत्खनन कार्य लीज की शर्तों के अनुरूप ही किया जाए.

किसान संगठन से जुड़े मनोज कुमार मिश्र का कहना है कि खेती-किसानी चौपट होने का असर सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा. बालू की नीलामी और उत्खनन का जो खेल इन दिनों चल रहा है, उससे साफ़ जाहिर है कि जनकेंद्रित विकास में सरकार की दिलचस्पी कम है. सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति मेवालाल चौधरी का ताल्लुक इसी क्षेत्र से है. दरअसल, उनकी पत्नी नीता चौधरी यहां से विधायक हैं. तारापुर अनुमंडल मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर गाजीपुर है. यहीं के मध्य विद्यालय में मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर उतरा था. इसी के पास एक जलमीनार है, जिसका निर्माण 2007 के आस-पास किया गया था. क्षेत्र के लोग आज भी इस जलमीनार से जलापूर्ति का इंतज़ार कर रहे हैं. दरअसल, इस जलमीनार में पानी चढ़ाने के लिए बोरिंग कम की गई और पंप क्षमता के अनुरूप नहीं लगाए गए. पंप से मोटर चलाकर सिर्फ़ छह जगहों पर पानी की आपूर्ति की जा रही है. जलमीनार में जल संग्रह करके पानी घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था कारगर नहीं हो सकी. मुख्यमंत्री के दौरे से पहले जब मुंगेर के जिला पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह तारापुर गए, तो स्थानीय लोगों ने उनसे अपनी नाराजगी का इजहार किया. इस पर उन्होंने यह कहकर छुटकारा पा लिया कि आप लोग मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा निकल जाने दीजिए, हम ख़ुद इस मामले को देखेंगे. दरअसल, ये सारे मामले ऐसे हैं, जो पूरी व्यवस्था और उसकी संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करते हैं. ■

एक डीजी साहब को पुलिस मुखिया की नई-नई कुर्सी मिली. सामान्य शिष्टाचारवश वह सपा के क़द्दावर नेता एवं लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव से मिलने गए.

यूपी के दबंग आईपीएस

अखिलेश राज में ख़ाकी का गिरता ज़मीर

पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस कर्मचारी तक, सभी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं. हो भी क्यों न, क्योंकि जब बड़े अफ़सर अपने स्वार्थ के लिए नेताओं की जी हुज़ूरी करेंगे, तो ऐसे में उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों का मनोबल कैसे ऊंचा रह सकता है? पुलिस अफ़सरों के बड़े-बड़े कारनामे पेश करती यह विशेष रिपोर्ट...

अजय कुमार

दृश्य एक : मथुरा के एसपी प्रदीप यादव का नोएडा भ्रमण. दिन भर व्यक्तिगत काम निपटाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होने के लिए देर शाम वह एक होटल के बार में पहुंचते हैं. क़रीब पौन घंटा बिताने के बाद एसपी साहब अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं. चंद पलों में ही हूटर बजाती यह गाड़ी हवा से बातें करते हुए दौड़ने लगती है. उनके साथ पंजाब पुलिस का एक अधिकारी भी था. कुछ ही देर में इस अनियंत्रित वाहन ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिसकी मौक़े पर ही मौत हो गई. वायरलेस पर मैसेज गूंजा. पुलिस ने एसपी साहब की कार रोक ली. साहब ने खिड़की का शीशा नीचे करके अपना परिचय दिया. परिचय सुनते ही पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए और एक अज्ञात वाहन चालक के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करके मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया.

दृश्य दो: प्रदेश की क़ानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए डीजी एसी शर्मा को हटाकर नागर साहब को डीजी बना दिया गया. नए डीजी ने अधीनस्थों को तलब किया. सभी लोग मुख्यालय के मीटिंग हॉल में इकट्ठे हो गए. डीजी साहब भी समय पर पहुंच गए, लेकिन उनका मन शायद कहीं और भटक रहा था. मीटिंग हॉल में लगे एलसीडी पर आईपीएल का मैच चल रहा था. साहब ने अधीनस्थों से बिगड़ती क़ानून व्यवस्था के सुधार के बारे में राय मांगी. अधीनस्थ सुझाव देने लगे, लेकिन साहब की नज़रें मैच पर टिकी थीं, इसलिए मीटिंग की गंभीरता पर फ़र्क़ पड़ रहा था. तभी वह ज़ोरदार आवाज़ में बोले, ओह...कैच छूट गया. कुछ ही देर में उनके मातहत भी उन्हीं के रंग में रंगकर मैच का आनंद उठाने लगे. बस, इस तरह मीटिंग निपट गई.

दृश्य तीन: सचिवालय के मीडिया सेंटर में नियमित प्रेस ब्रीफिंग. गृह सचिव आर एन उपाध्याय एवं आईजी क़ानून व्यवस्था राजकुमार विश्वकर्मा पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. एक पत्रकार का सवाल, सोनभद्र में एक पिता द्वारा अपने तीन छोटे बच्चों की हत्या और उसके बाद स्वयं आत्महत्या का कारण क्या था? आईजी विश्वकर्मा कुछ बोलते, इसके पहले ही गृह सचिव का ज़ोरदार ठहाका गूंजा और वह दार्शनिक अंदाज़ में बोले, महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो जन्मा है, उसकी मौत निश्चित है. अब मौत का क्या कारण बताया जाए. इस ठहाके को अखिलेश सरकार ने गंभीरता से लिया. दो घंटे के अंदर ही गृह सचिव को उनके पद से हटा दिया गया.

यह तीसरा दृश्य उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और पुलिस प्रशासन का हाल बयां करने के लिए काफ़ी है. नौकरशाहों की लालफ़ीताशाही से जहां जनता परेशान है, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अनुभव भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं है. उद्योगपतियों के सम्मेलन में नौकरशाही पर बात छिड़ी, तो अखिलेश यादव को अपनी आपबीती याद आ गई. वह बोले, मैंने एक काम करने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग के सचिव ने पांच महीने तक उसे लटकाए रखा. एक दिन जब मैंने थोड़ी सख्ती से कहा कि कल तक काम हो जाए, तो उन्होंने तीन दिनों के बाद मेरे सामने दो पेज की निगेटिव रिपोर्ट रख दी और बोले, यह काम होना मुश्किल है. मैंने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा, दो पेज की निगेटिव टिप्पणी में आपने पांच महीने लगा दिए, तो काम होने में तो पांच साल लग जाएंगे. फिर मैंने दूसरे सचिव को बुलाकर कहा, यह काम होना है. उन्होंने फाइल ली और दो लाइन की सकारात्मक टिप्पणी लिखकर अनुमोदन के लिए फाइल अगले ही दिन मुझे भेज दी. इसी के साथ अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से बोले, सचिवालय में बाबूराज चलता है.

आपस में लड़ते-झगड़ते पुलिस के बड़े अधिकारी अपराध की ज़मीनी हक़ीक़त समझने की कोशिश ही नहीं करते. कई अधिकारी तो यही मुग़ालता पाले हुए हैं कि हाईफाई तरीक़े से वे माउस घुमाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं. एक एडीजी तो अपने मातहतों को क़ानून व्यवस्था सुधारने के लिए थोक के भाव आदेशात्मक एसएमएस भेजकर ख़ूब नाम कमा रहे हैं. यह बात अलग है कि उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता. यह देखकर दु:ख होता है कि पुलिस का ज़मीर मर गया है, क्योंकि वह अपना काम ईमानदारी से नहीं करती. कुर्सी बचाने के लिए वह सत्तारूढ़ दल के नेताओं की परिक्रमा करती है. सत्ताधारी दल का झंडा लगी गाड़ी में झांकने की उसे हिम्मत नहीं पड़ती, चेक करना तो दूर की बात है. सच तो यह है कि पुलिस की इस कमज़ोरी का अपराधी ख़ूब फ़ायदा उठाते हैं. हाल में लखनऊ में एक बिल्डर का क़त्ल हो गया. हत्यारे उसका शव 250 किलोमीटर दूर फ़तेहपुर में फेंक आए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी. हत्यारे जब गिरफ्त में आए, तो उन्होंने क़बूला कि वे सपा का झंडा और हूटर लगे वाहन से शव को लेकर गए थे. रास्ते में एक-दो जगह चेकिंग में फंसे, तो गाड़ी का हूटर बजा दिया. यह एक बानगी भर है. दरअसल, अधिसंख्य पुलिस वाले नेताओं, बाहुबलियों एवं हनक-धमक वालों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके चलते हैं.

एक डीजी साहब को पुलिस मुखिया की नई-नई कुर्सी मिली. सामान्य शिष्टाचारवश वह सपा के क़द्दावर नेता एवं लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव से मिलने गए. शिवपाल ने कहा कि हमारी सरकार के लिए क़ानून व्यवस्था बेहद अहम मुद्दा है, आपको इस ओर पूरा ध्यान देना होगा. डीजी ने जी सर कहकर बिना समय गंवाए अपनी अलग तान छेड़ दी. बोले, सर, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूं. वहां आंवला बहुत अच्छा मिलता है. अगली बार जाऊंगा, तो लेता आऊंगा. शिवपाल उनका मुंह देखते रह गए. इन बड़े साहब के बारे में कहा जाता है कि बात कहीं की होती है और यह शुरू कहीं की कर देते हैं.

हाल में ही मथुरा से हटाए गए चर्चित एसपी साहब के सपा से अच्छे रिश्ते थे. सपा के प्रोफेसर साहब काफ़ी सोच-समझ कर उन्हें पंजाब से डेपुटेशन पर उत्तर प्रदेश लाए थे. उम्मीद थी कि बिरादरी के होने के कारण सरकार के वफ़ादार रहेंगे, लेकिन उनका नाम काम की बजाय सरकारी लूट-खसोट और प्रेम प्रसंग के कारण ज़्यादा सुर्ख़ियों में रहा. इसी प्रकार एसएसपी यशस्वी यादव को महाराष्ट्र से लाकर कानपुर नगर का एसएसपी बनाया गया, लेकिन उनका मंत्र शायद ईमानदारी की बजाय शॉर्टकट से सफलता हासिल करना है. ज़िले में क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एसएसपी साहब अपराधों पर रोक लगाने की बजाय खुद को कामयाब दिखाने के लिए तरह-तरह के गुडवर्क करते रहे. फ़र्ज़ी तरीक़े से बेगुनाहों को फंसाकर केस खोले जा रहे हैं. कभी सिम पकड़वाते हैं, तो कभी कॉलगर्ल्स बरामद कराते हैं. मीडिया के सामने अपनी ही पीठ थपथपाने वाले यशस्वी यादव की पत्नी कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की उपाध्यक्ष हैं. कानपुर में पुलिस और केडीए द्वारा अवैध निर्माण के नाम पर ख़ूब धन उगाही की जा रही है. सीलिंग कराकर डीलिंग का धंधा पूरे शबाब पर है.

अब पुलिस वालों के ज़मीर की बात की जाए. एक समय लखनऊ में एसएसपी के पद पर तैनात रहे बी बी बक्शी की अपने डीआईजी सुलखान सिंह से नहीं पटी. वजह थी कि डीआईजी उनके फ़ैसलों पर लगाम लगा देते थे. दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि डीआईजी ने एसएसपी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी, लेकिन ऊपर से प्रतिकूल प्रविष्टि तुरंत ख़ारिज कर दी गई. वर्तमान की बात की जाए, तो अखिलेश सरकार द्वारा कानपुर नगर में डीआईजी अमिताभ यश को काफ़ी सोच-समझ कर एसएसपी के पद पर तैनाती दी गई थी. वहां तैनात डीआईजी रेंज सुनील गुप्ता उनसे सीनियर थे. अमिताभ द्वारा की जा रही थानेदारों की तैनाती गुप्ता को रास नहीं आ रही थी. एसएसपी जिस थानेदार को तैनात करते, डीआईजी साहब पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर उसकी ख़ामियां गिना देते. अंतत: एसएसपी और डीआईजी दोनों को कानपुर से हटा दिया गया. ऐसा ही एक वाक़या लखनऊ से जुड़ा है. अखिलेश के सत्ता संभालते ही लखनऊ में डीआईजी आशुतोष पांडेय को एसएसपी बनाया गया. तत्कालीन एडीजी लॉ ऐंड ऑर्डर जगमोहन यादव की लखनऊ के एसएसपी पांडेय से ख़ूब ठनी. ग़ौरतलब है कि थानेदारों की तैनाती को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हुआ था. इसी बीच पांडेय का आईजी स्तर पर प्रमोशन हो गया, लेकिन उन्होंने लखनऊ का एसएसपी बने रहना ही ज़्यादा बेहतर समझा. जगमोहन यादव और आशुतोष पांडेय की लड़ाई का अंत यह रहा कि पहले तो आशुतोष को उनके पद से चलता कर दिया गया और उसके कुछ महीने बाद जगमोहन यादव को भी एडीजी लॉ ऐंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया.

वैसे, जगमोहन की विदाई का कारण तत्कालीन डीजीपी ए सी शर्मा ज़्यादा थे. डीजीपी शर्मा के बारे में कहा जाता था कि वह ऑफिस में ही डीलिंग करते थे. बिल्कुल ताज़ा मामला आगरा और मथुरा का है. मथुरा के एसपी का दिल एक महिला दारोग़ा पर आ गया. एसपी साहब डीआईजी आगरा की मातहती में थे. डीआईजी पहले से ही इस महिला दारोग़ा पर फ़िदा थे. प्रेमिका को लेकर दोनों में ख़ूब ठनी. ऊपर तक चर्चा हुई. दोनों दबंग थे. ऊपर से डांट-डपट हुई, लेकिन दोनों को नहीं सुधरना था, सो नहीं सुधरे. पानी जब ऊपर तक आ गया, तो मजबूरी में दोनों को हटाना पड़ा. मजबूरी यह थी कि दोनों ने सत्ता शिखर के दो बड़ों का अलग-अलग दामन थाम रखा था. ■

इस राज में क़ानून-व्यवस्था ध्वस्त : स्वामी प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी सरकार को पूरी तरह से फ्लॉप क़रार दिया है. उन्होंने कहा कि सूबे की क़ानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है. बड़े पैमाने पर चोरी, डकैती और ख़ूनख़राबे से अराजकता का माहौल है. शासन-प्रशासन पंगु हो गया है. जनता भयभीत है. मौर्य ने सपा सरकार को क़ानून व्यवस्था सहित सभी मामलों में अब तक की सबसे असफल सरकार क़रार दिया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तुलना एक बेचारे से की, जिसके कई आक़ा हैं और वही पर्दे के पीछे से सरकार चलाते हैं. जनता की नाराज़गी बेचारे सीएम को झेलनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था को वही मुख्यमंत्री प्रभावित कर सकता है, जो अफ़सरों की मनमानी पर लगाम लगा सके. सत्तारूढ़ दल को अपने ही दल के क़ानून तोड़ने वाले नेताओं के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. मायावती सरकार की ख़ूबियां गिनाते हुए मौर्य ने कहा कि बहन जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, अपने ही घर से अपनी पार्टी के उस सांसद को गिरफ्तार करा दिया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी और वह फ़रार था, जबकि सपा सरकार अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अगर अपराध में लिप्त पाती है, तो उन्हें जेल भेजने की बजाय उनकी ताजपोशी कर दी जाती है. गोंडा में पशु तस्करी के आरोपी नेता को दंडित करने की बजाय खुला छोड़ दिया गया. अब वह मंत्री बना बैठा है, जबकि पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया. सपा सरकार अपने ही बोझ तले दबी जा रही है. अखिलेश यादव प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव क़ायम रखने में भी असफल रहे हैं. वह कहते हैं कि बहन जी के पांच सालों के शासनकाल में एक-दो छोटी-मोटी वारदातों को छोड़कर पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव क़ायम रहा, जबकि अखिलेश के डेढ़ वर्ष के शासन में ही तीन दर्जन से अधिक सांप्रदायिक दंगों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने बीते 27 मई को राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर वर्तमान सरकार को बर्ख़ास्त करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है.■

पुलिस का मनोबल तोड़ने की राजनीतिक साज़िश

राजनेता पुलिस का मनोबल किस तरह से तोड़ते हैं, इसकी बानगी कुछ दिनों पूर्व आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद ख़ालिद की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद देखने को मिली. सरकार ने अपना वोट बैंक मज़बूत करने के लिए कई पुलिसवालों के ख़िलाफ़ अनाप-शनाप मुक़दमे ठोंक दिए. सीरियल ब्लास्ट के आरोपी ख़ालिद की मौत के बाद मचे बवाल को शांत करने के लिए एक मुक़दमा रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह के ख़िलाफ़ भी दर्ज कर दिया गया, जो ख़ालिद की मौत के समय रुड़की के रामकृष्ण ट्रस्ट मिशन में व्याख्यान दे रहे थे. अपने ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज होने की बात सुनकर वह ग़ुस्सा हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह सब सरकार के पैंतरे हैं. ख़ालिद की गिरफ्तारी मेरे ही कार्यकाल में हुई थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह आतंकवादी था और रहेगा. अब उसके परिवार को अखिलेश सरकार छह लाख रुपये की मदद देकर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है?

इनका कहना है...

“आज आईपीएस अफ़सर मलाईदार पोस्टिंग के लिए सत्ताधारी दल के लोगों की गणेश परिक्रमा करते हैं और सच यही है कि जब कमाऊ ज़िला मिल जाता है, तो कुर्सी बचाने के लिए जायज़-नाजायज़ सब काम करते हैं. नतीजतन, अपराध लगातार बढ़ते जाते हैं.

-श्रीराम अरुण, पूर्व डीजीपी”

“एडीजी क़ानून व्यवस्था ने एक ज़िले के कप्तान को निर्देश दिया कि वह पशुओं की तस्करी करने वालों की धरपकड़ करें. एसपी ने पशु तस्करों के ख़िलाफ़ अभियान चलाया, तो सत्ताधारी दल के एक नेता फंदे में आ गए. नेताजी ने पकड़े गए पशु तस्करों को छोड़ने के लिए एसपी को घूस देने की पेशकश की. एडीजी ने मीडिया में इस मामले को उछाल कर ख़ूब वाहवाही बटोरी, लेकिन जब संबंधित एसपी को सरकार ने हटाने का निर्णय लिया, तो एडीजी साहब उनकी मदद के लिए सामने नहीं आए. ऐसे में सवाल यह उठता है कि कौन मातहत अपने अफ़सर की बात मानेगा?

-एक डीजी की प्रतिक्रिया”

“आज के अफ़सर नैतिकता भूल गए हैं. सही निर्णय लें, तो उनके अधीनस्थ भी डरते रहेंगे. अफ़सर जैसा आचरण करेंगे, नीचे वाले उसी का अनुसरण करेंगे.

-के के बंसल, पूर्व डीजीपी”

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिजोफ्रेनिया को युवाओं का सबसे बड़ी क्षमतानाशक यानी डिसएब्लर बताया है. विश्व की 10 सबसे बड़ी अक्षम बनाने वाली बीमारियों में सिजोफ्रेनिया को भी शामिल किया गया है.

सिजोफ्रेनिया
जब ख़ुद की ही ख़बर न हो

सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति अपने होशोहवास खो बैठता है. ऐसे में वह कल्पना और यथार्थ का फ़र्क़ ही नहीं समझ पाता. दरअसल, वह अपनी कल्पनाओं में इतना आगे निकल जाता है कि उसे कल्पना ही सच लगने लगती है. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस बीमारी की चपेट में रचनात्मक लोग ज़्यादा आते हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने जमाने की जानी-मानी अभिनेत्री नलिनी जयवंत, परवीन बॉबी, अभिनेता राजकिरण, उर्दू के जाने-माने शायर मजाज लखनवी एवं मीर तकी मीर भी इस बीमारी से ग्रसित थे. कैसे होते हैं सिजोफ्रेनिया के मरीज और कैसे करनी चाहिए उनकी देखभाल, जानिए मनोचिकित्सक से...

प्रियंका तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

चर्चित निर्देशक अपर्णा सेन ने 15 पार्क एवेन्यू नामक एक फिल्म बनाई थी, जिसमें मीठ्ठी (कोंकणा सेन) इस पते की तलाश करती है. मीठ्ठी को यह विश्वास है कि इस पते पर वह अपने पति एवं पांच बच्चों के साथ रहती है. वह अपनी कल्पना में इतनी गहराई तक उतर चुकी है कि उसे अपने काल्पनिक पति एवं बच्चों के अलावा, और कुछ भी दिखाई नहीं देता. वह अपनी कल्पना में न जाने क्या-क्या कहानियां गढ़ लेती है. वह अपने आस-पास जो भी देखती और सुनती है, उसे ख़ुद और अपने काल्पनिक पति से रिलेट कर लेती है. दरअसल, इस फिल्म में मीठ्ठी एक बीमारी से जूझ रही है, जिसे सिजोफ्रेनिया या खंडित मानसिकता कहते हैं. इस बीमारी में मरीज़ का दिमाग़ी संतुलन बिगड़ जाता है. कई बार लंबे समय तक इस गंभीर मानसिक त्रासदी से गुजरने के बाद इस रोग की चरम परिणति मरीज़ द्वारा हत्या या आत्महत्या के रूप में भी देखी गई है. हालांकि इस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे देश में इस रोग के प्रति जागरूकता न होने के कारण मरीज़ को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता. हमारे देश में इस बीमारी को लेकर कई तरह के अंधविश्वास भी देखे गए हैं. ख़ास तौर पर गांवों में लोग इस बीमारी को भूत-प्रेत का प्रकोप समझते हैं और इलाज के लिए तंत्र-मंत्र का सहारा लेकर तांत्रिकों या ढोंगी बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं. इससे मरीज़ की स्थिति बज़ाय सुधरने के और भी बिगड़ जाती है.

बढ़ते शहरीकरण, टूटते संयुक्त परिवार, करियर का दबाव, पैसा कमाने की होड़ और घरेलू ज़िम्मेदारियों के कारण कई तरह की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. इससे अकेलापन, उदासी एवं तनाव जैसे मानसिक रोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. मानसिक रोगों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है. पहली श्रेणी में वह परिस्थिति आती है, जिसमें व्यक्ति यथार्थ और कल्पना का अंतर समझता है और दूसरी श्रेणी में सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी आती है, जिसमें व्यक्ति यथार्थ और कल्पना के बीच का फ़र्क़ भूल जाता है. इस बीमारी के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आने वाले समय में मानसिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे. एक सर्वे के मुताबिक, पूरी दुनिया में लगभग 2.4 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं. सामान्य तौर पर 15 से 35 वर्ष के लोग इससे ग्रसित होते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आने वाले समय में इस रोग से संबंधित रोगियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. यह बीमारी पुरुष और महिला, दोनों में समान रूप से होती है. एक सर्वे के मुताबिक, 70 प्रतिशत लोग इस बीमारी से इलाज के बाद सामान्य जीवन जीते हुए देखे गए हैं, 20 प्रतिशत लोगों में यह बीमारी काफी लंबी देखी गई है, जिन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत थी, वहीं दूसरी ओर 10 प्रतिशत लोगों ने इस बीमारी में मौत को गले लगा लिया. इनमें अधिकतर युवा एवं प्रौढ़ पुरुष थे.

क्या है सिजोफ्रेनिया

इसमें रोगी सच और कल्पना के बीच का अंतर नहीं समझ पाता. यह अत्यंत गंभीर किस्म की मानसिक बीमारी है. रोगी भारी मानसिक पीड़ा से गुजरता है. वह अपने ही विचारों में खोया रहता है. उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है और न ही उसे लोगों से मिलना-जुलना अच्छा लगता है. हर व्यक्ति को वह शक़ की निगाह से देखता है. जैसे उसके आस-पास के लोग उसके ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रहे हों. उसे अजीबोग़रीब डरावनी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, डरावनी परछाइयां दिखाई पड़ती हैं. इन सबसे घबरा कर वह हिंसा और आत्महत्या जैसे क़दम तक उठाने की कोशिश करता है. रोगी धीरे-धीरे स्वयं के प्रति उदासीन होता जाता है. यहां तक कि वह दिनचर्या के काम भी ठीक से नहीं कर पाता है. सामान्य किस्म के सिजोफ्रेनिया के मरीज़ गुमसुम और चुपचाप रहते हैं, कई बार तो उनकी हालत बच्चों जैसी भी हो जाती है, लेकिन गंभीर किस्म के सिजोफ्रेनिया के रोगी हिंसक और विद्रोही हो जाते हैं. कभी-कभी वे न केवल ख़ुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरनाक हो जाते हैं. ऐसे में वे ख़ुद को नुक़सान पहुंचाने या आत्महत्या जैसे प्रयास भी कर सकते हैं.

क्या हैं कारण

कुछ सालों पहले तक इस बीमारी का वास्तविक कारण पता नहीं था, लेकिन मानव मस्तिष्क और व्यवहार पर किए गए आधुनिक शोध से पता चलता है कि यह बीमारी मस्तिष्क की रासायनिक संरचना एवं कार्य-व्यवहार में आए ख़ास प्रकार के बदलाव के कारण होती है. यही नहीं, शोध यह भी कहते हैं कि मस्तिष्क में पाए जाने वाले स्नायु रसायन (न्यूरोकेमिकल्स)-डोपेमाइन और सेरोटोना के स्तर में परिवर्तन की वजह से भी यह बीमारी होती है. यह बीमारी तनाव के कारण नहीं होती है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर आनुवांशिक तौर पर यह बीमारी होने की आशंका होती है, उसमें तनाव के कारण ही यह उभर कर बाहर आ जाती है. कई बार ऐसी कोई घटना, जिससे व्यक्ति को शॉक लगे, उस परिस्थिति में भी वह सिजोफ्रेनिया की चपेट में आ सकता है. मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अविवाहित पुरुष नौकरी से संबंधित परेशानियों, दोस्तों एवं परिवार द्वारा नीचा दिखाने पर हीनभावना का शिकार होने के कारण भी कई बार सिजोफ्रेनिया की चपेट में आ जाते हैं.

किन्हें होती है यह बीमारी

माता-पिता में किसी एक को यह बीमारी होने पर उनके बच्चे को यह बीमारी होने की आशंका 15 से 20 प्रतिशत तक होती है, जबकि माता-पिता दोनों को यह बीमारी होने पर बच्चे को यह बीमारी होने की आशंका 60 प्रतिशत तक हो सकती है. जुड़वा बच्चों में से एक को यह बीमारी होने पर दूसरे बच्चे को भी यह बीमारी होने की आशंका शत-प्रतिशत होती है. सिजोफ्रेनिया की बीमारी आम तौर पर युवावस्था में ख़ास तौर पर 15-16 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है. कुछ लोगों में यह बीमारी ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और धीरे-धीरे गंभीर रूप धारण कर लेती है.

रचनात्मक लोग मानसिक बीमारी की चपेट में ज़्यादा होते हैं

नए अध्ययन बताते हैं कि रचनात्मक पेशे से जुड़े लोग आम लोगों की तुलना में मानसिक बीमारियों की चपेट में ज़्यादा आते हैं. रचनात्मकता और सिजोफ्रेनिया के बीच गहरा संबंध है. कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट केशोधकर्ताओं ने 10 लाख, 20 हज़ार मरीजों और उनके रिश्तेदारों पर शोध किया. इस शोध में पता चला कि कई मानसिक बीमारियां, जैसे बायपोलर डिसऑर्डर उन लोगों के पूरे समूह में अधिक फैली हुई है, जो कलात्मक या वैज्ञानिक पेशे से ताल्लुक रखते हैं. इनमें नृत्यांगनाएं, शोधकर्ता, शायर, फोटोग्राफर एवं लेखक शामिल हैं. शोध के मुताबिक, लेखकों को सिजोफ्रेनिया, अवसाद, बेचैनी और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या अधिक होती है. सामान्य लोगों के मुक़ाबले ऐसे लेखकों में आत्महत्या करने की आशंका भी 50 फ़ीसद ज़्यादा रहती है. इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि सिजोफ्रेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर और एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित मरीजों के क़रीबी रिश्तेदारों में रचनात्मक पेशे से जुड़े लोग अधिक होते हैं. ■

क्या है इलाज

जब इस बीमारी को लेकर किसी तरह की कोई जागरूकता नहीं थी, तब इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पागल क़रार दिया जाता था. उसे सालों तक पागलखाने या मानसिक अस्पताल में रखा जाता था. जैसे-जैसे चिकित्सा विज्ञान में तरक्की हो रही है, वैसे-वैसे इसके इलाज के तरीक़ों में निरंतर सुधार हो रहा है. इस बीमारी के इलाज से पहले किसी मनोचिकित्सक से इसकी अच्छी तरह से पहचान आवश्यक है. इसके लिए मनोवैज्ञानिक जांच के अलावा, परिवार के इतिहास की जानकारी भी ली जाती है. इसके बाद बीमारी के कारण का पता लगाया जाता है. दिल्ली साइकिएट्रिक सेंटर के डॉ. सुनील मित्तल कहते हैं कि आज इस बीमारी के सफल इलाज के लिए क्लोजपीन एवं रेसपेरिडॉन जैसी दवाइयां और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी (ईसीटी) उपलब्ध हैं. ग़ौरतलब है कि इन दिनों इलाज के लिए क्लोजपीन एवं रेसपेरिडॉन का ही सबसे अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं सिजोफ्रेनिया के मरीजों को उपचार के बाद समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं सामान्य गतिविधियों के योग्य बनाने के लिए चिकित्सकों के साथ-साथ परिवार और समाज का सामूहिक प्रयास भी आवश्यक है. इसके अलावा, इस बीमारी के इलाज के तौर पर दवाइयों से उपचार के साथ ही फैमिली थेरेपी, पर्सनल साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का सहारा भी लिया जाता है. हालांकि कुछ रोगियों में इलाज के लिए ईसीटी (इलेक्ट्रो थेरेपी, बिजली के ज़रिए उपचार) का भी सहारा लिया जाता है. गंभीर किस्म के वैसे रोगी, जिन पर दवा असर नहीं करती है, उनके लिए ईसीटी अत्यंत सुरक्षित और प्रभावकारी होती है. ख़ासकर, हिंसक व्यवहार वाले रोगियों पर इसका तुरंत असर होता है और उनकी हिंसक प्रवृत्ति तुरंत बंद हो जाती है. डॉक्टर सुनील कहते हैं कि हालांकि ईसीटी को लेकर कई तरह की ग़लत धारणाएं हैं जैसे कि ईसीटी के बाद रोगी पर दवा असर नहीं करती है, ईसीटी से रोगी को झटका लगता है, एक बार ईसीटी लगने पर बार-बार ईसीटी देनी पड़ती है आदि. लेकिन यह महज भ्रम है, इससे रोगी को बिल्कुल नुक़सान नहीं होता है.

डॉ. सुनील कहते हैं कि बीमारी के दौरान रोगी वर्षों तक परिवार एवं समाज से पूरी तरह कट जाते हैं. वे जब इलाज के बाद सामान्य स्थिति में वापस आते हैं, तब ख़ुद को मानसिक तौर पर उसी अवस्था में पाते हैं, जिसमें रोग के शुरू होने से पहले थे. रोग के बीच की अवधि उनके जेहन से निकल जाती है और इस बीच समाज एवं परिवार काफ़ी आगे निकल चुका होता है. इस लिहाज़ से उन मरीज़ों का पुनर्वास बहुत ही मेहनत एवं धैर्य के साथ करना पड़ता है, जिसमें चिकित्सकों के साथ-साथ परिवार एवं समाज का सहयोग आवश्यक है. सिजोफ्रेनिया के इलाज और पुनर्वास में फैमिली थेरेपी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. इसके लिए परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है. उन्हें यह बताया जाता है कि वे रोगी के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कैसी भावना प्रकट करेंगे और उसके काम-काज में किस तरह से मदद करेंगे. आम तौर पर सिजोफ्रेनिया के रोगी को अस्पताल में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन गंभीर किस्म के रोगियों को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए किसी मानसिक अस्पताल में रखना पड़ सकता है. यहां उन्हें प्रशिक्षित चिकित्सक और नर्स की देखरेख में रखा जाता है. उनका बिहेवियर थेरेपी चार्ट बनाया जाता है और इसमें उनके सुधार को नोट किया जाता है. रोगी को अपना काम ख़ुद करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है.

सिजोफ्रेनिया मानसिक बीमारी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिजोफ्रेनिया को युवाओं का सबसे बड़ी क्षमतानाशक यानी डिसएब्लर बताया है. विश्व की 10 सबसे बड़ी अक्षम बनाने वाली बीमारियों में सिजोफ्रेनिया को भी शामिल किया गया है. यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जो न सिर्फ़ रोगी की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि उसके परिजनों के लिए भी एक सिरदर्द बन जाती है. यह ज़्यादातर युवाओं को उस वक्त प्रभावित करती है, जब उनकी तरक्की और कार्य करने की क्षमता शिखर पर होती है. अक्सर सिजोफ्रेनिया को लोग युवावस्था की स्वाभाविक समस्या या युवाओं की सनक मानने की भूल कर बैठते हैं. ■

डॉ. सुनील मित्तल
निदेशक, दिल्ली साइकिएट्रिक सेंटर

> डॉ. सुनील मित्तल कहते हैं कि बीमारी के दौरान रोगी वर्षों तक परिवार एवं समाज से पूरी तरह कट जाते हैं. वे जब इलाज के बाद सामान्य स्थिति में वापस आते हैं, तब खुद को मानसिक तौर पर उसी अवस्था में पाते हैं, जिसमें रोग के शुरू होने से पहले थे. रोग के बीच की अवधि उनके जेहन से निकल जाती है और इस बीच समाज एवं परिवार काफी आगे निकल चुका होता है. इस लिहाज से उन मरीजों का पुनर्वास बहुत ही मेहनत एवं धैर्य के साथ करना पड़ता है, जिसमें चिकित्सकों के साथ-साथ परिवार एवं समाज का सहयोग आवश्यक है. सिजोफ्रेनिया के इलाज और पुनर्वास में फैमिली थेरेपी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है.

किसानों में भी छोटे किसान, बड़े किसान, मज़दूर आदि भेद पैदा करना, जिससे ग्रामीण समाज इकट्ठा न हो, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती रही हैं और इसमें राजनीतिक दल जाने-अनजाने साथ देते रहे हैं.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

समस्या का समाधान खोजने की ज़रूरत

छत्तीसगढ़ नरसंहार और आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी एवं फिक्सिंग की ख़बरें जनसामान्य में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आख़िर कौन से क़दम उठाए जाने चाहिए, यही बता रही है यह विचारोत्तेजक टिप्पणी.

पिछले हफ्ते दो प्रमुख घटनाएं अख़बारों की सुर्खियां बनीं. पहली, छत्तीसगढ़ में नरसंहार की घटना. सलवा जुडूम पर तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए और इसे ख़त्म किया जाना चाहिए. कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य प्रायोजित काउंटर वायलेंस (जवाबी हिंसा), जिसे नन स्टेट ऐक्टर्स द्वारा अंजाम दिया जा रहा था, के ख़िलाफ़ गंभीर टिप्पणी की थी. उसके बाद सलवा जुडूम का नाम बदल गया, लेकिन हिंसक गतिविधियां फिर भी जारी रहीं. इसे जिस शख्स ने शुरू किया था, वह मारा गया. पूरा का पूरा नक्सलवादी आंदोलन सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है. माओवादियों की हिंसा को प्रति-हिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता. आप पुलिस और सेना की कार्रवाई को उचित समझ सकते हैं, लेकिन काउंटर वायलेंस के लिए निश्चित रूप से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई स्थान नहीं है. केंद्र सरकार ने इस मामले में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई और न अब गंभीर नज़र आती है. क्यों? मुझे नहीं पता.

होना तो यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तलब करते और इस मामले को अपने हाथ में लेते. मुख्यमंत्री अगर सहमत नहीं हैं, तो छत्तीसगढ़ में अस्थायी रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह का अमानवीय व्यवहार तुरंत बंद कर देना चाहिए और साथ ही माओवादियों के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिए. दरअसल, असली मुद्दा आदिवासियों का उनके निवास स्थान से विस्थापन का है. आदिवासी क्षेत्रों में कंपनियां खनन अधिकारों का आनंद उठा रही हैं. यह जगह नक्सलवाद या माओवाद के लिए मुफीद बन गई है. पूर्व गृहमंत्री चिदंबरम समझते थे कि इस समस्या को पुलिस और सख्त कार्रवाई से ख़त्म किया जा सकता है. वर्तमान गृहमंत्री अगंभीर व्यक्ति हैं. इस नरसंहार के वक्त वह अमेरिका में थे और बजाय तुरंत लौटने के उन्होंने अपनी यात्रा का समय और बढ़ा दिया. वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने कुछ सैनिकों एवं नागरिकों की मौत के बाद अपनी विदेश यात्रा का समय तुरंत कम कर दिया. दरअसल, हम इस मामले को बहुत ही हल्के ढंग से ले रहे हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री को यह मामला अपने हाथ में लेना चाहिए और सलवा जुडूम हमेशा के लिए ख़त्म किया जाना चाहिए.

दूसरा मामला है आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग सिंडिकेट का. मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि आईपीएल तुरंत रोका जाना चाहिए और इसे बंद किया जाना चाहिए. बीसीसीआई अगर खुद को बचाना चाहता है, तो वह आईपीएल से दूर रहे. आईपीएल को ललित मोदी ने शुरू कराया था, यह तर्क देकर कि बीसीसीआई को नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाए. आईपीएल क्रिकेट के लिए नहीं है, यह विदेश में खेलने या एक बेहतर घरेलू क्रिकेट टीम तैयार करने के लिए नहीं है, यह क्रिकेटरों के लिए भी नहीं है, बल्कि यह एक इंटर कॉरपोरेट तमाशा है. सट्टेबाजी और फिक्सिंग इसमें अंतर्निहित हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है. देर रात की पार्टियां, फैशन शो, चीयर लीडर्स, ये सब मिलकर क्रिकेट के लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हैं. सामान्य टेस्ट क्रिकेट या एक दिवसीय मैच से पहले देर रात की पार्टियों के लिए बीसीसीआई खिलाड़ियों को मना करती है और अनुशासनहीनता की अनुमति कभी नहीं देती, लेकिन आईपीएल में यह सब जायज बना दिया गया है. यह भारतीय क्रिकेट के लिए सोचने का वक्त है और यही वह वक्त है, जबकि

> **बीसीसीआई अगर खुद को बचाना चाहता है, तो वह आईपीएल से दूर रहे. आईपीएल को ललित मोदी ने शुरू कराया था, यह तर्क देकर कि बीसीसीआई को नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाए. आईपीएल क्रिकेट के लिए नहीं है, यह विदेश में खेलने या एक बेहतर घरेलू क्रिकेट टीम तैयार करने के लिए नहीं है, यह क्रिकेटरों के लिए भी नहीं है, बल्कि यह एक इंटर कॉरपोरेट तमाशा है.**

आईपीएल को तुरंत बंद कर दिया जाए. बीसीसीआई को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के संचालन के अपने मूल कार्य में लग जाना चाहिए. दुर्भाग्यवश, वरिष्ठ राजनेता जो बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं, ललित मोदी के जाल में फंस गए हैं. अब वे कह रहे हैं कि श्रीनिवासन को पद से हट जाना चाहिए. श्रीनिवासन पद से हटते हैं या नहीं, यह प्रासंगिक नहीं है और यह मुद्दा भी नहीं है. मुद्दा यह है कि आईपीएल की भूमिका क्या है? बीसीसीआई कैसे आईपीएल चला सकती है, जो एक सर्कस की तरह है, एक तमाशा है. अब केवल एक ही उपाय है कि आईपीएल को बंद कर दिया जाए. कई वरिष्ठ राजनेता बीसीसीआई में हैं.

दरअसल, पूरी कहानी राजस्थान से शुरू होती है, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने क़रीबी दोस्त ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट में शामिल किया था. ललित मोदी के पास क्रिकेट को देने के लिए कुछ नहीं है. वह केवल मुख्यमंत्री के निजी दोस्त थे. एक अध्यादेश के जरिए मुख्यमंत्री ने यह अनिवार्य कर दिया कि स्थानीय लोगों को राजस्थान क्रिकेट चलाना चाहिए. स्थानीय लोगों की परिभाषा क्या है? राजस्थान के किसी भी जिले में जिसकी संपत्ति है, वह स्थानीय व्यक्ति है. इस तरह से ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट में लाया गया. अगर वसुंधरा राजे फिर से सत्ता में आती हैं, तो मैं नहीं जानता कि क्या वह दोबारा ऐसा ही करेंगी, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री को राजस्थान क्रिकेट की भलाई के लिए तत्काल क़दम उठाने चाहिए. अभी केंद्रीय मंत्री सी पी जोशी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे हैं. उन्हें क्रिकेट के बारे में क्या पता है? सच तो यह है कि भारतीय क्रिकेट सड़ चुका है, इसकी सफाई की ज़रूरत है और यह आईपीएल से ही शुरू होनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

...ताकि किसान रहें आत्मनिर्भर

ठाकुरदास बंग
feedback@chauthiduniya.com

हरित क्रांति के दौरान पिछले दस वर्षों में अनाज की विपुलता निर्मित हुई, तब स्वाभाविक रूप से ही मंडियों में अनाज के दाम गिरने लगे. ऐसी परिस्थिति में शासन ने दामों को गिरने दिया और किसान बर्बाद हो गए. कभी-कभी सरकार ने काग़ज़ पर इन चीज़ों का आधार मूल्य भी ज़ाहिर किया, जो कि लागत ख़र्च की तुलना में काफी कम था. इस कम क़ीमत पर भी किसान का अनाज ख़रीदना सरकार ने अपना दायित्व नहीं माना. अत: घोषित सरकारी क़ीमत काग़ज़ पर रही और बाज़ार द्वारा किसानों से लूट जारी रही. विदेशों में अनाज या कच्चा माल भेजकर किसान अपना लागत ख़र्च प्राप्त कर सकता था. इससे राष्ट्र को न सिर्फ़ विदेशी मुद्रा मिलती, बल्कि किसान से लूट भी बंद हो जाती. यही नहीं, अनाज का स्टॉक राष्ट्र में कम हो जाने से यहां भी उसकी क़ीमतें बाज़ारों में ऊंची हो जातीं और किसान की बर्बादी रुकती, लेकिन ऐसे समय में विदेशों में वस्तुएं भेजने पर पाबंदियां लगाई गईं. प्याज, कपास और मूंगफली का विदेशों में निर्यात रोक दिया गया. जैसे, मूंगफली का उत्पादन ख़र्च एक किलो के लिए कुछ वर्षों पूर्व चार रुपये तीस पैसे आता था, लेकिन भारतीय बाज़ार में भाव था दो रुपये आठ पैसे. उस समय यूरोप में मूंगफली निर्यात करके साढ़े आठ रुपये किलो की दर से बेची जा सकती थी. इससे 250 करोड़ रुपये किसानों को मिलते और इतनी विदेशी मुद्रा राष्ट्र को मिलती. ज्वार का उत्पादन ख़र्च क़रीब एक किलो के पीछे दो रुपये पड़ता है. यह ज्वार मध्य पूर्व में भेजी जाती, तो सवा दो रुपये किलो की दर से बिक सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करने दिया जाता है.

इसलिए अभाव की परिस्थिति में लेवी लगाकर किसानों से लूट करना और विपुलता की हालत में बाज़ारों में उपज कम दाम में नीलाम होने देना, ऐसी दो-रंगी नीति शासन की रही. महाराष्ट्र में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ ने ज्वार का लागत ख़र्च किसानों से आंकड़े प्राप्त करके पौने दो सौ रुपये प्रति कुंतल घोषित किया. महाराष्ट्र सरकार ने ज्वार का आधार मूल्य 122 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया. अक्टूबर 1982 में ज्वार पैदा हुई, तब सरकार ने घोषित मूल्य के अनुसार ज्वार की ख़रीदी नहीं की. बाज़ार में 80-90 रुपये प्रति कुंतल के भाव से अधिकांश किसानों को अपनी ज्वार बेचनी पड़ी और लूट होने देनी पड़ी. यदि किसान ने कच्चे माल को पक्का माल बनाया, तो भी सरकार पक्के माल को भी लागत ख़र्च जितनी क़ीमत किसान को नहीं मिलने देती है. जैसे महाराष्ट्र में किसानों ने सहकारी चीनी मिलें खड़ी कीं. गन्ने का लागत ख़र्च 288 रुपये टन था, जबकि किसान को मिले 142 रुपये.

किसानों को लगा कि महंगी चीनी बेचकर इस नुक़सान की पूर्ति हम कर लेंगे. सरकार ने चीनी पर 65 प्रतिशत लेवी लगाकर उसे 4 रुपये प्रति किलो उत्पादन ख़र्च के आधार पर नहीं बेचने दिया. नतीजतन, किसान को 2 रुपये 12 पैसे के भाव से चीनी लेवी में देनी पड़ी और यह सब हुआ ग़रीबों के नाम पर! देहातों में कितने प्रतिशत ग़रीब चीनी ख़रीद सकते हैं?

ये नग्न नीतियां ढंक जाएं और भ्रम पैदा हो, इसलिए सरकार कई तरीक़े काम में लाती है. जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियां सब्सिडी पर देना, ग़रीबों के लिए झोपड़ियां बनाना, गांवों में पाठशालाएं खोलकर कल्याणकारी राज्य का सबूत देना, दवाखाने खोलना, सड़कें बनाना, अकाल के समय राहत कार्य आदि. ग्रामीणों के सामने इस प्रकार का कोई न कोई खिलौना रखना, जिससे कि उनका मन अन्याय के विरुद्ध बग़ावत न कर बैठे, ऐसी नीतियां पिछले 35 सालों में अपनाई गई हैं. किसानों को यह खिलौना देने की बजाय उसका हक यानी लागत ख़र्च पर आधारित भाव क्यों नहीं मिलने दिया जाता? किसानों में भी छोटे किसान, बड़े किसान, मज़दूर आदि भेद पैदा करना, जिससे ग्रामीण समाज इकट्ठा न हो, ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती रही हैं और इसमें राजनीतिक दल जाने-अनजाने साथ देते रहे हैं. ग्रामीणों को इन सारी चालों और हरकतों को समझना चाहिए. ग्रामवासी अकाल का सामना क्यों नहीं कर सकते, सब लोग मिलकर अपने लिए शाला-दवाखाना क्यों नहीं बना सकते आदि तथ्यों की बुनियादी छानबीन की जानी चाहिए.

कारखाने में भी मंदी के कारण कभी-कभी नुक़सान होता है, वहां भी आग लगती है या मज़दूर हड़ताल पर चले जाते हैं, लेकिन पूर्वानुभव के जरिए इतना-इतना नुक़सान होने वाला है, यह जानकर पक्के माल का लागत ख़र्च निकालते समय इसे गिना जाता है और इसके अनुसार ही पक्के माल की क़ीमत तय की जाती है. अत: नुक़सान के दिनों में इस लाभ-हानि फंड में से रकम निकाल कर खराब दिन बिताए जाते हैं. दस वर्षों में कितनी बार अकाल आएगा, यह अनुमान कृषि में भी कई दशकों के अनुभव से गणित के आधार पर निकाला जा सकता है. इसके लिए प्रति वर्ष नुक़सान फंड बनाना पड़ेगा, यह सोचकर किसान इसे लागत ख़र्च में उद्योग की भांति क्यों न जोड़ें? वैसे ही शिक्षा, सामान्य चिकित्सा आदि का सामान्य ख़र्च जोड़कर किसान एवं मज़दूर को उतनी रोजी क्यों न मिले? प्राथमिक आवश्यकताओं पर आधारित इस पारिश्रमिक की दर को कृषि वस्तु का लागत ख़र्च निकालते समय क्यों न जोड़ा जाए? ऐसा करने से सरकार के अनुदान या मेहरबानी पर निर्भर रहने की ज़रूरत ग्रामीणों को नहीं पड़ेगी. ■

पाठकों की दुनिया

मानव त्रासदी का सजीव चित्रण

फ़िरदौस ख़ान का आलेख-ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, एक मानव त्रासदी का सजीव चित्रण है. मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई, 1987 और मलियाना में 23 मई, 1987 को इंसानियत के दुश्मनों ने जिस प्रकार हैवानियत का नंगा नाच किया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था. इन्हें सरकार की नाकामी या उसके द्वारा प्रायोजित दंगे कहें, तो गलत न होगा. इन दंगों में पीएसी ने जो रोल अदा किया और निहत्थे-बेक़सूर मुसलमानों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया, उसने अंग्रेजों के राज की याद ताज़ा कर दी. यह लेख पढ़ने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात में आख़िर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे क्यों कराए जाते हैं और अधिकतर मुसलमान ही क्यों दंगों के शिकार होते हैं? उत्तर स्पष्ट है कि चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार, सभी की एक ही नीति है कि मुसलमानों को किसी भी तरह दहशत में रखा जाए, ताकि वे अपने हक़ की बात न कर सकें. उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी वी एन राय ने अपनी पुस्तक में साफ़ तौर पर लिखा है कि मुसलमान कभी भी दंगों की शुरुआत नहीं करता, लेकिन दंगों में मरने वालों में अधिकतर मुसलमान ही होते हैं. ऐसे में यदि यह मान लिया जाए कि राज्यों और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां सांप्रदायिक हैं, तो कोई ग़लत बात नहीं है. बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना कोई नई बात नहीं है. ऐसी परिस्थितियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं. आज मुसलमान देश में अल्पसंख्यक हैं और ग़ैर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि बहुसंख्यक अपनी बातों को अल्पसंख्यकों पर थोपना चाहते हैं, जो अक्सर दंगों का कारण बनती हैं. मुसलमानों को चाहिए कि वे संगठित एवं शिक्षित हों, साथ ही आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनें. जब तक वे सत्ता में अधिक से अधिक दख़ल नहीं रखेंगे, प्रशासन एवं सुरक्षाबलों में अपनी भागीदारी दर्ज नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी. दंगों को केवल संतुलन स्थापित करके ही रोका जा सकता है, संतुलन चाहे सांगठनिक हो, शैक्षिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक.

-रफ़ीक़ चौहान, करनाल, हरियाणा.

राष्ट्रीय दवा नीति एक छलावा

राष्ट्रीय दवा नीति-2011 को कैबिनेट की मंज़ूरी दिलाकर ज़रूरी दवाइयां सस्ती करने का सरकारी फ़ैसला ऊपर से देखने में बेहतर लग रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस नीति (बाज़ार आधारित नीति) के तहत दवाइयों के मूल्य तय किए जा रहे हैं, वह दवा कंपनियों की लूट को क़ानूनी जामा पहनाने जैसी है, क्योंकि उसके तहत कंपनियों द्वारा तय एमआरपी के औसत मूल्य को सेलिंग प्राइस अथवा सरकारी रेट तय करने की बात कही गई है. ग़ौरतलब है कि कंपनियां लागत से 1000-3000 प्रतिशत ज़्यादा एमआरपी तय करती हैं. ऐसे में इन कंपनियों द्वारा तय एमआरपी का औसत बहुत ज़्यादा राहत देता नज़र नहीं आ रहा है. इसके विपरीत जो कंपनियां सस्ते दामों पर दवाइयां बेच रही हैं, वे भी इस औसत के चक्कर में अपने मूल्य बढ़ा देंगी. दरअसल, सरकार द्वारा 348 दवाइयों के मूल्य नियंत्रण की बात एक तरह से छलावा और लोगों को भरमाने का प्रयास भर है. यह नीति पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि सरकार सच्चे मन से दवाइयों के दाम कम नहीं करना चाहती. जहां हज़ारों प्रतिशत मुनाफ़ा कमाया जा रहा हो, वहां 10-20 प्रतिशत की कमी का क्या मतलब है? सरकार दवाइयों के दाम लागत मूल्य के आधार पर तय करे, तब कहीं जाकर सही मायने में आम जनता को कुछ फ़ायदा हो सकेगा.

-आशुतोष कुमार सिंह, मुंबई, महाराष्ट्र.

जागरूकता ज़रूरी

इसमें कोई शक नहीं है कि उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, लेकिन यहां उपभोक्ता अधिकारों को लेकर लोगों में सबसे कम चेतना है. अधिकांश लोग उत्पाद ख़रीदते समय ठगे जाते हैं. सरकार भी इसे लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं दिखती. पिछले दिनों मीडिया ने नक़ली घी के रैकेट का पर्दाफ़ाश किया था. ज़्यादा क़ीमत देने के बाद भी उपभोक्ताओं को कई बार ख़राब उत्पाद हाथ लग जाते हैं, लेकिन इसे वे अपना दुर्भाग्य मानकर चुप रह जाते हैं. ज़ाहिर है कि इससे उत्पाद बनाने वाले कारोबारियों का मनोबल बढ़ जाता है. शायद यही कारण है कि बाज़ार में घटिया एवं नक़ली वस्तुओं की भरमार है. ऐसा नहीं है कि उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त अधिकार नहीं हैं, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है. जटिल प्रक्रिया होने के कारण भी लोग उपभोक्ता न्यायालय में जाने से बचते हैं. ईमानदारी, मानवता और गुणवत्ता तो लगता है कि अब बीते दिनों की बात हो गई है.

-अशोक निर्मोही मुन्ना, दरभंगा, बिहार.

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11,
नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सेना रायसीना हिल्स तक जा सकती है

छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी घटना हो गई. कांग्रेस के काफिले पर गोली का चलना, लगभग 29 लोगों का मारा जाना, मारने के लिए लोगों के नाम पुकारना और उसके बाद जिन लोगों की जान बच गई, उनका मीडिया में आकर तरह-तरह के बयान देना. दूसरी घटना. पुलिस के जवानों की घेरकर हत्या और उनका असहाय स्थिति में शिकार बन जाना और उसके बाद पुलिस के लोगों का सरकार के ऊपर आरोप लगाना. क्या ये दोनों घटनाएं क़ानून व्यवस्था से संबंध रखती हैं, जिसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों साबित करना चाहते हैं? कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी, वरना यह कांड न होता और राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार उसे पर्याप्त सुरक्षाबल नहीं दे रही है, तो ऐसे में वह नक्सलवादियों का सामना कैसे करे?

सवाल यह है कि 65 वर्षों के बाद भी हमारा दिमाग़ या तो बहुत ज़्यादा मूर्ख हो गया है, जिससे हम सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं या फिर हम जानबूझ कर सच्चाई देखना ही नहीं चाहते. सत्यता यह है कि हमारा राजनीतिक तंत्र देश में सर्वांगीण विकास चाहता ही नहीं. आज़ादी के बाद लगभग हर दल की सरकार केंद्र में रही और राज्यों में भी सरकारें बदलती रहीं. इसके बावजूद देश का प्रत्येक राज्य न्यायपूर्ण विकास से वंचित दिखाई दे रहा है. एक तरफ़ न्यायपूर्ण विकास से वंचित रहना और दूसरी तरफ़ सामान्य सुविधाओं का उन्हें न मिल पाना, जो पिछड़ों की श्रेणी या फिर राज्य के विकसित हिस्से में नहीं आते हैं, यह एक और दु:खदायी बात है. हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने कभी उन क्षेत्रों में झांकने की कोशिश ही नहीं की, जहां पर सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है और महंगाई की वजह से लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं. अगर राजनीतिक नेतृत्व ने इस स्थिति को देखा होता और इसे गंभीरता से महसूस किया होता, तो आज यह स्थिति नहीं आती कि सड़क पर चलने में राजनेताओं को डर महसूस हो. हक़ीक़त तो यह है कि अब बड़े नेता सड़कों पर निकलते ही नहीं, वे सिर्फ़ ख़रीदारी करने के लिए या तो शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर खाना खाने के लिए बड़े रेस्टोरेंट में. वे छोटे रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाते. इसके पीछे जहां उनका काला धन काम करता है, उससे ज़्यादा उनका डर काम करता है. वे सामान्य जगहों पर जाकर लोगों के गुस्से का केंद्र नहीं बनना चाहते. जब राजनेताओं का यह हाल है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि देश की नौकरशाही के बड़े हिस्से, जिसे देश के विकास या समस्याओं को हल करने में रुचि लेने की कोई चाह ही नहीं है, की क्या मन:स्थिति होगी. पूरा देश राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति से चलता है और आज के राजनेताओं में न इच्छाशक्ति है, न समझदारी है और न ही कोई भविष्य की कल्पना है.

> **छत्तीसगढ़ की इस घटना ने इस धारणा की पुष्टि कर दी है कि जनता उस मुक़ाम पर पहुंच गई है, जहां उसके मन में सत्ताधीशों के प्रति अब कोई मोह नहीं रहा. वह यह मानती है कि सारे दल एक हैं और शायद इस पार्टी तंत्र की वजह से ही देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी और ग़ैर बराबरी वाले विकास का बोलबाला है. इस धारणा ने लोगों को अपना क़ानून बनाने की मन:स्थिति में ला दिया है. लोगों का विश्वास न तो पुलिस पर है, न ही लोकसभा-विधानसभाओं पर है और अब उनका न्यायपालिका के ऊपर से भी विश्वास डगमगाने लगा है.**

छत्तीसगढ़ की इस घटना ने इस धारणा की पुष्टि कर दी है कि जनता उस मुक़ाम पर पहुंच गई है, जहां उसके मन में सत्ताधीशों के प्रति अब कोई मोह नहीं रहा. वह यह मानती है कि सारे दल एक हैं और शायद इस पार्टी तंत्र की वजह से ही देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी और ग़ैर बराबरी वाले विकास का बोलबाला है. इस धारणा ने लोगों को अपना क़ानून बनाने की मन:स्थिति में ला दिया है. लोगों का विश्वास न तो पुलिस पर है, न ही लोकसभा-विधानसभाओं पर है और अब उनका न्यायपालिका के ऊपर से भी विश्वास डगमगाने लगा है. छत्तीसगढ़ की घटना के बाद टेलीविजन के कुछ पत्रकार जंगलों में गए और उन्होंने वहां से जो तस्वीरें अपने चैनल के लिए भेजीं, उन्हें देखकर नेताओं के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे. उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हम अफ्रीकी देशों से भी बदतर स्थिति में रह रहे हैं. टेलीविजन कैमरों के फुटेज बताते हैं कि न कहीं सड़क है, न पानी है, न न्याय है, न विकास है, न स्कूल हैं, न अस्पताल हैं और न ही इनकी कोई संभावना है. यह स्थिति कुछ सैकड़ा या लाखों लोगों की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पूरा उत्तर पूर्व, हमारी सीमा से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं, जिनमें उड़ीसा और कश्मीर प्रमुख हैं, इन सारे ज़िलों में एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका से भी बदतर स्थिति में ज़िंदगी गुजार रहा है. होते-होते समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब समस्या सुधारने की बात लोग सुनना ही नहीं चाहते. लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजनेता इस बात को समझते ही नहीं. आज भी वे विकास की जगह क़ानून और व्यवस्था की समस्या बताकर अपनी कोताही, अपनी नालायकी और अपने पाप को छुपा लेना चाहते हैं.

छत्तीसगढ़ या जिन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी समस्या क़ानून और व्यवस्था की नहीं है. उनकी समस्या विकास की है, वह भी न्यायपूर्ण और संतुलित विकास की. पर चाहे टेलीविजन चैनल हों, राजनेता हों या अधिकारी हों, उनके द्वारा सेना भेजने का राग भैरवी शुरू हो गया है. टेलीविजन के ऊपर बयान देने वाले बहुत सारे कम अक्ल समीक्षक सेना भेजने की वकालत कर रहे हैं. उन्हें यह नहीं पता कि अगर सेना एक बार छत्तीसगढ़ जैसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अपने ही देश के लोगों से लड़ने में लगा दी गई, तो फिर वह वहीं तक नहीं रुकेगी, बल्कि रायसीना हिल्स, जहां राष्ट्रपति का घर है, वहां तक चली जाएगी. लोकतांत्रिक देश में सेना का एक रोल होता है और सेना को उस रोल से अलग करने की बात जो भी कर रहा है, वह न सिर्फ़ लोकतंत्र का, बल्कि इस देश का दुश्मन है. इस देश के नौजवानों और बुद्धिजीवियों को यह आवाज़ उठानी चाहिए. अगर राजनेताओं ने संपूर्ण देश में संतुलित विकास का रास्ता नहीं पकड़ा और देश में सेना के इस्तेमाल की भाषा पर रोक लगाने की मांग नहीं की, तो हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि इस देश के आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं.

इस देश का जितना नुक़सान राजनीतिज्ञों ने किया है और ख़ासकर बड़ी पार्टियों के राजनीतिज्ञों ने, उतना नुक़सान तो उन्होंने भी नहीं किया, जिन्होंने बरसों हमारे ऊपर शासन किया था. किसी तरह का भविष्य का कोई भी नक्शा राजनीतिक दलों के पास नहीं है और इसीलिए वे लोगों को झूठे वादों में उलझाना चाहते हैं. आख़िर पैंसठ वर्षों से जनता वादों का ही तो खेल देखती आ रही है. मेरा मोटा आकलन है कि लोग इस बात को समझ गए हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी, असंतुलित विकास, ख़राब शिक्षा और लचर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज़िम्मेदार राजनीतिक दल हैं. मैंने उन सारे काग़ज़ों को खंगाला, जिनमें राजनीतिक दलों ने जनता के लिए वादे किए हैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी वे वादे पूरे होते नज़र नहीं आए, बल्कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करने वाले बयान ज़रूर देखने को मिले. कोई कहता है कि हमने 100 में से 90 वादे पूरे किए, कोई कहता है कि 80 वादे पूरे कर दिए. इन राजनेताओं में ज़रा भी समझ नहीं है कि अगर वादे पूरे होने का फ़ायदा जनता को मिला होता, तो क्या वह राजनीतिक दलों को हिकारत की नज़र से देखती, जैसे आज देख रही है. राजनेता इस बात को भूल जाते हैं कि अगर वे जनता की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो वह अपनी समस्याएं सुनाने के लिए असंवैधानिक तरीक़े अपना लेगी. पर धन्य हैं वे राजनेता, जो दिन में बजते इस नगाड़े को नहीं सुन पा रहे हैं, जनता के दर्द का शंखनाद नहीं सुन पा रहे हैं, जनता का दर्द, उसकी तकलीफ और उसके आंसुओं को नहीं देख पा रहे हैं. तब हम कहने में क्यों संकोच करें कि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं और नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और इस तरह की घटनाएं बड़े पैमाने पर इस देश में कब से होने लगेंगी, इसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जनता के सब्र का प्याला भर चुका है और वह कभी भी छलक सकता है, कभी भी टूट सकता है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

अंतहीन युद्ध

आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध कोई नई बात नहीं है. आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है. इसके विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, इसी पर रोशनी डाल रही है यह टिप्पणी.

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब शांति काल की शुरुआत होगी. शांति के लिए किसने कितना प्रयास किया, इसकी बात होने लगी, लेकिन एक युद्ध ख़त्म होने के तुरंत बाद ही दूसरा युद्ध शुरू हो गया और यह युद्ध था आतंकवाद के विरुद्ध. आलोचकों का कहना था कि अमेरिका का हमेशा से कोई न कोई दुश्मन रहा है, इसलिए उसने एक नया युद्ध खोज निकाला, लेकिन आलोचकों ने उसका इतिहास सही तरीके से नहीं पढ़ा था. हाल में लंदन की गलियों में जिस तरह से उसके सैनिक की हत्या की गई, उसने एक बार फिर से इतिहास की ओर देखने का मौक़ा दिया है. आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध कोई नई बात नहीं है. दरअसल, इसे समझने के लिए सौ साल पूर्व के इतिहास में जाने की ज़रूरत है. बीसवीं सदी के इतिहास को जानने का एक रास्ता यह है कि प्रथम विश्वयुद्ध द्वारा उत्पन्न समस्याओं से पर्दा उठाया जाए, जो कि 94 साल पहले की घटना है. पहली समस्या जर्मनी के साथ हुई, जिसके कारण द्वितीय विश्वयुद्ध जैसी त्रासदी झेलनी पड़ी, लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध के समय पूर्व में रहने वाले लोगों का विकास हुआ, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य के विभाजन की शुरुआत हो गई. इसके अगले तीस सालों में भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का ख़ात्मा हो गया. इसके साथ ही 1918 में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन भी हो गया था, जिससे उत्पन्न समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है.

इस युद्ध के समय ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश स्थित कार्यालयों ने एक गुप्त संधि (साइक्स-पिकोट पैक्ट) की थी. इस संधि ने ब्रिटेन और फ्रांस के संरक्षण में ऑटोमन साम्राज्य को देशों में बांट दिया. पहली बार जेरूशलम ग़ैर-मुस्लिम शासन के अधिकार में चला गया. सीरिया एवं लेबनान को फ्रांस की देखरेख में रखा गया. जॉर्डन एवं इराक ब्रिटेन की खोज थे. फिलीस्तीन को ब्रिटेन का उत्तरदायित्व बना दिया गया. इससे न केवल भारत प्रभावित हुआ, बल्कि गांधी जी ने भी ख़िलाफ़त आंदोलन शुरू कर दिया. पहली बार हिंदू और मुस्लिम, दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और वह भी किसी घरेलू मुद्दे पर नहीं, बल्कि इस्तांबुल के मुद्दे पर. चौरी-चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया. ख़िलाफ़त को ब्रिटिश शासन द्वारा समाप्त नहीं किया गया, जिस बात का डर गांधी जी को था, बल्कि उसे कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त कर दिया गया. ऐसे में हिंदू-मुस्लिम के बीच एकता टूट गई और फिर कभी हिंदू-मुस्लिम एकता नहीं बनी. देश के विभाजन को इसी क्रम में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ख़िलाफ़त आंदोलन के बाद मुसलमानों को देश में अपनी स्थिति का भान हुआ, हालांकि इसके पहले वे इस्तांबुल को ही सत्ता का केंद्र मानते थे.

> **पिछले बीस सालों से आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध जारी है. यह नब्बे के दशक में पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले और यूएस कोल एवं केन्या में बम गिराए जाने से शुरू हुआ. कई मुजाहिदीन, जिन्हें मुस्लिम संगठनों ने प्रशिक्षण एवं हथियार दिए थे, सीमा पार कर कश्मीर पहुंचे और उन्होंने भारत में हमले भी किए.**

कुछ मायनों में पाकिस्तान केवल दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व एशिया की पूर्वी सीमा भी है. आतंकवाद के विरुद्ध जंग की जड़ मध्य पूर्व के इसी बंटवारे में है. फिलीस्तीन-इजरायल विवाद भी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का एक पहलू है, जिसमें मुस्लिम इस विवाद के लिए ब्रिटेन और अमेरिका पर आरोप लगाते हैं. 1945 के बाद मध्य पूर्व में सेक्युलर शासन, यहां तक कि समाजवादी शासन का एक दौर भी आया था, लेकिन तीन बार इजरायल से हारने के बाद अरब ने सेक्युलर विचार छोड़ दिया और वह पुराने विश्वास की ओर लौट गया. सऊदी अरब में तेल से आने वाले पैसों के कारण बहाबी आंदोलन पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में फैलाया गया. अब बदला लेने का समय था. ओसामा बिन लादेन का विचार इस बारे में बिल्कुल साफ़ था. वह अपने जेहाद को ख़िलाफ़त टूटने और जेरूशलम को अपवित्र करने के विरुद्ध कार्रवाई मानता था. वह सऊदी अरब में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के कारण दु:खी था, जहां मक्का एवं मदीना जैसे पवित्र शहर हैं. सोवियत संघ के अफगानिस्तान के साथ संघर्ष ने तालिबान एवं अलक़ायदा को अमेरिकी संसाधनों का इस्तेमाल करके मजबूत बनने का मौक़ा दिया. जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से चला गया, तो उनका ध्यान अमेरिका एवं उसके सहयोगियों की ओर गया. भारत ने अमेरिका का सहयोगी बनना तय किया और उसे आतंकवाद का भुक्तभोगी बनना पड़ा. यही स्थिति यूके की भी है. पिछले बीस सालों से आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध जारी है. यह नब्बे के दशक में पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले और यूएस कोल एवं केन्या में बम गिराए जाने से शुरू हुआ. कई मुजाहिदीन, जिन्हें मुस्लिम संगठनों ने प्रशिक्षण एवं हथियार दिए थे, सीमा पार कर कश्मीर पहुंचे और उन्होंने भारत में हमले भी किए. हम यूएसए में 9/11, लंदन में 7/7, मैड्रिड, बाली और कई अन्य जगहों पर हुई बम विस्फोट की घटनाओं के गवाह हैं. हाल में लंदन में एक सैनिक की हत्या उसी कड़ी का एक छोटा अध्याय है. यह लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं होगी. भारत भी इस युद्ध का उसी तरह हिस्सा बना हुआ है, जैसे यूके या यूएस इसके हिस्से हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

ट्रेन के चालक को नींद आएगी, तो ड्रेस ही उसे जगा देगी. उसने शराब पीकर ट्रेन चलाई, तो मुख्यालय पर तुरंत संदेश पहुंच जाएगा.

सूचना का अधिकार – जानने का अधिकार जीने का अधिकार – चौथी दुनिया की पहल

स्कूल इमारत पर कितना ख़र्च हुआ?

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

सरकारी स्कूल इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है. वजह, निजी स्कूलों का ख़र्च उठा पाने की हैसियत देश की उस 70 फ़ीसद आबादी के लिए शायद ही हो, जो रोज़ाना 20 रुपये से कम की आमदनी पर अपना जीवनयापन करती है. ऐसे में सरकारी स्कूल ही एक रास्ता बचता है, जहां इनके बच्चों को शिक्षा मिल सके. निश्चित तौर पर सरकार ने शिक्षा, ख़ासकर प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और सरकार इन योजनाओं पर अरबों रुपये ख़र्च भी कर रही है. सर्वशिक्षा अभियान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, बावजूद इसके, आज भी यह हालत है कि गांवों में अधिकांश प्राथमिक स्कूलों के भवन जर्जर अवस्था में हैं. यही नहीं, कभी इन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है, तो चाक नहीं. चाक होता है, तो बैठने के लिए मेज़ या कुर्सियां नहीं होतीं. अगर होती भी हैं, तो टूटी-फूटी.

हर एक स्कूल को साल में इन ज़रूरी चीज़ों के लिए बजट आवंटित किया जाता है. अब सवाल यह उठता है कि आख़िर पैसा मिलने के बाद भी प्राथमिक स्कूलों की हालत ख़राब क्यों रहती है? ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस बात पर नज़र रखें कि आख़िर स्कूल के विकास के लिए आने वाले पैसे का कहीं ग़लत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है.

ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों को इन चीज़ों के लिए पैसा नहीं मिलता. हर एक स्कूल को साल में इन ज़रूरी चीज़ों के लिए बजट आवंटित किया जाता है. अब सवाल यह उठता है कि आख़िर पैसा मिलने के बाद भी प्राथमिक स्कूलों की हालत ख़राब क्यों रहती है? ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए इस बात पर नज़र रखें कि आख़िर स्कूल के विकास के लिए आने वाले पैसे का कहीं ग़लत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है. ऐसी ख़बरें आती रही हैं कि स्कूल के विकास के लिए आने वाले पैसे का हेडमास्टर, मुखिया और अधिकारी मिलकर ग़बन कर जाते हैं. हमें पैसे की इस चोरी को रोकने के लिए क़दम उठाना ही होगा, क्योंकि यह हमारा ही पैसा है, जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और सरकार फिर उन पैसों को हमारे विकास के लिए ख़र्च करती है. क्या हम अपने विकास के लिए आने वाले पैसों का

हिसाब नहीं मांगना चाहेंगे?

आइए इस अंक में प्रकाशित आवेदन का इस्तेमाल कीजिए और अपने इलाक़े के सरकारी स्कूल के विकास से जुड़े ख़र्च का हिसाब मांगें. आप इस आवेदन के माध्यम से पूछ सकते हैं कि किसी ख़ास साल में आपके क्षेत्र के स्कूल के विकास के लिए कितनी रक़म आवंटित की गई और यह रक़म किन कार्यों के लिए आवंटित की गई? किन एजेंसियों के माध्यम से उक्त काम कराए गए? किन लोगों ने उक्त कार्यों को सही बताया और ठेकेदार को भुगतान की अनुमति दी? ठेकेदार को उक्त कार्य के लिए कितनी रक़म का भुगतान किया गया? यदि आप इस तरह की सूचना मांगते हैं, तो तय मानिए कि इस आवेदन से उन लोगों पर दबाव ज़रूर बनेगा, जो विकास का पैसा हज़म कर जाते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और साथ ही अन्य लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

विद्यालय की मरम्मत व अन्य ख़र्च का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय : सूचना केअधिकार अधिनियम-2005 केतहत आवेदन.

महोदय,
.... विद्यालय केसंबंध में सूचना केअधिकार केतहत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त विद्यालय को वर्ष..............से............केबीच कुल कितनी राशि का आवंटन किया? आवंटित राशि का ब्यौरा निम्नलिखित विवरण केसाथ दें:
   क. आवंटन का वर्ष
   ख. राशि
   ग. कार्य का नाम, जिसकेलिए आवंटन किया गया
   घ. ख़र्च की गई राशि
   ड. कार्य का नाम, जिसकेलिए राशि ख़र्च की गई
2. उपरोक्त विद्यालय में वर्ष..............से............केबीच कुल ख़र्च की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित विवरण केसाथ दें:
   . कार्य का नाम, जिसकेलिए ख़र्च किया गया
   . कार्य का संक्षिप्त विवरण
   . कार्य केलिए स्वीकृत राशि
   . कार्य स्वीकृत होने की तिथि
   . कार्य समाप्त होने की स्थिति अथवा चालू कार्य की स्थिति
   . कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
   . कार्य शुरू होने की तिथि
   . कार्य समाप्त होने की तिथि
   . कार्य केलिए ठेका किस दर पर दिया गया?
   . कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है?
   . कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
   . कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं,
   . उन सहायक तथा कार्यपालन अभियंताओं केनाम बताएं, जिन्होंने इन कार्यों का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी. इनके द्वारा कार्य केकिस भाग का निरीक्षण किया गया?

मैं आवेदन फीस केरूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नं.............है.
यदि मांगी गई सूचना आपकेविभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों केतहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्न:
(यदि कुछ हो)

ज़रा हट के

ताले की नो टेंशन

घर से जल्दी निकलने के चक्कर में लोग जल्दी में चाबी इधर-उधर रखकर भूल जाते हैं. जिससे कि कभी-कभी ताला खोलने की बजाय उसे तोड़ना पड़ता है, कहा जाता है कि जल्दी का काम तो शैतान का होता है. इसीलिए जल्दबाज़ी न करें, चाबी भूलने की आदत ज़्यादातर व्यक्तियों में होता है, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब इस समस्या को आप टाटा बोल दीजिए, लेकिन इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन का होना ज़रूरी है. बस एक फोन कीजिए और दरवाज़ा ख़ुद ही खुल जाएगा. दरअसल, अब डिजिटल ताले का अवतार हो चुका है. इस खास ताले को अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनाया गया है.

अपने घर के दरवाजे में बस आपको एक डिजिटल लॉक लगाना होगा. इसके बाद इस डिजिटल लॉक की कंट्रोल इकाई को अपने अपार्टमेंट के अंदर जोड़ना होगा. डिजिटल लॉक लगाने के बाद किसी ऐप को डाउनलोड करते ही यह लॉक काम करने लगता है. अगर दरवाजे में पहले से इंटरकॉम लगा हुआ है, तो आपको उसमें एक छोटी सी चिप लगानी होगी. जब आप दरवाजे के पास जाकर अपने फोन का बटन दबाते हैं, तो यह आपके अपार्टमेंट में लगे कंट्रोल यूनिट को एक संदेश भेजता है और दरवाज़ा खुल जाता है. फोन खो गया, नो टेंशन. बहुत से लोगों को यह डर होगा कि अगर फोन खो जाए, तो क्या होगा? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप ताले से जुड़ी सारी जानकारी पहले ही सेव कर रख सकते हैं. उस जानकारी के आधार पर ताला खुल जाएगा. अगर आप घर पर नहीं हैं और आपकी फैमिली या कोई रिश्तेदार आ जाए, तो भी चिंता की बात नहीं है. दूर बैठकर ही इस खास सॉफ्टवेयर की मदद से यह ताला खोला जा सकता है. इसमें समय व पैसे दोनों की बचत होगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

गाड़ी से भी तेज दौड़ती साइकिल

सभी लोग सोचते हैं कि साइकिल से ज़्यादा अच्छी कार है, क्योंकि साइकिल को गाड़ी की रफ्तार से तेज दौड़ाना नामुमकिन है. वैसे तो सभी व्यक्तियों को साइकिल की रफ्तार का अंदाज़ा होता ही है. साइकिल को अधिक से अधिक 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही दौड़ाया जा सकता है. क्या आपने कभी साइकिल को कार या फिर तेज रफ्तार स्पोर्ट बाइक को पछाड़ते हुए देखा है. आपको हैरानी होगी कि साइकिल कार या फिर बाइक को कैसे पछाड़ सकती है. दरअसल, ऐसा ही कुछ फ्रांस के रहने वाले फ्रैंकोएस जीसी ने एक रॉकेट लगी साइकिल से 263 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर कर दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया है. जीसी ने अपनी इस साइकिल में एक रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिससे यह साइकिल बेहद ही तेज गति से फर्राटा भरती है. इस साइकिल की रफ्तार का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह साइकिल आपकी आखों के सामने से कब ग़ायब हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा. ग़ौरतलब है कि जीसी ने यह नया विश्वकप रिकॉर्ड पिछले रिकॉर्ड 242.6 किलोमीटर प्रतिघंटा को तोड़कर बनाया है. ■

चालक को नियंत्रित रखेगी ड्रेस

आए दिन रेल दुर्घटनाओं के बारे में सुनते और पढ़ते रहते हैं. यह दुर्घटना ट्रेन चालक की सावधानी न बरतने के कारण होती है. कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. अब ट्रेन चालक को सावधानी बरतने के लिए उसकी ड्रेस उसे सावधान कर देगी. जैसे ही ट्रेन के चालक को नींद आएगी, तो ड्रेस ही उसे जगा देगी. उसने शराब पीकर ट्रेन चलाई, तो मुख्यालय पर तुरंत संदेश पहुंच जाएगा. धुंध के सीजन में सिग्नल दिखाएगी, तो भारी गर्मी से राहत देने के लिए ड्रेस ठंड का एहसास कराएगी. भारतीय रेलवे के इतिहास में ऐसी पहली ड्रेस बन रही है, जो चालक आराम से पहनकर ख़ुद या हज़ारों यात्रियों की सुरक्षा कर सकता है. भिवानी के टीआइटी कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्रों व प्राध्यापकों के इस प्रोजेक्ट को रेलवे डीजल लोको मोटिव शेड तुगलकाबाद ने भी अस्थायी अनुमति प्रदान कर दी है. इस ड्रेस की ख़ासियत यह है कि रेलगाड़ी में आग लगी, तो ड्रेस सचेत करेगी, धुंध में 800 मीटर पहले रेलमार्ग पर लगे लाइट सिग्नल बताएगी, दिमाग व धड़कन को भी यह ड्रेस मॉनीटर करेगी. इसमें सेंसरों का भी इस्तेमाल किया गया है. चालक को नींद का झटका आते ही सेंसर सबसे पहले वाइब्रेटर को वाइब्रेट करेगा. न जागने पर बजर बजना शुरू हो जाएगा. फिर भी नहीं जागने पर पिन्स हाथों में चुभना शुरू हो जाएंगी. इसके बावजूद चालक पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो मुख्यालय को संदेश चला जाएगा और गाड़ी धीमी हो जाएगी. ■

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
यह सप्ताह आपके लिए अच्छा साबित होगा. इस सप्ताह अत्यधिक विश्वास में आकर कोई निर्णय न लें, अन्यथा नुक़सान में रहेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से आप उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन अंततः आप फ़ायदे में रहेंगे. केवल अपनी आलसी प्रवृत्ति से बचें. जीवन साथी से भी आपका बर्ताव अच्छा बना रहेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप कोशिश करें कि जो पैत्रिक संपत्ति है, उसे बिना विवाद के समाधान कर लें. इस सप्ताह आपको अपने पुराने निवेश में भी फ़ायदे होंगे. नौकरीपेशा और व्यापारी भी आमतौर पर खुश रहेंगे. आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे. वहां पर भी ख़र्च संभव है. व्यर्थ यात्रा से बचें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
यह सप्ताह आपके भाग्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा. पुरानी समस्याओं से निजात मिलेगा. आप अपनी प्रतिभा और पराक्रम से बड़ी चीजों को भी आसानी से निपटा लेंगे. बेरोज़गार लोगों को भी रोज़गार का अवसर प्राप्त होगा. विद्यार्थियों के लिए सफलता पाने वाला सप्ताह रहेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह कुछ मानसिक समस्या भी आपको परेशान कर सकती है. आपकी व्यस्तता बढ़ेगी. आप अपनी व्यर्थ के ख़र्चों पर लगाम लगाएं. पार्टनरशिप वाले व्यापारी अपने लेन-देन का ध्यान रखें. परिवार केअंदर कुछ मतांतर उत्पन्न होंगे. इस सप्ताह ज़्यादा परिश्रम करने केलिए भी आप तैयार रहें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह आप पुरानी समस्याओं से निजात पाएंगे. आपका पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा. स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. निवेश के लिए भी अनुकूल समय है. नौकरीपेशा लोग थोड़े चिंतित रहेंगे. व्यापारी हलके उतार चढ़ाव केसाथ अच्छा करेंगे. विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
यह सप्ताह आपकेलिए बहुत अनुकूल सप्ताह नहीं रहेगा और मानसिक उद्विग्नता बढ़ेगी. पारिवारिक माहौल भी थोड़ा तनावयुक्त रहेगा. परिवार में विवाह से संबंधित चर्चा हो सकती है. व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाएंगे. मित्र बंधु का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा. नौकरीपेशा लोग ध्यान रखें कि उनके अधिकारी उनसे खुश हैं या नहीं.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आय कम और ख़र्च ज़्यादा होगा. स्वभाव आपका उग्र होता दिखेगा. आपको धन की प्राप्ति होगी. वाहन सावधानी से चलाएं. किसी भी तरह के क्रय विक्रय में सावधानी रखें. पारिवारिक वातावरण सौहार्द्रपूर्ण रहेगा. विद्यार्थी वर्ग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी. परोपकार केकार्य भी करेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह अकस्मात धन प्राप्ति केयोग हैं. सप्ताहांत में थोड़े ख़र्चे भी बढ़ेंगे. कुछ पारिवारिक शुभ कार्यों के प्रबल संकेत भी हैं. कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा और मन हर्षोत्फुल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों केपदोन्नति की ख़बर प्राप्त होगी. अपने साथ कार्य करने वाले लोगों केसाथ वाद विवाद से बचें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह नए कार्यों में अत्यधिक हड़बड़ी न दिखाएं. मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोत्तरी होगी. पूर्व नियोजित कार्यों में परेशानी और मानसिक तनाव रहेगा. स्वास्थ्य केप्रति सजग रहने की ज़रूरत है. अतिथियों का सम्मान करना पड़ेगा. जमा पूंजी को सावधानी से ख़र्च करें. स्थाई संपत्ति की ख़रीद पर विचार बनेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
यह सप्ताह आपके लिए भाग्य से ज़्यादा कर्म प्रधान रहेगा. सांस्कृतिक और सामूहिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त रहेगा. भूमि और भवन ख़रीदने की योजना बनेगी. पारिवारिक क्लेश रहेगा, लेकिन आप इससे दूरी बना कर चलें. विद्यार्थियों केलिए अच्छा प्रदर्शन दिखाने का समय है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह आपका उत्साह बढ़ा रहेगा. आप सप्ताह का कुछ समय नई योजना बनाने में भी व्यतीत करेंगे. इस सप्ताह ज्ञानी लोगों केसंपर्क में भी रहेंगे. आपकी आलसी प्रवृत्ति के कारण आप अपमानित होंगे, स्थानांतरण से प्रोन्नति का भी योग है. जोखिम वाले बाज़ार से बच कर चलें. विरोधी का स्वर तेज रहेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
यह सप्ताह आपकेलिए सामान्य फल देने वाला रहेगा. आप अपने आपको किसी भी समाचार से निराश न करें. आपके पारिवारिक सदस्य ही आपकेविरोध में प्रतिक्रिया दे सकते हैं. किसी मित्र बंधु केऊपर विश्वास कर कोई बड़ा निर्णय न लें. किसी नए व्यक्ति केसंपर्क से आपको लाभ का योग है. स्वास्थ्य में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा.

cshekhar_3@hotmail.com

विश्लेषकों का कहना है कि पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ की अगुवाई वाली नई सरकार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते न केवल सुधार सकती है, बल्कि आतंकवाद निरोधक रणनीति भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती है.

पाकिस्तान में नवाज शरीफ का राज

बहेगी अमन की बयार !

पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब कोई व्यक्ति, यानी नवाज शरीफ तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हों. चुनावी जंग तो उन्होंने जीत ली, लेकिन उन्हें अंदरूनी कलह, आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर भी सोचना होगा. भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भी उन्हें पाकिस्तान के लोगों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी उन्हें ये सारे काम करने होंगे. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या नवाज पाकिस्तान में अमन की बयार बहा पाएंगे?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नवाज शरीफ की जीत ने पाकिस्तान में जनतंत्र का बिगुल फूंक दिया है, जिसकी गूंज भारत में भी साफ़ सुनाई दे रही है. दरअसल, ज़रूरत इसी बात की थी, क्योंकि सुस्थिर, शांत, खुशहाल पाकिस्तान हिंदुस्तान के अपने राष्ट्रहित में है. पाकिस्तान के ऐतिहासिक आम चुनाव में नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) 272 सीटों में से 122 सीटों पर जीत हासिल कर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. नवाज की जीत को पड़ोसी मुल्कों में पाक में स्थिर सरकार की स्थापना के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि यह सरकार के वहां की सेना के साथ रिश्तों पर निर्भर करता है, जो कि इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकों का अधिकांश समय सैनिक शासन के पहरे में ही गुजरा है, जहां किसकी आज़ादी कब छिन जाए और किसकी ज़िंदगी पर कब ग्रहण लग जाए, यह दावे के साथ कहा ही नहीं जा सकता. सच तो यह है कि नवाज शरीफ खुद इस क्रूर और तानाशाह सैन्य शासन के भुक्तभोगी हैं. इसलिए यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान सरकार की स्थिरता वहां की सेना के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करती है. दरअसल, अगर सरकार और सेना के बीच मेलजोल रहा, तो सरकार स्थिर रहेगी, अन्यथा यदि तनातनी बढ़ी और रिश्ते तल्ख हुए, तो समझिए कि सरकार का पत्ता साफ़. इसलिए नवाज शरीफ को बहुत सोच- समझ कर चलना होगा, अन्यथा वह एक कोरे प्रधानमंत्री से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाएंगे.

सुधर सकते हैं भारत-पाक रिश्ते

विश्लेषकों का कहना है कि पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ की अगुवाई वाली नई सरकार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते न केवल सुधार सकती है, बल्कि आतंकवाद निरोधक रणनीति भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकती है. यह हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1999 में शरीफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा के लिए आमंत्रित किया था. इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब यह उम्मीद है कि परमाणु संपन्न इन पड़ोसियों के बीच संबंधों के एक नए दौर का सूत्रपात भविष्य में ज़रूर होगा.

दरअसल, जीत के बाद नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया है कि वह अपनी सरजमीं से भारत में आतंक फैलाने वाली किसी गतिविधि की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का भलीभांति एहसास है कि किस तरह से करगिल युद्ध से उन्होंने अपने हाथ जला लिए थे. इसीलिए अब वह हर क़दम फूंक-फूंक कर रखेंगे. दरअसल, उनके बयानों से भी यही लगता है. यहां यह बताना ज़रूरी है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए नवाज ने पहल भी शुरू कर दी है. यदि बयानों के इशारों को समझें, तो परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. लेकिन स्थिति चाहे जो भी हो, भारत से हाथ मिलाने के लिए नवाज हरसंभव कोशिश करेंगे. शरीफ ने कहा कि हम भारत से रिश्ते बेहतर करने के लिए काम करेंगे. हम भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, इसलिए करगिल और 26/11 जैसी घटनाओं की इजाजत हम कभी नहीं देंगे. यह हम सभी जानते और मानते हैं कि आतंकवाद भारत और पाकिस्तान दोनों को नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच कश्मीर समेत सभी मुद्दे सुलझाना चाहते हैं. लाहौर घोषणा पत्र एक अच्छी शुरुआत थी और वह एक बार फिर उस पर अमल करेंगे. एक बड़े क़दम के तौर पर उन्होंने भारत को भरोसा दिलाया कि जेहादी तत्वों को नेस्तनाबूद करने की हरसंभव कोशिश की जाएगी.

धनी परिवार के हैं नवाज

पाकिस्तान में तीसरी बार प्रधानमंत्री का ताज पहन चुके नवाज शरीफ का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक धनी परिवार में 25 जनवरी, 1949 को हुआ था. लाहौर के सरकारी कॉलेज से स्नातक और पंजाब यूनिवर्सिटी से क़ानून की डिग्री हासिल करने वाले शरीफ का निजी एवं राजनीतिक जीवन बहुत उतार-चढ़ाव से भरा रहा.

भारत से गहरा रिश्ता

नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में इतिहास रचने जा रहे हैं. सरहद के उस पार इतिहास रचने वाली इस शख्सियत का इतिहास भारत की मिट्टी से ही निकला है. बस एक पीढ़ी पहले नवाज के पिता पंजाब के तरनतारन के एक गांव में रहा करते थे. नवाज शरीफ के पिता मियां मुहम्मद शरीफ कारोबार के सिलसिले में लाहौर चले गए. कारोबार चल निकला, तो वे लोग वहीं बस गए. लाहौर के उनके घर का नाम भी जात्ती उमरा ही है. सियासत की ज़मीन बनाते-बनाते नवाज शरीफ भले ही अपनी असली ज़मीन भूल गए हों, लेकिन यहां की मिट्टी आज भी उन्हें याद करती है.

ग़ौरतलब है कि नवाज शरीफ ने वर्ष 1999 में लाहौर घोषणा पत्र में काफी सफलता प्राप्त की थी. इसके बाद उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा था, इसलिए यह बात आगे नहीं बढ़ सकी. जानकार भी कहते और मानते हैं कि शरीफ संबंध सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें साथ ही साथ यह भी लगता है कि पाकिस्तान में सेना के वर्चस्व, खुफिया एजेंसी आईएसआई के हस्तक्षेप और आतंकवादी संगठन तालिबान के कारण दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करने में मुश्किलें ही मुश्किलें हैं. पाकिस्तान मामलों के जानकार भरत वर्मा मानते हैं कि शरीफ को पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उच्चतम न्यायालय का सहारा लेना होगा. एक अन्य जानकार फिरोज अहमद ने कहा कि यदि शरीफ सेना और आईएसआई पर नियंत्रण रखने में सफल होंगे, तभी दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बन पाएंगे. पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा का कहना है कि फिलहाल कश्मीर मुद्दे को एक तरफ़ रखकर अन्य मुद्दे सुलझाने को तवज्जो दी जाए, तो कश्मीर समस्या सुलझाने में मदद मिल सकती है. हालांकि भारत की भी अपनी कुछ चिंताएं हैं, जिनसे वह नवाज शरीफ को अवगत कराना चाहेगा. 2010 में तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने पाक यात्रा के दौरान एक सूची सौंपी थी. भारत पहले उन मुद्दों पर कार्रवाई चाहता है, जो 2008 के आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई से संबंधित हैं.

पाक अवाम होगी खुशहाल

पाकिस्तानी हलकों में यह बात सरेआम है कि अब वहां अमन-चैन की नई बयार बहेगी. विशेषज्ञ सुशांत सरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में इस चुनाव में काफी बदलाव देखने को मिला है और वहां मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह से अवाम ने वोट डाला है और दल विशेष को समर्थन दिया है, उससे लगता है कि इस बार पाकिस्तान में काफी बदलाव आने वाला है. नवाज शरीफ की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि उन्हें चार मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ेगा. पहला, सेना. दूसरा, अमेरिकी दखल एवं अफगानिस्तान. तीसरा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार एवं बिजली संकट जैसी आंतरिक समस्याएं. चौथा, भारत से रिश्ते. भारत से रिश्ते सीधे-सीधे पाकिस्तान की विदेश नीति से जुड़े हैं, जिसे आईएसआई और सेना संचालित करती है.

नवाज शरीफ क्यों जीते?

- नवाज शरीफ ने खुद को पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित किया है.
- पाकिस्तान में बेहतरीन इंफ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट्स लागू करने का श्रेय नवाज शरीफ को ही जाता है.
- मध्य वर्ग और छोटे शहरों के व्यापारियों की पसंद हैं नवाज शरीफ.
- अमेरिकियों ने विरोधी अभियानों को हवा दी, जिसे पाकिस्तानी अवाम ने तहेदिल से लिया.
- पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए बदनाम आसिफ अली जरदारी का विकल्प जनता को तलाशना ज़रूरी था.
- राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस घड़ी में खस्ताहाल पारिवारिक जागीर में तब्दील हो चुका था.
- तख्ता पलट की आशंका से परेशान जरदारी ने मेमोगेट प्रकरण में अपनी लाचारी बेनकाब कर दी थी. ऐसा नेता सुशासन कैसे दे सकता था.
- आर्थिक संकट हो या समाज के वंचित तबके को राहत दिलाने वाले कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा के समय सार्थक हस्तक्षेप अथवा संघीय ढांचे वाले राज्य की विभिन्न इकाइयों की आकांक्षाओं का सामंजस्य, सभी मोर्चों पर उनकी सरकार नाकाम साबित हो चुकी थी. यह बात हर पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल-ए-बर्दाश्त थी कि जरदारी-भुट्टो परिवार पाकिस्तान की संप्रभुता या सम्मान की हिफाजत करने में पूरी तरह नाकाम नज़र आता रहा. पाकिस्तान में बिजली संकट भी गहराता गया, जिसका समय रहते सरकार ने कोई हल ही नहीं निकाला.

आंतरिक समस्याएं

जरदारी की हार का सबसे बड़ा कारण बना बिजली संकट. हालांकि इससे निजात दिलाने के लिए फिलहाल नवाज शरीफ के पास कोई रोडमैप नहीं है. एक कटु सच यह भी है कि पाकिस्तान में 18 से 20 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है और इसे दुरुस्त करने के लिए उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाना होगा, यानी अपने पूरे शासन के दौरान नवाज शरीफ बिजली समस्या से दो-चार होते रहेंगे.

भ्रष्टाचार और महंगाई

पाकिस्तान के आर्थिक हालात बेहद खस्ताहाल हैं. महंगाई ने मुल्क को अब तक की सबसे भयावह स्थिति में पहुंचा दिया है. भ्रष्टाचार तेजी से पांव पसारता जा रहा है. ग़ौरतलब है कि कुछ समय पहले पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर भी उतर चुके हैं, इसलिए इससे निजात पाने के लिए उन्हें कड़े क़दम उठाने होंगे, लेकिन खुद उन पर भी कई आरोप हैं. इसी के चलते 1993 में वह बर्खास्त भी हो चुके हैं. यही नहीं, नवाज शरीफ की पार्टी के कई नेता इस आरोप से जूझ रहे हैं.

आतंकवाद से निपटना ज़रूरी आतंकवाद से पाकिस्तान का चोली-दामन का साथ रहा है. अभी भी बड़े एवं खूंखार आतंकी वहां पनाह पा रहे हैं. इसे लेकर कई देशों ने अपनी चिंता पाकिस्तान से साझा भी की है, लेकिन पाकिस्तान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. एक तरफ़ खैबर पख्तूनख्वा एवं अफगान से लगे इलाकों में अलकायदा और तालिबान सक्रिय हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव में बेशक तालिबान नाकाम रहा हो, लेकिन आएदिन होने वाले धमाके उसकी उपस्थिति बता ही देते हैं. नवाज को इस स्थिति से भी निपटना होगा, लेकिन यह सेना के सहयोग के बिना असंभव दिख रहा है.

क्या है विकल्प?

नवाज शरीफ फिलहाल सेना या आईएसआई से दो-दो हाथ करने से बचेंगे, यानी विदेश नीति में वह फिलहाल कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं. वह भारत एवं अमेरिका से रिश्तों में वैसी ही तल्खी बनाए रख सकते हैं, जैसी अभी है. हां, अफगान के मुद्दे पर ज़रूर वह सक्रियता दिखा सकते हैं, क्योंकि सेना भी यही चाहती है. ■

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा.

10 जून-16 जून 2013
चौथी दुनिया

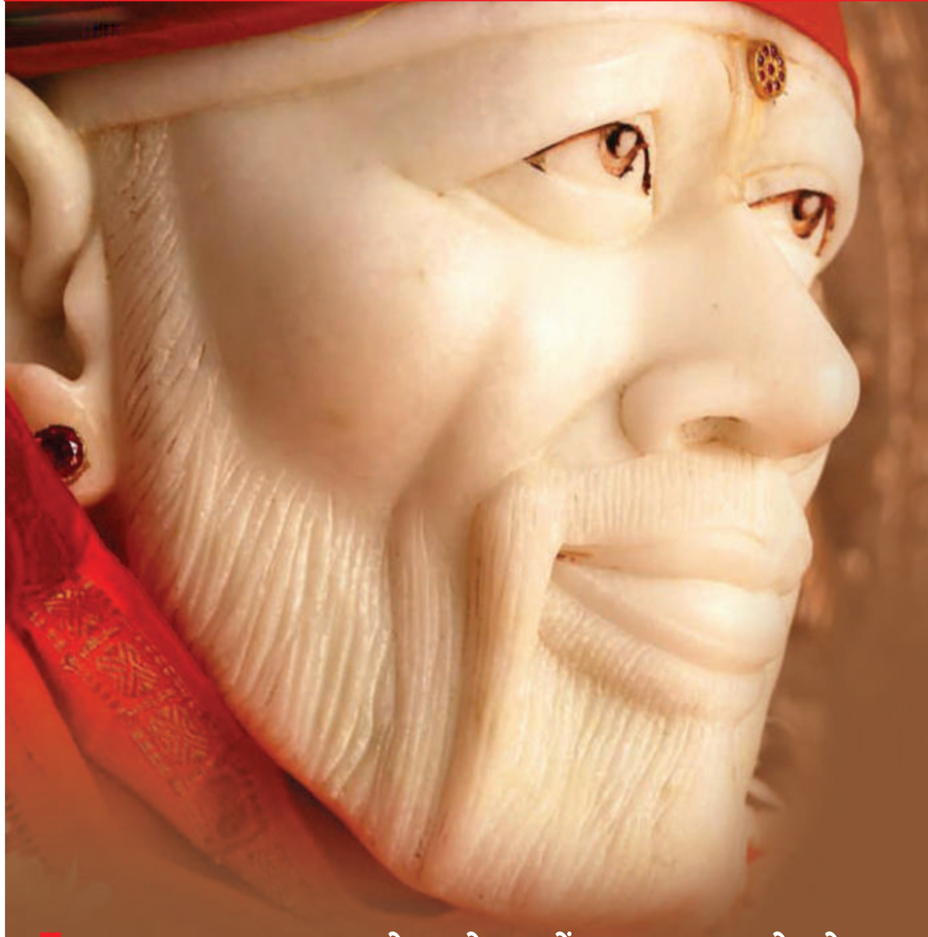

गुरु में हो विश्वास ...

अगर मनुष्य स्वच्छ मन से अपने गुरु में आस्था प्रकट करे, तो उसकी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं. साई बाबा ने किस तरह अपने भक्तों की चिंताओं को दूर किया. आइए जानते हैं इस लेख से.

यह सर्वविदित है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ श्रीमद्भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी. काकासाहेब इन ग्रंथों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधि लेने के उपरांत भी वह उसी प्रकार अध्ययन करते रहे. एक समय चौपाटी (मुंबई) में काकासाहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे. माधवराव देशपांडे (शामा) और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे. ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे. उस समय 11वें स्कंध के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोर्त्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझायी थी. राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान भी किया था. पठन समाप्त होने पर काकासाहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है. नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है. अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए कोई आशा ही नहीं है.

माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी नहीं लगी. वह कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साई सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तब फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है. यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है, तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं. क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है. तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहां रह जाता है. परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काकासाहेब का समाधान न हुआ. वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही रहे. दरअसल, यह विचार उनके मस्तिष्क में बार-बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी.

एक महाशय, जिनका नाम आनंदराव पाखाडे था, माधवराव को ढूंढते-ढूंढते वहां आ पहुंचे. उस समय भागवत का पठन हो रहा था. श्री पाखाडे भी माधवराव के समीप जाकर बैठ गए और उनसे धीरे-धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे. वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे. इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा. अतएव काकासाहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है. कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वप्न दिया है, उसे उनसे ही सुनो. उसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है. सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काकासाहेब को. सभी के कहने पर श्री पाखाडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है. मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूं. पानी मेरी कमर तक है और अचानक जब मैंने ऊपर देखा, तो साईबाबा के श्री-दर्शन हुए. वे एक रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री-चरण जल के भीतर थे. यह दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ. इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा. मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री-चरणों पर गिरो. मैंने उत्तर दिया कि मैं भी यही करना चाहता हूं. परंतु उनके श्री-चरण तो जल के भीतर हैं. अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं. मैं तो निस्सहाय हूं. इन शब्दों को सुनकर शामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपाकर अपने चरण बाहर निकालिए. बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया. बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ. घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अब तुम्हारा कल्याण होगा. उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक ज़री के किनारों की धोती मेरे शामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा.

बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाडे धोती लाए और काकासाहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं. कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेशसूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया. काकासाहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता, तो वे काग़ज़ की दो पर्चियों पर स्वीकार-अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते थे और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था, उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे. इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही दो पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रख दिया और एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा. बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई, तो वह स्वीकारसूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी. इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काकासाहेब का संदेह भी दूर हो गया. इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी मां अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है. बाबा के इन वचनों को हृदयपटल पर अंकित कर लो. इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता (गुरु) ही सच्चा पिता (सच्चा गुरु) है. दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हों, परंतु अपने गुरु का उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए. संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर, उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो. तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है, जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का. सच तो यह है कि बाबा की हर कथा में कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

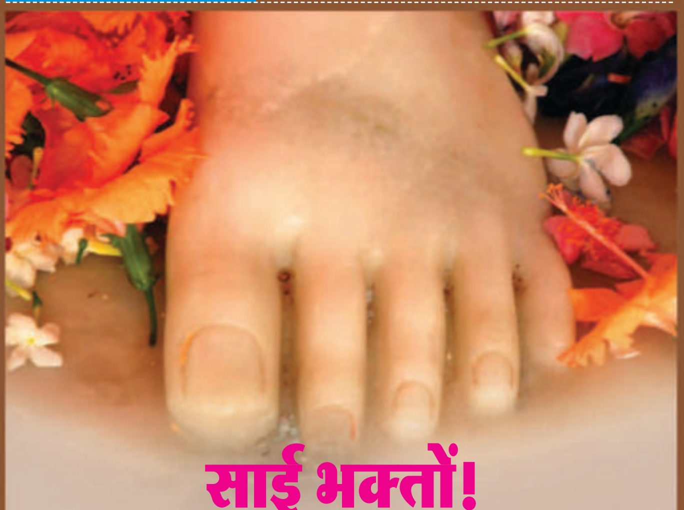

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर),
उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

दक्षिण भारत का काशी रामेश्वरम

सोनिका गुप्ता
sonika@chauthiduniya.com

दक्षिण भारत का रामेश्वरम मंदिर चार पवित्र धामों में से एक है. भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है. और क्या विशेषताएं हैं इस काशी में?

रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में स्थित है. रामेश्वरम का रामनाथस्वामी मंदिर शिल्प, स्थापत्य और आस्था के लिहाज़ से भी देश के सबसे महान मंदिरों में से एक है. यहां भगवान शिव का भव्य एवं प्राचीन मंदिर है, जो बारह ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत आता है. इस शिवलिंग की स्थापना दरअसल, भगवान राम ने की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ गया था. रामनाथ यानी राम के नाथ अर्थात शिव. चूंकि राम एवं शिव दोनों से मंदिर जुड़ा है, इसलिए यह मंदिर उन अनूठे मंदिरों में से एक है, जो शैव व वैष्णव, दोनों के लिए समान रूप से श्रद्धा के प्रतीक हैं. मंदिर तीन सौ साल पहले बना था और यह द्रविड़ शिल्प का बेहतरीन नमूना है. इसके गर्भगृह के चारों तरफ़ तीन गलियारे हैं. इसके अंत में बने गलियारे को भारत का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है. इसमें विभिन्न आकृतियों से सजे 1212 स्तंभ हैं. जहां आज मंदिर हैं, वहीं पर राम ने लंका युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शिव की आराधना में यज्ञ किया था. गर्भगृह में स्थापित दो लिंगों में से एक हनुमान द्वारा कैलाश से लाया गया और दूसरा सीता द्वारा रेत से बनाया गया था.

रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजाओं का बड़ा हाथ रहा. अब यह रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई है. रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है. कहा जाता है कि यह पत्थर राम ने केवटराज को राजतिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था. रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए जाते हैं. रामेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की दो मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग-अलग स्थापित की गई हैं. देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्द्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी. मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है. सेतुमाधव कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर भी प्रमुख है. इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक रोचक कहानी यह है कि राम ने पहले सागर से प्रार्थना की और कार्य सिद्ध न होने पर धनुष चढ़ाया, तो सागर प्रकट हुआ, जिसके कारण इसकी स्थापना की गई. कहीं पर सीताजी ने अग्नि-प्रवेश किया था, तो किसी अन्य स्थान पर श्रीराम ने जटाओं से मुक्ति पाई थी. ऐसी सैकड़ों कहानियां प्रचलित हैं. यहां राम-सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं, जो पानी पर तैरते रहते हैं. मान्यता है कि नल-नील नामक दो वानरों ने उनको मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को भी छुआ, वह पानी पर तैरने लगी और सेतु के काम आई. यहां कुछ और भी महत्वपूर्ण तीर्थ हैं-

विल्लूरणि

रामेश्वरम के मंदिर के बाहर कई तीर्थ हैं. प्रत्येक तीर्थ के बारे में अलग-अलग कथाएं हैं. यहां से क़रीब तीन मील पूर्व में एक गांव है, जिसका नाम तंगचिमडम है. गांव रेल मार्ग के किनारे बसा है. वहां स्टेशन के पास समुद्र में एक तीर्थकुंड है, जो विल्लूरणि तीर्थ कहलाता है. समुद्र के खारे पानी के बीच में से मीठा जल निकलता है, जो अचंभे की बात है. कहा जाता है कि एक बार जब सीताजी को प्यास लगी थी, तब पास में समुद्र को छोड़कर और कहीं पानी ही नहीं था, इसलिए राम ने अपने धनुष की नोंक से यह कुंड खोदा था.

कोदंड स्वामी मंदिर

रामेश्वरम के टापू के दक्षिण भाग में, समुद्र के किनारे एक और दर्शनीय मंदिर है. यह मंदिर रमानाथ से पांच मील दूर है. कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर राम की शरण ली थी.

रावण-वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राजतिलक कराया था. इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां देखने योग्य हैं. यहां विभीषण की मूर्ति भी है.

गंधमादन पर्वत

रामेश्वरम शहर से क़रीब डेढ़ मील उत्तर-पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी-सी पहाड़ी है. हनुमानजी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी. बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी. इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, जहां श्रीराम के चरण-चिन्हों की पूजा की जाती है. यह पादुका मंदिर कहलाया.

रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए जाते हैं. रामेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की दो मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग-अलग स्थापित की गई हैं. देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्द्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी. मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है. सेतुमाधव कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर भी प्रमुख है.

सीता कुंड

रामेश्वरम के पास कई ऐसे विशेष स्थान हैं, जहां स्नान करने से पाप को धोया जाता है. रामनाथजी के मंदिर के पूर्वी द्वार के सामने बना हुआ सीताकुंड मुख्य है. कहते हैं कि यह वही स्थान है, जहां सीताजी ने अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए आग में प्रवेश किया था. सीताजी के ऐसा करते ही आग बुझ गई और अग्निकुंड से जल उमड़ आया था. इसीलिए यह स्थान सीताकुंड कहलाया. यहां का समुद्र का किनारा अर्द्धगोलाकार है. सागर एकदम शांत और लहरें बहुत कम उठती हैं यहां.

आदि-सेतु

रामेश्वरम से सात मील दक्षिण में एक स्थान है, जिसे दर्भशयनम कहते हैं. यहीं पर राम ने पहले समुद्र में सेतु बांधना शुरू किया था. इस कारण यह स्थान आदि सेतु भी कहलाता है.

बाईस कुंड

रामनाथ के मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ हैं. इनमें प्रधान तीर्थों (जल कुंड) की संख्या चौबीस थी, लेकिन दो कुंड सूख गए हैं और अब बाईस रह गए हैं. ये वास्तव में मीठे जल के अलग-अलग कुंए हैं. इनमें स्नान करना फलदायक और पाप-निवारक समझा जाता है. कहा जाता है कि इन तीर्थों में अलग-अलग धातुएं मिली हुई हैं. इस कारण इसमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं.

उल्लेखनीय है कि रामेश्वरम के समुद्रों में तरह-तरह की कोड़ियां, शंख और सीपें मिलती हैं, तो कहीं सफ़ेद रंग का बड़ियास मूंगा मिलता है. यह एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी दर्शनीय स्थल है. मद्रास से रेलगाड़ी यात्रियों को क़रीब बाईस घंटे में रामेश्वरम पहुंचा देती है. रास्ते में पामबन स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती है. ■

दरअसल

मौत अटल है

एक दिन यमदूत एक व्यक्ति के प्राण हरण करने आया, तो उस व्यक्ति ने कहा : मुझे आपके साथ आना पड़ेगा?
यमदूत : बिल्कुल
व्यक्तिः क्यों?
यमदूतः मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें तेरा नाम सबसे ऊपर है, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा.
व्यक्तिः ठीक है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हम यहां दोनों साथ में खाना खाकर जाएंगे.
यमदूतः ठीक है.
(वह व्यक्ति यमदूत से नज़र चुराकर खाने में नींद की गोलियां मिला देता है.)
खाना खाने के बाद यमदूत को ज़ोरदार नींद आती है और वह वहीं सो जाता है, वह व्यक्ति मौक़े का फ़ायदा उठाकर लिस्ट में से अपना नाम ऊपर से काटकर सबसे नीचे लिख देता है. जब यमदूत नींद से उठता है, तो कहता है, हे मानव ! तेरा खाना बहुत स्वादिष्ट था. मैं तुझसे ख़ुश हूं. अब मैं पहले तुझे नहीं लिस्ट में सबसे नीचे वाले से जाने की शुरुआत करूंगा.

शिक्षा : मौत को कोई नहीं टाल सकता, विधि का जो लेख है, वह होकर ही रहेगा. ■

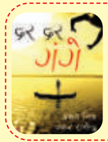

गंगोत्री से आगे बढ़ते हुए कब पहाड़ों पर ही गंगा का सौंदर्य पक्ष ख़त्म हो जाता है और गंगा चिंता का विषय बन जाती है, इसका एहसास पहाड़ी जीवन देखकर ही हो सकता है.

अनंत विजय

अलविदा! इंजीनियर

असगर अली इंजीनियर साहब एक तरक्की पसंद और प्रगतिशील विचारधारा के स्कॉलर थे. अस्सी के दशक में इस चिंतक और विचारक ने इस्लाम और उसकी व्याख्या को तर्कों की कसौटी पर कसना शुरू किया, तो कट्टरपंथी बेचैन हो गए. आज वे नहीं रहे, लेकिन उन्हें हम उनकी किताबों के माध्यम से श्रद्धांजलि दे सकते हैं.

एक बार कुछ लोग मोहम्मद साहब के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि हुज़ूर आपके बाद अगर इस्लाम के नाम पर उसकी अनर्गल व्याख्या की जाने लगे, तो उसको कैसे परखा जाए कि वह सही है या ग़लत. मोहम्मद साहब ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया कि इस्लाम की किसी भी तरह की व्याख्या को पवित्र कुरआन की कसौटी पर कसना और अगर कोई भी व्याख्या, चाहे वह कितने भी बड़े विद्वान की क्यों न हो, कुरआन की कसौटी पर खरा न उतरे, तो उसको उठाकर दीवार पर मारना. मोहम्मद साहब के इस कथन को कई व्याख्याकारों ने भुला दिया या फिर यह कह सकते हैं कि उसे दरकिनार कर दिया. नतीजा यह हुआ कि इस्लाम में कट्टरपंथ को लगातार बढ़ावा मिलता रहा, लेकिन यह कहना भी ग़लत होगा कि सभी इस्लामी विद्वानों ने इस्लाम की व्याख्या में ग़लती की. वहां भी कई तरक्की पसंद और प्रगतिशील विचारधारा के स्कॉलर हुए, जिन्होंने इस्लाम में फैली कुरीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. अस्सी के दशक में भारत में एक ऐसा ही चिंतक और विचारक सामने आया, जिसने इस्लाम और उसकी व्याख्या को तर्कों की कसौटी पर कसना शुरू किया. इस शख्स का नाम था असगर अली इंजीनियर.

अस्सी के दशक में ही असगर अली इंजीनियर साहब ने इस्लाम और भारत में सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर किताबों की एक पूरी श्रृंखला प्रकाशित की. उनके तर्कों ने कट्टरपंथियों को बेचैन कर दिया. उन्हें लगा कि अगर इस शख्स को नहीं रोका गया, तो उनकी दुकानदारी बंद हो सकती है. धर्म की ग़लत-सलत व्याख्या कर अपनी दुकान चमकाने वालों ने असगर अली इंजीनियर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन जानलेवा हमले करवाए. लेकिन असगर अली इंजीनियर अपने पथ से डिगे नहीं और अपनी कलम के जोर पर कुरीतियों के खिलाफ अपनी इस जंग को जारी रखा.

असगर अली का जन्म राजस्थान के दाऊदी वोहरा समाज के एक परिवार में 10 मार्च, 1939 को हुआ था. उनकी प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई, जहां उन्हें कुरआन, हदीस और अरबी की तालीम दी गई, लेकिन असगर अली का दिल कहीं और लग रहा था. अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नौकरी के लिए मुंबई जा पहुंचे. उन्होंने तक़रीबन दो दशक तक मुंबई महानगरपालिका में इंजीनियर की नौकरी की और यहीं से उनके नाम के साथ इंजीनियर शब्द जुड़ गया. जब पूरा देश इमरजेंसी के सदमे और ख़ौफ़ में था, उस वक्त असगर अली साहब ने तय किया कि वह नौकरी नहीं करेंगे. नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने दाऊदी बोहरा समाज में व्याप्त कुरीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी. वर्ष 1977 में वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कमेटी के महासचिव बने. इस पद पर पहुंचते ही उन्होंने इस समाज में जारी कठमुल्लेपन पर अपनी लेखनी और कार्यों के ज़रिए हल्ला बोल दिया. असगर अली साहब ने इस्लाम और इस्लामिक न्याय शास्त्र का तार्किक विवेचन शुरू कर दिया. नतीजा यह हुआ कि बोहरा समाज के धर्मगुरु ने उनको समाज से बाहर करने का फरमान जारी कर दिया. समाज बदर के फरमान के बाद उनके दफ्तरों पर हमले हुए, लेकिन कोई भी इस्लामी संगठन उनके बचाव के लिए आगे नहीं आया. उस वक्त असगर अली इंजीनियर बेहद जांबाजी के साथ कठमुल्लों से लोहा लेते रहे और उन्होंने यह साबित किया कि क्रांति के लिए हथियार उठाना ज़रूरी नहीं, बल्कि कलम के ज़ोर पर भी समाज में बदलाव के बीज बोए जा सकते हैं. उनके इस काम में हिंदी की उस दौर की प्रतिष्ठित पत्रिका सारिका और उसके तत्कालीन संपादक कमलेश्वर ने साथ दिया. असगर अली इंजीनियर के कई लेख उस दौर में सारिका में छपे, जिसके बाद गैर उर्दू पाठकों के बीच भी उनकी एक छवि निर्मित हुई. इस्लाम की व्याख्या का असगर अली इंजीनियर का अपना एक अलहदा तरीक़ा था. दरअसल, वे यह मानते थे कि इस्लाम में जिनकी आस्था नहीं है, वह भी इस्लामिक नागरिकों की तरह ही इंसान हैं. ज़ोर जबरदस्ती से धर्म के प्रचार के वे ख़िलाफ़ थे, उनकी यही बातें कठमुल्लों को रास नहीं आती थी.

आज के मौजूदा हालात में भारत के अलावा, विश्व के कई देशों में इस्लाम को लेकर बहुत भ्रांतियां व्याप्त हैं. अलग-अलग तरह की टीकाओं और व्याख्याओं के चलते इस्लाम की छवि एक कट्टरपंथी धर्म के रूप में दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है. इस्लाम की सही व्याख्या करती हुई किताबें भी भारत में लगभग नहीं के बराबर मौजूद हैं. असगर अली इंजीनियर ने अपने लेखन से भरसक इस कमी को दूर करने की कोशिश की. उनकी कई किताबें- इस्लाम एंड इट्स रेलिवेंस टू ऑवर एज, इस्लाम एंड रिवोल्यूशन, इस्लाम एंड मुस्लिम्स जैसी किताबों ने धर्म पर छाए धुंध को हटाने का काम किया. भारत में दंगों पर भी असगर अली इंजीनियर साहब ने काफ़ी काम किया. दंगा पीड़ित इलाक़ों का भ्रमण करने के बाद वहां के लोगों के मनोविज्ञान पर भी उन्होंने किताबें लिखीं. इस विषय पर लिखी उनकी दो किताबें- कम्युनलिज्म और कम्युनल वॉयलेंस इन इंडिया और कम्युनल रॉयट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया- बेहतरीन हैं. भारत के सामाजिक तानेबाने को समझने के लिए इन दो किताबों को पढ़ना मुझे ज़रूरी सा लगता है.

असगर अली इंजीनियर साहब इस्लाम में स्त्रियों की स्थिति को लेकर ख़ासे चिंतित रहा करते थे. उनका मानना था कि कुरआन में स्त्रियों को जो जगह दी गई है, वह अभी उस मुक़ाम तक नहीं पहुंच पाई है. असगर अली साहब कहते थे कि मुसलमानों में जिस तरह का पितृसत्तात्मक समाज है, वहां महिलाओं को अभी तक बराबरी का हक़ नहीं दिया जा सका है. वह ताउम्र मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहे. असगर साहब का मानना था कि आधुनिक जमाने की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखीं और संवेदनशील हैं. लिहाजा उन्हें यह गंवारा नहीं है कि वे अपने पति का प्यार अपनी सौतन के साथ बांटें. उनका मानना था कि स्त्रियों को बराबरी का हक़ देने की वकालत नहीं करने वाले लोग धार्मिक नहीं हो सकते. हालांकि असगर अली के आलोचक इस बात से इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते थे. उनके विरोधियों का तर्क है कि असगर अली ने कुरआन की व्याख्या बेहद आधुनिक तरीक़े से की है. जिस वक्त कुरआन अस्तित्व में आया था, उस वक्त के हालात अलग थे. लेकिन असगर अली इंजीनियर अपनी बातों पर अडिग रहे. असगर अली इंजीनियर साहब ने पचास से ज़्यादा किताबें लिखीं. अभी कुछ सालों पहले ही उनकी आत्मकथा भी आई थी.

14 मई को असगर अली इंजीनियर साहब ने मुंबई में अंतिम सांस ली. उन्हें उनकी आख़िरी इच्छा के मुताबिक दाऊदी बोहरा संप्रदाय के कब्रिस्तान में नहीं दफनाकर सांताक्रूज के मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया. जहां उनके दोस्त मजरूह सुल्तानपुरी, कैफी आजमी और अली सरदार जाफरी दफन हैं. उन्हें उनके बेटे इरफान के साथ उनके निकट सहयोगी राम पुनियानी ने कब्र में उतारा. एक मुसलमान स्कॉलर को एक हिंदू ने कब्र में उतारा, इसका एक बड़ा संदेश है, जो अली असगर इंजीनियर साहब देना चाहते थे. असगर अली इंजीनियर साहब को श्रद्धांजलि.

हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है.
बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावर पैदा..

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पतितपावनी गंगा यात्रा की गाथा

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

हाल में पेंगुइन ने गंगा पर आधारित एक किताब प्रकाशित की है, जिसका नाम है दर दर गंगे. आइए जानते हैं, इस किताब में क्या ख़ास है?

गंगा सिर्फ़ एक नदी नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति है, सभ्यता है और आस्था है, इसीलिए गंगा को गंगा मैया कहा जाता है. हिंदू धर्म के अनुयायी गंगा को देवी मानकर इसकी उपासना करते हैं. अनेक पवित्र तीर्थस्थल गंगा के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार प्रमुख हैं. गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है. मान्यता यह है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है. मरने वाले व्यक्ति की राख और अस्थि कलश को गंगा में विसर्जित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसीलिए इसे पतितपावनी भी कहा जाता है. कुछ लोग गंगा के किनारे अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं. ग़ौरतलब है कि उत्तराखंड में 39 सौ मीटर ऊंची गंगोत्री से निकली गंगा 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में समा जाती है. अपनी लंबी यात्रा के दौरान गंगा तक़रीबन दस लाख वर्ग किलोमीटर उपजाऊ मैदान की रचना करती है.

हाल में पेंगुइन बुक्स ने गंगा पर आधारित किताब दर दर गंगे प्रकाशित की है. इसमें गंगा की यात्रा की कहानी है, जो गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक पहुंचती है. इस किताब के लेखक अभय मिश्रा और पंकज रामेन्दु ने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक यात्रा की. फिर गंगा की हालत और गंगा से जुड़े लोगों के बारे में अपने संस्मरण लिखे. लेखकों का कहना है कि तीन चरणों में की गई गंगा यात्रा वास्तव में गंगा के बहाने ख़ुद के भविष्य को जानने की यात्रा थी. गंगा किनारे चलते हुए हमारे भीतर भी एक यात्रा चल रही थी. यह यात्रा थी हमारी परंपराओं की, हमारी संस्कृति की, जो गंगा की लहरों की तरह ही कहीं-कहीं उत्ताल, तो कहीं-कहीं शांत नज़र आती थी. यह यात्रा ख़ुद की जिज्ञासा को शांत करने के लिए थी कि कैसे एक सभ्यता, समृद्ध संस्कृति, एक जीवन रेखा नदी मात्र में तब्दील हो गई? क्यों एक नदी निकलते, चलते, बहते करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लेती है? क्या वजह है कि कोई नदी मां कहलाने लगती है? इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए हमने गंगा के दर दर को खोजने की कोशिश की. गंगोत्री से आगे बढ़ते हुए कब पहाड़ों पर ही गंगा का सौंदर्य पक्ष ख़त्म हो जाता है और गंगा चिंता का विषय बन जाती है, इसका एहसास पहाड़ी जीवन देखकर ही हो सकता है. इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जिस टिहरी में पूरी भागीरथी को बांध दिया गया है, वहां पीने का पानी टैंकरों से क्यों आता है. किताब की शुरुआत होती है गंगोत्री से. फिर अगला पड़ाव आता है उत्तरकाशी, इसके बाद टिहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, नरौरा, गंगा नगहर, कन्नौज, बिठुर, कानपुर, कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद, विंध्याचल, बनारस, ग़ाज़ीपुर, बक्सर, पटना, बख्तियारपुर, मुंगेर, सुल्तानपुर, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, राजमहल, फरक्का, मायापुरी, कोलकाता और गंगासागर, जहां यह यात्रा ख़त्म हो जाती है. दरअसल, लेखकों ने न केवल गंगा के धार्मिक पक्ष को सामने रखा है, बल्कि गंगा की मौजूदा हालत और इससे जुड़े लोगों के सुख-दुख को भी विभिन्न किरदारों के माध्यम से पेश किया है. मसलन, किताब के अध्याय गढ़मुक्तेश्वर, पहचान का संकट को ही लीजिए-

जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े

हरि राम यही गाना गाते हुए अपनी नाव को साफ़ कर रहा है. वह जानता है कि अब यह गाना सिर्फ़ मन बहलाने के लिए ही रह गया है. आज अगर प्रभु आ जाएं, तो शायद केवट उन्हें पार करा पाने की असमर्थता प्रकट करते हुए हाथ जोड़ लेगा. अब तो यह गाना सिर्फ़ मल्लाह जाति के गौरवगान के रूप में ही रह गया है, क्योंकि अब न तो गंगा में इतना पानी बचा है और न ही मल्लाहों में इतना उत्साह.

दरअसल, गंगा की धारा अवरुद्ध होने से जहां गंगा में रहने वाले जीवों पर बुरा असर पड़ा है, वहीं गंगा से जुड़े लोगों का रोज़गार भी प्रभावित हुआ है. इस किताब में गंगा से जुड़ी समस्याओं का भी ज़िक्र है, जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करती हैं.

पर्यावरणविद और गांधीवादी कार्यकर्ता अनुपम मिश्र का कहना है कि दर दर गंगे सचमुच पूरी गंगा दिखा देती है, पूरी गंगा घुमा देती है. यह गंगा की गहराई भी बताती है और हमारे आधुनिक विकास का उथलापन भी. गंगोत्री से गंगा सागर तक की ऐसी विचार-यात्रा अद्भुत आनंद देती है. साथ ही एक अजीब-सी उदासी भी. उदासी इसलिए कि पाठक इस यात्रा की समाप्ति को मन से स्वीकार नहीं कर पाता. बहरहाल, किताब बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक है. यह कहना ग़लत न होगा कि यह पाठक को गंगा की संपूर्ण यात्रा करा देती है. किताब की भाषा शैली उत्कृष्ट है और यह पाठक को शुरू से आख़िर तक बांधे रखती है. उम्मीद है कि पाठकों को यह किताब बेहद पसंद आएगी.■

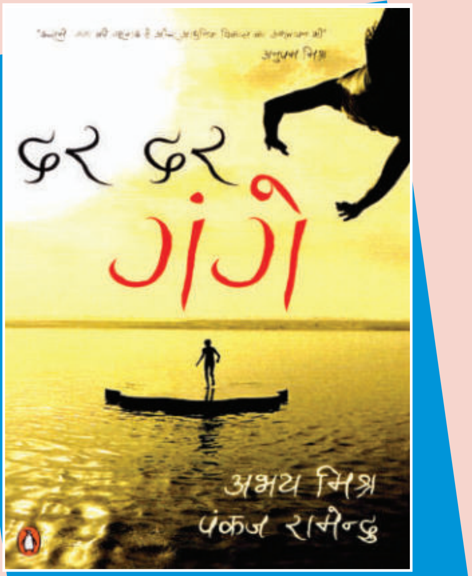

समीक्ष्य कृति : दर दर गंगे
लेखक : अभय मिश्रा, पंकज रामेन्दु
प्रकाशक : पेंगुइन बुक्स
क़ीमत : 199 रुपये

पर्यावरणविद और गांधीवादी कार्यकर्ता अनुपम मिश्र का कहना है कि दर दर गंगे सचमुच पूरी गंगा दिखा देती है, पूरी गंगा घुमा देती है. यह गंगा की गहराई भी बताती है और हमारे आधुनिक विकास का उथलापन भी. गंगोत्री से गंगा सागर तक की ऐसी विचार-यात्रा अद्भुत आनंद देती है.

काव्य दुनिया

स्त्री

पुरुष यानी व्यक्ति
जो सो सकता है पैर फैलाकर
सारी चिंताएं हवाले कर
पत्नी यानी स्त्री के
और वह स्त्री
जो रहती है निरंतर जागरूक
और देखती रहती है
आगम की कठोर
नज़दीक आती परछाई को
और सुनती रहती है
उसकी कर्कश पदचापों की आहट
क्योंकि सोती नहीं है वह रात-रात भर
कभी ओढ़ाती रहती है सर्दी में
बच्चों को अपनी हृदय अग्नि
और कभी चुप कराती रहती है
बुख़ार में तपते बच्चे को
या बदलती रहती है
छोटे बच्चे के गीले कपड़े
और स्वयं पड़ी रहती है
उसके द्वारा गीले किए पर
या गलती है हिमशिला-सी
रोते हुए बच्चे को ममत्व देकर
और कभी-कभी देती रहती है
नींद में बड़बड़ाते पति यानी पुरुष के
प्रश्नों का उत्तर
क्योंकि उसे तो जागना ही है निरंतर

-डॉ. वेद व्यक्ति, *फ़रीदाबाद, हरियाणा*

लड़का

एक लड़का
जो घर से भाग गया
मां को याद आया
पिता को याद आया
आंगन, चौबारे, खेत
घर-द्वार, पगडंडी
बाग़-बग़ीचे, नहर, नलकूप
ताल-तलैया, मेले, नौटंकी
जागरण, भागवद, रामलीला
गिल्ली-डंडे के मैदान
कंचों की खन-खन, पतंगों की उड़ान
झूमते खेत, उदास किसान को
याद आया
एक लड़का
जो घर से भाग गया
उसे घर
कभी याद नहीं आया ■

-सुनीता जोशी, *सीतापुर, उत्तर प्रदेश*

किताब मिली

पुस्तक	लेखक	प्रकाशक	मूल्य
हिंदी साहित्य का उत्तरवर्ती काल	सत्यदेव मिश्र	लोकभारती प्रकाशन	400 रुपये

इस किताब में आधुनिक साहित्य की अनेक विधाओं के उद्विकास का संक्षिप्त विवरण है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

कंपनी ने अपनी इस नई बीएस4 नॉर्म्स वाली अंबेस्डर को कोलकाता के टैक्सी एसोसिएशन में पेश किया था.

बिजली की टेंशन को बॉय बॉय

अगर अचानक बिजली चली जाए, तो हम बिजली आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बिजली आएगी तो हम फोन, कैमरा, टॉर्च और प्रिंटर आदि पर काम कर पाएंगे. अगर नहीं आती, तो हमारा काम अटका रह जाता है, जिससे कि समय बरबाद होता है. आजकल लोग हर रोज कई ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक या फिर बैटरी पॉवर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैमरा, टॉर्च, सेलफोन, एमपी3 प्लेय. ग़ौरतलब है कि इन सभी गैजेट्स को हमें रोज चार्ज भी करना पड़ता है, लेकिन उस दिन हम इसे चार्ज कैसे करेंगे, जब हमारे पास बिजली बनाने के सभी साधन ख़त्म हो जाएंगे. वैसे, वैज्ञानिक भी सोलर एनर्जी को भविष्य में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं. हालांकि वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के कई दूसरे स्रोतों के बारे में भी पता लगाया है, लेकिन उनमें से सच तो यह है कि सोलर एनर्जी सबसे कारगर ऊर्जा का स्त्रोत माना जाता है. अगर सोलर गैजेट्स की बात करें, तो मार्केट में कई सोलर गैजेट्स भी उपलब्ध हैं. लेकिन फिर भी कुछ लोग सोलर गैजेट्स को लेकर भविष्य के नज़रिए में बदलाव लाना चाहते हैं. होसुंग जुंग, सियोबिजन ली और यंगू डू सोलर एनर्जी पर कुछ ऐसे गैजेट्स और दूसरी चीजों की डिजाइन बनाने में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में लोगों को आसानी से ऊर्जा मिल सके.

सोलर एनर्जी चश्मा

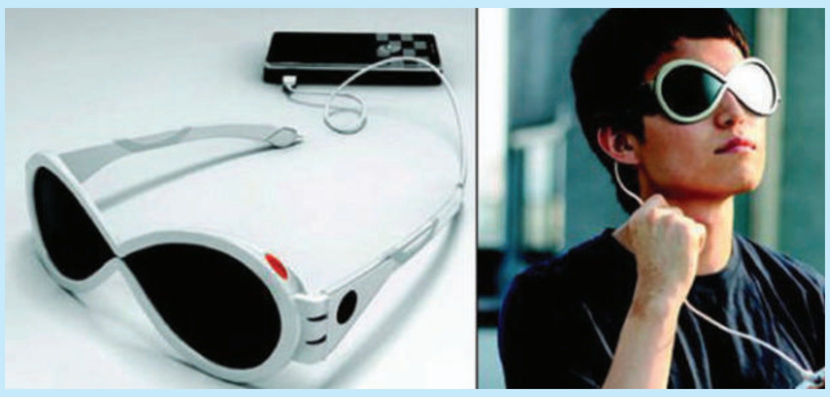

सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने वाला, यह चश्मा या सन ग्लासेस कोई साधारण ग्लासेस नहीं हैं. दरअसल इनमें सोलर ग्लासेस लगे हुए हैं, जो कि धूप में चलने से चार्ज हो जाते हैं. इसके बाद आप इससे कुछ और डिवाइसेस को भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं.■

सोलर कैमरा स्ट्रेप

आप अपने कैमरे की चार्जिंग को लेकर अब बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, क्योंकि यह कोई साधारण स्ट्रेप नहीं है. चूंकि इसमें सोलर सेल लगे हुए हैं, इसीलिए आप कभी भी इस सोलर सेल की मदद से अपना कैमरा चार्ज कर सकते हैं. ■

सोलर ट्रैफिक लाइट

भविष्य में यह सोलर लाइट आपको हर जगह दिखेंगी, क्योंकि ये लाइटें दिन में अपने आप चार्ज होकर रात में ट्रैफिक को संभाल सकती हैं. ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगी. ■

सोलर पॉवर रेडियो

रेडियो की जगह भले ही आजकल एमपी3 प्लेयर ने ले ली हो, लेकिन रेडियो का अपना एक अलग मज़ा है, क्योंकि आने वाले समय में रेडियो में सोलर सेल लगे होंगे, जिसकी मदद से आप कहीं भी जी भरकर रेडियो सुन सकते हैं. ■

सोलर बैटरी चार्जर

यह चार्जर स्पेशल ट्रैवलिंग के लिए ही बनाया गया है, जिसकी मदद से कोई भी डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, एमपी3 प्लेयर आसानी से चार्ज किया जा सकता है. ■

सोलर फ्लोटिंग रिजॉर्ट

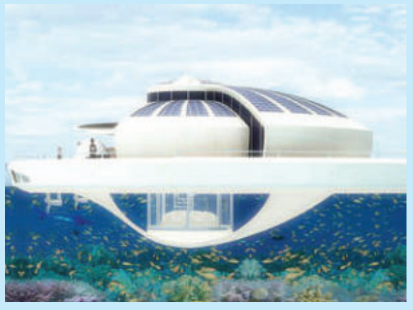

इस सोलर घर को आप भविष्य का घर भी कह सकते हैं, जिसमें ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो कि घर में बिजली देते रहते हैं. इसके अलावा, ऐसे घरों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है.■

जीरो एस, परफेक्ट बाइक

> बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता के साथ ही इंधन की खपत की झंझट से मुक्त, इससे ज़्यादा एक बाइक चालक को और क्या चाहिए! हालांकि कंपनी ने इस बाइक को भारतीय सड़क पर उतारने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है.

आजकल बाइकों के नाम बड़े ही अजीब-ग़रीब होते हैं, जो कि सुनने में बड़े अटपटे लगते हैं. अब देखिए जीरो एस मोटरसाइकिल का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा होगा कि यह नाम कैसा है, लेकिन जीरो एस मोटरसाइकिल अमेरिका की नामी-गिरामी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है. जी हां, यह कंपनी दुनिया भर में अपने बेहतरीन इलेक्ट्रिक बाइकों के लिए मशहूर है.

वैसे इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी के तौर पर भी पहचान मिल चुकी है. हालांकि भारतीय सड़कों से यह कंपनी दूर है, लेकिन जिस प्रकार से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही यह कंपनी भारतीय बाज़ार में भी फर्राटा भरेगी. कंपनी की तरफ़ से बनाई गई सबसे लोकप्रिय बाइकों में से एक है. ग़ौरतलब है कि जीरो एस ने यूरोपियन ई-मोटरबाइक ऑफ द इयर का खिताब अपने नाम किया है और यह लगातार तीसरी बार है, जब जीरो एस ने यह कारनामा कर दिखाया है.

बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता के साथ ही इंधन की खपत की झंझट से मुक्त, इससे ज़्यादा एक बाइक चालक को और क्या चाहिए! हालांकि कंपनी ने इस बाइक को भारतीय सड़क पर उतारने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन देश की सड़क के लिए यह एक परफेक्ट बाइक साबित हो सकती है. ■

अंबेस्डर का बीएस4 वर्जन

देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हिन्दुस्तान मोटर्स अपनी लोकप्रिय कार अंबेस्डर के नए अवतार को पेश करने जा रही है. इस बार यह कंपनी अंबेस्डर के नए बीएस4 को पेश करेगी. इस नई अंबेस्डर में कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता वाला बीएस4 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि बीएस4 नॉर्म्स वाले महानगरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कंपनी ने अपनी इस नई बीएस4 नॉर्म्स वाली अंबेस्डर को कोलकाता के टैक्सी एसोसिएशन में पेश किया था. कंपनी को अपने इस नये बीएस4 नॉर्म्स अंबेस्डर से काफी उम्मीदें हैं. यहां यह बताना ज़रूरी है कि अंबेस्डर का 1.5 लीटर डीजल कार अभी तक ऐसे महानगरों से दूर था. यह कार जल्द ही भारतीय बाज़ारों में दिखने लगेगी. सूत्रों की मानें, तो कंपनी इस नई बीएस4 अंबेस्डर कार को देश के 1% मेट्रोपॉलिटन शहर में पेश करेगी. लेकिन कुछ महीनों पहले कुछ शहरों में बीएस3 कारों पर बैन लगा दिया था.■

गैलेक्सी यंग स्मार्टफोन

बाज़ार में सैमसंग ने अच्छी पकड़ बना ली है. और दरअसल, इसीलिए आजकल ज़्यादातर लोगों के पास सैमसंग ही दिखाई पड़ता है. गैलेक्सी सीरीज़ की रेंज में अब तक सबसे सस्ता हैंडसेट स्टाकर लांच करने के बाद सैमसंग ने एक और स्मार्टफोन यंग लॉन्च किया है. इस हैंडसेट में 3.2 इंच की स्क्रीन दी गई है जो एचवीजिए रेज्योल्यूशन को सपोर्ट करती है, साथ में 1 गीगाहर्ट सिंगल कोर प्रोसेसर और 3 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो रोशनी में बेहतर व्यू देता है.

गैलेक्सी यंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई मोशन सेंसर लगे हुए हैं, जो इसकी क़ीमत को देखते हुए इसे महंगे फोन के फीचरों में शामिल करते हैं. इसके अलावा, इसका यूजर इंटरफेस काफी आसान है, यानी इसे कोई भी आसानी से ऑपरेट भी कर सकता है. फोन का भार 112 ग्राम है, जिससे इसे आराम से पॉकेट में कैरी कर सकते हैं. इस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग भी आसानी से कर सकते हैं. इंटरनल मेमोरी को आप माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट की मदद से 32 जीबी तक एक्सपैंड कर सकते हैं. इसमें कई फीचर्स हैं, जैसे फ्री ड्रॉप बॉक्स स्टोरेज, ईजी मोड, सैमसंग चैट ऑन मैसेंजर. सैमसंग ने नया स्मार्टफोन यंग खासतौर से उन लोगों के लिए लॉन्च किया है, जो कि फोन में थोड़ा अपग्रेड चाहते हैं. इसकी क़ीमत है 8,010 रुपये. ■

> गैलेक्सी यंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें कई मोशन सेंसर लगे हुए हैं, जो इसकी क़ीमत को देखते हुए इसे महंगे फोन के फीचरों में शामिल करते हैं. इसके अलावा, इसका यूजर इंटरफेस काफी आसान है, यानी इसे कोई भी आसानी से ऑपरेट भी कर सकता है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

क्या दोहा फुटबॉल विश्वकप में खेलेगा भारत

दुनिया भर में 2014 में ब्राजील में होने वाले विश्वकप को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं. लोगों के बीच इसे लेकर उत्सुकता का माहौल बना हुआ है. लेकिन भारत में 2014 की जगह 2022 का विश्वकप कौतुहल का विषय बन गया है. 2022 में दोहा में होने वाले विश्वकप के बारे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय फुटबॉल टीम उस विश्वकप में शिरकत करती दिखाई देगी. सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेट खिलाड़ी ने यह बात भारतीय फुटबॉल को लेकर कही है तो उनकेइस वक्तव्य में कितनी हक़ीकत है, और कितना फसाना है, यह जानना जरूरी है.

नवीन चौहान
navinchauhan@chauthiduniya.com

भारत में एक बार फिर फुटबॉल बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है, लोग इसे एक बार फिर गंभीरता से ले रहे हैं. देश के फुटबॉल प्रेमी उसके गौरवशाली अतीत के वापस लौटने की उमीद कर रहे हैं. ये कोशिशें वैचारिक स्तर पर तो जरूर होती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है. क्योंकि मैदान पर किसी भी तरह का परिवर्तन होता नहीं दिखाई पड़ा है, जिससे कि विश्वकप में खेलने के ख्वाब को हकीकत में बदला जा सके.

भारत का नाम उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिन देशों में फुटबॉल सुव्यवस्थित रूप से खेलना प्रारंभ किया गया था. पचास का दशक भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम समय था. 1950 में भारत ने ब्राजील में हुए विश्वकप में पहली बार क्वालीफाई किया था, लेकिन नंगे पैर होने की वजह से खिलाड़ियों को मैदान में उतरने नहीं दिया गया था. भारतीय खिलाड़ी उस समय नंगे पैर फुटबॉल खेलने के आदी थे, जबकि फीफा के नियमानुसार नंगे पैर फुटबॉल खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी. मायूसी का वह दौर आज भी चल रहा है. फुटबॉल प्रेमी भारत को विश्व की सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता में खेलते देखना चाहते हैं. छह दशकों से फुटबॉल प्रशंसक इस पल का इंतजार कर रहे हैं. 1956 में मेलबर्न में हुए ओलंपिक खेल भारतीय फुटबॉल का सबसे स्वर्णिम अध्याय है. भारत ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहला एशियाई देश बना था. भारत को उस ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल हुआ था.

ऐसे तो भारतीय फुटबॉल का इतिहास सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. पिछले सौ सालों में इसका विस्तार देश के कोने कोने तक नहीं हो सका. फुटबॉल के बेहतरीन मैदान और क्लब पश्चिम बंगाल, गोवा, मुंबई और उत्तर-पूर्व के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गए. फुटबॉल का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं बन पाया. आई-लीग में खेलने वाली 14 टीमों में से 11 टीमें गोवा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से हैं. पहले उत्तर भारत में हॉकी की लोकप्रियता ने फुटबॉल को पैर नहीं पसारने दिए. बाकी कसर देश में धर्म का दर्जा रखने वाले क्रिकेट ने पूरी कर दी. ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए इसमें देश के हर राज्य की भागीदारी सुनिश्चत करनी होगी.

सचिन के वक्तव्य को सिरे से दरकिनार नहीं किया जा सकता है क्योंकि सचिन क्रिकेट के अलावा कई अन्य खेलों में भी रुचि रखते हैं. इनमें से फुटबॉल भी एक है. सचिन ने फुटबॉल के भविष्य को लेकर कहा कि मैं जानता हूं कि 2022 में भारतीय फुटबॉल में कुछ बड़ा होने वाला है. सचिन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम उस साल के विश्वकप के लिए क्वालीफाई करने में सफल होगी. यही अभी से आपका लक्ष्य होना चाहिए और सीनियर खिलाड़ियों को चाहिए कि वे इसके लिए जूनियर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें.

कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) के उपाध्यक्ष प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने 2017 में होने वाले अंडर-17 विश्वकप की भारतीय दावेदारी का समर्थन किया था. उन्होंने कहा कि भारत एशिया का महत्वपूर्ण देश है. यहां फुटबॉल के विकास की अपार संभावनाएं हैं. प्रिंस अली भारत में पेप्सिको और एशियन फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट(एएफडीपी) के साझा कार्यक्रम किक फॉर होप को भारत में लांच करने के लिए आए थे. पेप्सिको और एएफडीपी 2013 में एशिया के 18 देशों में सामाजिक दायित्व के तहत फुटबॉल को एक माध्यम के रूप में प्रयोग कर सामाजिक कल्याण की परियोजनाएं संचालित कर रहा है. इसके अलावा वर्ष 2012 में इंडियन फुटबॉल फेडेरेशन और फीफा के बीच भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. बड़े औद्योगिक घरानों ने भारतीय क्रिकेट में अपार संभावनाओं को देखते हुए कदम रखा था, अब उन्हें विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल में भी अपार संभावनाएं नज़र आ रही हैं. औद्योगिक घराने अब फुटबॉल के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन(एआईएफएफ) की कॉरपोरेट घरानों को आई-लीग से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना में दिल्ली डेयरडेविल्स का मालिकाना हक रखने वाले जीएमआर और जिंदल जैसे बड़े ग्रुपों ने रुचि दिखाई है. एआईएफएफ ने फैसला किया कि अगले सत्र से इन कॉरपोरेट घरानों की दो से तीन टीमें आई- लीग में उतरेंगी. इसके लिए लीग में टीम की संख्या 14 से 16 करने का निर्णय लिया जा चुका है. व्यवसायिक घरानों ने भी फुटबॉल के विकास की ओर ध्यान दिया है. इसका असर राज्य और जिला स्तर पर फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता के रूप में दिखाई पड़ रहा है. फीफा के एक आकलन के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग 20 लाख लोग फुटबॉल खेलते हैं. वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम विश्व रैंकिंग में भारत 150 वें पायदान पर है. एशियाई रैंकिंग में भी भारत की स्थिति ठीक नहीं है. रैंकिंग में भारत बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों से भी पीछे है. भारत एशिया में पायदान पर है. जापान सबसे ऊंची रैंकिंग वाला एशियाई देश है उसके बाद दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है. इंडियन फुटबॉल फेडेरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने फिक्की द्वारा फुटबॉल पर केंद्रित गोल 2013 संगोष्ठी में कहा था कि फुटबॉल क्रिकेट के बाद देश में तेजी से तरक्की करने वाला खेल है. देश में फुटबॉल के बेहतरीन मैदानों की कमी है सरकार को आगे आकर इसके विकास के लिए काम करना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा खेल प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने और उनकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले देश में ज्यादा से ज्यादा विश्वस्तरीय फुटबॉल स्टेडियमों के बनाए जाने की आवश्यक्ता है. जूनियर स्तर से लेकर सीनियर स्तर तक के खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है. 2022 को लक्ष्य मानते हुए सीनियर स्तर पर फुटबॉल को मजबूत करने के साथ-साथ जूनियर स्तर पर फुटबॉल खिलाड़ियों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी, जिससे कि उदयीमान खिलाड़ियों को हर स्तर पर फुटबॉल खेलने का मौका मिल सके और सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव का फायदा जूनियर खिलाड़ियों को मिल सके.

जूनियर स्तर पर भारतीय फुटबॉल में बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं. अंडर-14, अंडर-16, अंडर-19, अंडर-22 की टीमों में देश के उत्तरी क्षेत्र के खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ती दिख रही है. भारत दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश और व्यवसायिक दृष्टि से एक बड़ा बाजार है. फीफा भारत को फुटबॉल की मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव सहयोग इसलिए दे रहा है, क्योंकि उसे भविष्य का फायदा भारत में नज़र आ रहा है. वह इस मौके को पूरी तरह भुनाना चाहता है. इंडियन फुटबॉल फेडेरेशन की सभी अकादमियों में 2017 में होने वाले अंडर-17 विश्वकप में क्वालीफाई करने का लक्ष्य रखकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. दो साल के प्रशिक्षण के बाद सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के समूह को उच्चस्तर की ट्रेनिंग के लिए दूसरी अकादमियों में भेजा जाएगा, ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए और बेहतर रूप में तैयार किया जा सके. आगे चलकर देश के अलग- अलग हिस्सों में इस तरह की अकादमियों को स्थापित किया जाएगा. जिसमें प्रकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके की फुटबॉल टर्फ के साथ सर्वसुविधा संपन्न होगी. इनमें जिम स्वीमिंगपूल जैसी कई सुविधाएं भी होंगी.

भारत में फुटबॉल के विकास के रास्ते में कई बाधाएं हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं. पैसे और बजट की कमी, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचों का प्रशिक्षण, रेफरियों का प्रशिक्षण, अन्य तकनीकि मामले, फिटनेस, चिकित्सकीय सहयोग, न्यूट्रिएंट्स और भूतपूर्व खिलाड़ियों के लिए करियर सपोर्ट जैसी अनगिनत बाधाएं हैं. इन सभी समस्याओं से एक सिस्टमैटिक तरीके से लक्ष्य निर्धारित करके पार पाया जा सकता है. इसके साथ ही जूनियर स्तर के विश्वकप का भारत में आयोजन एक चमत्कारिक प्रयोग साबित हो सकता है. इसी तरीके से भारत में एक झटके में भारतीय फुटबाल के स्तर में अप्रत्याशित बदलाव लाया जा सकता है. ■

हिंदी फिल्म के दर्शकों के लिए जल्द ही वह खुशखबरी देने वाले थे. वह अजय-करीना को लेकर एक हिंदी फिल्म की तैयारी में थे.

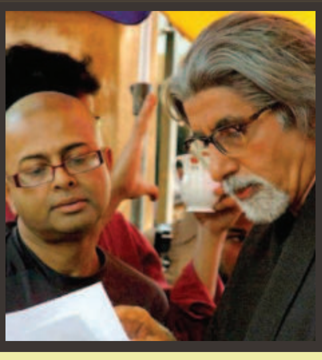

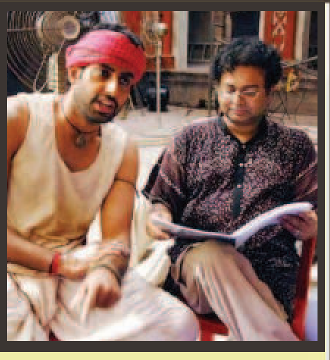

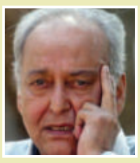

मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऋतुपर्णो घोष हमारे बीच नहीं रहे. इस बात को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है. हमने एक बेहतरीन फिल्म निर्देशक को बहुत कम उम्र में खो दिया.

–ऐक्टर सौमित्र चटर्जी

ऋतुपर्णो घोष के निधन की खबर से मैं सदमे में हूं. मैं ऋतु से कुछ-एक मौक़ों पर मिला था. वह बेहद गर्मजोश इंसान थे. वह बहुत याद आएंगे.

–मधुर भंडारकर

ऋतुपर्णो घोष केआकस्मिक निधन से मैं सन्न हूं. बेहद क्रिएटिव डायरेक्टर थे. हमने हाल में टैगोर प्रोजेक्ट पर बात की थी. नि:संदेह रितुपर्णो घोष का जाना देश के लिए अच्छा नहीं है. देश ने आज अपना एक अमूल्य बेटा खो दिया.

–ऐक्टर कबीर बेदी

मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऋतुपर्णो जी इस तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे. यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उन्हें इतनी जल्दी खो दिया. हाल ही में मेरी उनसे फोन पर एक फिल्म के सिलसिले में बात हुई थी. उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही हैं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दें. उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है.

–विद्या बालन

बंगाल के लिए ऋतुपर्णो घोष का निधन अपूर्णनीय क्षति है. वह राज्य के गौरव थे, हैं और हमेशा रहेंगे.

–ममता बनर्जी

ऋतु दा के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ. वह एक नायाब निर्देशक, अच्छे और अद्भुत इंसान थे. यकीन नहीं होता कि वह इस तरह से हम सब को छोड़ कर चले जाएंगे. अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी रितुपर्णो घोष के साथ मेरी पूरी फैमिली ने काम किया है. पापा यानी अमिताभ बच्चन ने फिल्म द लास्ट लियर, मां यानी जया बच्चन ने सन ग्लास, ऐश्वर्या ने चोखेर बाली और रेनकोट और मैंने अंतर महल में उनके निर्देशन में काम किया था. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

–अभिषेक बच्चन

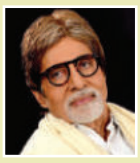

यकीन ही नहीं हो रहा कि रितुपर्णो घोष नहीं रहे. अभी हाल ही में तो मैंने उनसे फोन पर नई फिल्म के बारे में बात की थी. मैं एकदम पत्थर सा हो गया हूं. समझ में ही नहीं आ रहा कि यह सच कैसे स्वीकार करूं. वह एक बेहतरीन निर्देशक थे, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है.

–अमिताभ बच्चन

ऋतुपर्णो घोष के दुर्भाग्यपूर्ण देहावसान की ख़बर सुनकर उदास हूं. वह अपनी ब्रिलिएंट फिल्ममेकिंग के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे.

–नरेंद्र मोदी

वह हमारे समय के बेहतरीन निर्देशकों में से एक थे. उन्होंने कुछ माह पहले मुझे एक शानदार भूमिका की पेशकश की थी और मैं उनके साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक था. ऋतुपर्णो का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शानदार था. वह मानव स्वभाव को भी बेहतरीन तरीक़े से समझते थे. उन्हें और उनके सिनेमा को हमेशा याद रखूंगा. परमात्मा तुम्हारी आत्मा को शांति दे, मेरे दोस्त.

–अनुपम खेर

दु:खी हूं और ऋतुपर्णो घोष की ख़बर सुन कर हिल गया हूं. रेनकोट में उनके साथ काम करना एक यादगार अनुभव था. चीजों को देखने का उनका नज़रिया बहुत अलग और अनूठा था.

–अजय देवगन

ऋतुपर्णो घोष से मिलने का सम्मान मुझे इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार के दौरान मिला. ज़िंदगी इतनी अविश्वसनीय है, यकीन नहीं होता.

–परिणीति चोपड़ा

ऋतुपर्णो घोष के निधन से इंडस्ट्री सदमें में

नहीं रहे क्रिएटिव फिल्म मेकर

सत्यजीत रे और रबींद्रनाथ टैगोर से प्रभावित ऋतुपर्णो घोष एकमात्र ऐसे फिल्म मेकर थे, जिन्हें 12 नेशनल अवॉर्ड मिला. 49 वर्षीय इस निर्देशक की अचानक मौत से फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में है...

प्रियंका तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

एक अभिनेता, लेखक और बांग्ला फिल्मों के निर्देशक यह पहचान है ऋतुपर्णो घोष की. वह न सिर्फ़ महान फिल्मकार सत्यजित रे के फॉलोअर थे, बल्कि रबींद्रनाथ टैगोर के काफ़ी बड़े प्रशंसक भी थे. वह दोनों के कला प्रेम से प्रभावित थे. यही वजह थी कि ऋतुपर्णो में दोनों कलाकारों की कला की निपुणता देखने को मिल ही जाती थी. उन्होंने रबींद्रनाथ टैगोर की रचना पर फिल्में भी बनाईं. टैगोर की रचना पर आधारित उनकी कुछ फिल्में हैं, चोखेर बाली, नौका डुबी, चित्रांगदा. उन्होंने टैगोर पर जीवन स्मृति नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया. वह अब तक के सबसे ज़्यादा अवॉर्ड विनर निदर्शेक रह चुहे हैं. उन्हें उनकी फिल्मों के लिए अब तक कुल 12 नेशनल अवॉर्ड और कुछ अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. पिछले साल भी बांग्ला फिल्म अबहमान के लिए सर्वश्रेष्ट निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें ही मिला था. उनकी फिल्मों में समाज के लिए कोई मैसेज अवश्य होता था, जो उनकी फिल्मों की ख़ास विशेषता थी. वह व्यावसायिकता की दौड़ में शामिल नहीं थे, बल्कि वह समाज और परिस्थितियों के अनुसार फिल्में बनाते थे. सरल तरीक़े से अपनी बात रखने की कला में उन्हें महारत हासिल था. सरलता और सहजता के साथ गंभीरता से अपनी बात कह देने का ख़ास कौशल उन्हें दूसरों से अलग करती थी. वह बेहतरीन निर्देशक ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे. शोहरत की बुलंदियों को उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही छू लिया था. ऋतुपर्णो घोष की कुछ सफल फिल्में हैं दहन, अशुख, चोखेर बाली, उत्सव, बारीवाली, अंतर महल, और नौका डुबी. दहन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला, जबकि उत्सव के लिए उन्हें जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया.

उनका जन्म 31 अगस्त, 1963 को हुआ था. जादबपुर विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने के बाद, उन्होंने अपना करियर एक एडवर्टिजमेंट एजेंसी में कॉपी राइटर के रूप में शुरू किया. उन्होंने दूरदर्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई. 1992 में उनकी फिल्म हिरेर आंगटि रिलीज हुई. यह बच्चों की फिल्म थी, जो शिर्षेंदु मुखोपाध्याय की रचना पर आधारित थी. 1994 में उनकी दूसरी फिल्म उन्नीसे अप्रिल आई. जहां लोगों को एक नेशनल अवॉर्ड की अदद तलाश रहती है, वहां उनकी दूसरी फिल्म को ही नेशनल अवॉर्ड मिल गया.

ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मौत की वजह सेक्स चेंज ऑपरेशन था. इसके बाद से ही उनकी तबियत ख़राब रहने लगी थी और नींद में ही उनकी मौत हो गई. उनके घरवालों को 30 मई को सुबह सात बजे मौत का पता चला. उनकी मौत पर सभी सन्न थे. वह एक जिंदादिल व्यक्ति थे. मात्र 49 वर्ष की कम उम्र में वह दुनिया छोड़ गए. इस बात पर यकीन नहीं होता. उनकी मौत पर जैसे आसमान भी रो रहा हो. बेमौसम उस दिन जमकर बारिश हुई, लेकिन बारिश आए या तूफान उनके चाहने वाले घंटों उनकी आखिरी एक झलक पाने के लिए इंतजार करते रहे. फिल्म इंडस्ट्री के हजारों लोगों, सैफो फॉर इक्वैलिटी के सदस्यों समेत एलजीबीटी (लेस्बियन, समलैंगिक, द्विलिंगी और ट्रांसजेंडरों) के लोग भी वहां मौजूद थे. यहां भीड़ को संभालना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऋतुपर्णो के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र चढ़ाया. उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अरूप विश्वास, बॉबी हकीम और ब्रात्य बसु भी थे. सभी की आखें नम थीं. घोष के प्रति सम्मान प्रकट करने और रबींद्रनाथ टैगोर के प्रति उनके अनुराग को देखते हुए टैगोर रचित आगुनेर पारोशमणि जैसी प्रार्थनाएं और शोक–गीत भी बजाए गए.

उन्होंने बच्चन परिवार में सभी के साथ काम किया. अपनी अंग्रेजी फिल्म द लास्ट लियर में उन्होंने अमिताभ को लिया. वहीं अपनी फिल्म सन ग्लास में उन्होंने जया को लिया. फिल्म चोखेर बाली और हिंदी फिल्म रेनकोट में उन्होंने ऐश्वर्या राय को लिया. अभिषेक बच्चन उनकी फिल्म अंतर महल में दिखे. हालांकि हिंदी फिल्मों के दर्शक उन्हें अजय देवगन और ऐश्वर्या राय अभिनीत रेनकोट के लिए ही ज़्यादा जानते हैं. हिंदी फिल्म के दर्शकों के लिए जल्द ही वह खुशखबरी देने वाले थे. वह अजय–करीना को लेकर एक हिंदी फिल्म की तैयारी में थे. उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया. पहली बार वर्ष 2003 में रिलीज़ हुई हिमांशु परीजा द्वारा निर्देशित उड़िया फिल्म कथा दैथिली मा कु में वह दिखाई दिए. उनके माता–पिता दोनों का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से था. सचमुच कला उन्हें विरासत में मिली थी. उनके पिता सुनील घोष एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और पेंटर थे. ■

वह एक पुरुष के शरीर में महिला थे : दीप्ति नवल

वह बेहद सहज इंसान थे और उन्हें अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने में किसी तरह की हिचक नहीं थी. मेमरीज इन मार्च में उनके साथ काम कर चुकी अभिनेत्री दीप्ति नवल कहती हैं कि वह अपने समलैंगिकता को लेकर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे. वह एक पुरुष के शरीर में महिला थे. ऋतुपर्णो ने मुझे बताया कि एक बार अभिषेक ने उन्हें ऋतु दा नहीं, ऋतु दी कहा. यह बताते हुए उनकी आंखों में चमक थी.

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

10 जून-16 जून 2013

www.chauthiduniya.com

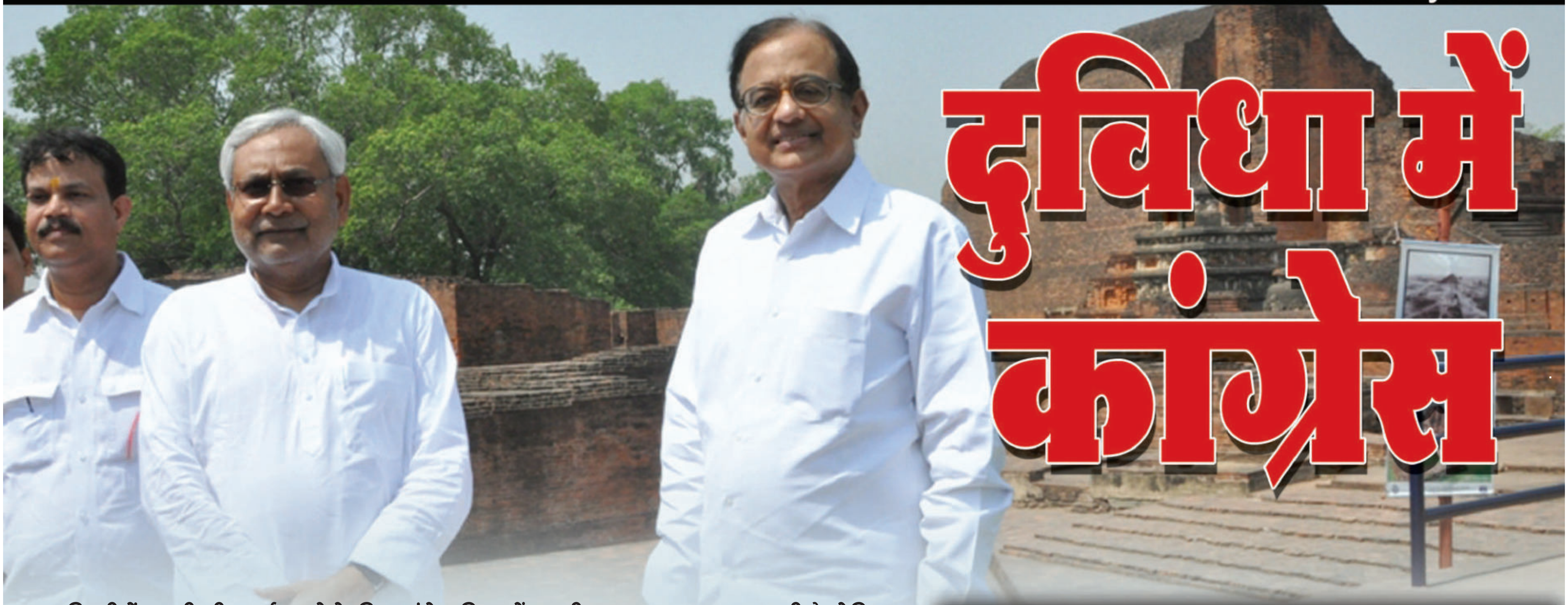

दुविधा में कांग्रेस

दिल्ली में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, लेकिन वह काफ़ी दुविधा में है कि वह अपने पुराने साथी राजद और लोजपा के साथ समझौता करे, नीतीश कुमार के साथ जाए या फिर ख़ुद ही चुनाव लड़े. हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस और जदयू की गतिविधियां देख कर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस और जदयू एक साथ होंगे. इसमें भी समस्या यह है कि जदयू को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर भाजपा का साथ छोड़ना पड़ेगा. दूसरी बात यह भी है कि जदयू अध्यक्ष शरद यादव कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के तालमेल के ख़िलाफ़ हैं...

सरोज सिंह

feedback@chauthiduniya.com

दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए जो राजनीतिक बिसात कांग्रेस बिहार में बिछाना चाहती है, उसमें अगर-मगर के कई पेंचों ने कांग्रेस आलाकमान को दुविधा में डाल दिया है. बिहार में गठबंधन को लेकर कांग्रेस पिछले दो दशक से कई प्रयोग कर चुकी है और इतने लंबे सफ़र के बाद जो रास्ता सामने आया, वह पार्टी को आगे नहीं ले जा सका, बल्कि हुआ यह कि एक सीमित राजनीतिक दायरे में फंस कर कांग्रेस अब भी क़राह रही है. कांग्रेस का मानना यह है कि अब वक्त इससे बाहर निकलने का है. यह कैसे होगा और इसके लिए जो राजनीतिक मोहरे फिट करने हैं, वे कैसे तय होंगे. दिल्ली से लेकर पटना तक इसे लेकर कांग्रेस के नेता पसीना बहा रहे हैं. वजह राहुल गांधी का वह फरमान है, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द एक लाइन तय करने की बात कही है, वह भी इस शर्त के साथ कि किसी भी हालत में इस बार निशाना चुकना नहीं चाहिए. यही वजह है कि कांग्रेस इस बार हर एक विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तीन रास्ते कांग्रेस के सामने हैं. पहला, वह अपने पुराने सहयोगी यानी कि राजद एवं लोजपा के साथ सीटों का सम्मानजनक समझौता करे, दूसरा विकल्प नीतीश कुमार के साथ सीटों का तालमेल है और तीसरा अकेले मैदान में कूदने का विकल्प है, लेकिन इन तीनों विकल्पों में इतने पेंच हैं कि कांग्रेस फिलहाल दुविधा में फंसी नज़र आ रही है. लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान के साथ कांग्रेस पहले भी चुनाव लड़ चुकी है. लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान को भी कांग्रेस का साथ भाता है. नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के ख़िलाफ़ आक्रामक हमला बोलने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन दोनों नेताओं की ज़रूरत है. इसके अलावा, चुनाव के बाद यूपीए अगर सरकार बनाती है, तो फिर इन नेताओं को सत्ता का स्वाद चखने का मौक़ा भी मिलेगा. कांग्रेस भी जानती है कि लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान चूंकि धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, इसलिए उनके लिए यूपीए में रहना ही श्रेयष्कर होगा, लेकिन अपने पिछले अनुभवों को लेकर कांग्रेस हिचक रही है. एक तरह का गुस्सा तो यहां यह भी है कि 2009 के चुनाव में राजद एवं लोजपा ने गठबंधन पर एकतरफ़ा फ़ैसला ले लिया था. दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर लालू प्रसाद के साथ चुनाव में उतरने का फ़ैसला किया गया, तो नए वोटरों का पूरा साथ पार्टी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि युवा वोटर लालू प्रसाद को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. एक और पेंच यह है कि कांग्रेस इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. ऐसे में कोई सम्मानजनक समझौता हो पाएगा, इसे लेकर शंका जताई जा रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे उत्साहजनक बात यह है कि लालू एवं पासवान इस बार किसी भी हाल में केंद्र की सत्ता में भागीदार बनना चाहते हैं. पांच साल सत्ता से दूर रहने का दर्द उनके चेहरे पर साफ़ पढ़ा जा सकता है. ऐसे में हो सकता है कि सीट बंटवारे में लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान अपना दिल कुछ बड़ा कर लें. कांग्रेस के लिए एक रास्ता नीतीश कुमार के पास से भी गुजरता है. यह तब संभव है, जब जदयू एवं भाजपा की राह अलग हो जाए. हालात कुछ ऐसे बन भी रहे हैं और नीतीश कुमार इस हालात का पूरा फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं. उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की शर्त रखकर कांग्रेस को पहल करने का मौक़ा दिया है और कांग्रेस ने भी बिना समय गंवाए, इस पर विचार करने के लिए कमिटी का गठन कर दिया. कमिटी में नीतीश कुमार के ख़ास लोगों को भी सदस्य बनाया गया है. कांग्रेस यह मान रही है कि अगर नीतीश कुमार के साथ चुनाव से पहले तालमेल हो जाए, तो उसे कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं और बिहार से कुछ ज़्यादा सीटें यूपीए के खाते में जा सकती हैं. कांग्रेस लालू की तुलना में नीतीश कुमार की छवि को बेहतर मान रही है, लेकिन इसमें पेंच यह है कि जदयू के अध्यक्ष शरद यादव कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के तालमेल के ख़िलाफ़ हैं. इसलिए जदयू के कुछ रणनीतिकार यह सोच रहे हैं कि विशेष राज्य के शर्त पर चुनाव बाद कांग्रेस को सहयोग दिया जाए, भले ही सरकार को बाहर से समर्थन देना पड़े. बिहार के हित के नाम पर यह क़दम किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और जनादेश का अपमान भी नहीं होगा. सबसे बड़ी बात यह होगी कि पार्टी में विवाद की गुंजाइश नहीं बचेगी. अगर चुनाव के पहले तालमेल का कोई रास्ता नहीं निकला, तो जदयू एवं कांग्रेस नेता इस विकल्प को अमलीजामा पहना सकते हैं. पिछले दिनों जब पी चिदंबरम पटना आए थे, तो नीतीश कुमार ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था. राजगीर से दोनों नेता एक ही कार में पटना तक आए और नीतीश कुमार ने चिदंबरम को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के गेट तक छोड़ने का शिष्टाचार निभाया था. इससे यह लगता है कि कांग्रेस एवं नीतीश कुमार कुछ शर्तों के साथ भविष्य में एक रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन इस पर सारी कवायद भाजपा के अलग होने के बाद ही शुरू होगी. तीसरे विकल्प के तौर पर कांग्रेस अकेले चुनावी अखाड़े में आ सकती है, लेकिन इससे इस चुनाव में पार्टी को कोई ख़ास चुनावी लाभ मिलने की संभावना कम ही दिख रही है. चूंकि संगठन और भरोसे के स्तर पर सुबे में कांग्रेस काफ़ी कमजोर है, इसलिए पार्टी इस विकल्प को अंतिम रास्ते के तौर पर देख रही है. कांग्रेस लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीट बिहार से चाहती है, इसलिए वह इस बार ठोक-बजा कर ही कोई फ़ैसला लेगी. प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी कहते हैं कि हमने सारी बातें पार्टी नेतृत्व को बता दी हैं, ऐसे में आलाकमान को ही तालमेल या गठबंधन आदि पर फ़ैसला लेना है. मतलब साफ़ है कि दुविधा हर विकल्प में है. अब यह कांग्रेस आलाकमान पर है कि कितनी जल्दी वह इस दुविधा से बाहर आकर ज़मीन पर अपनी ताक़त को बढ़ाता है. चूंकि यही मौक़ा है कि कांग्रेस, प्रदेश में अपनी पुरानी पहचान वापस ले आए, नहीं तो फिर पार्टी को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा. ■

रामेश्वर दास केडिया होम्योपैथिक कॉलेज

अधर में छात्रों का भविष्य

जदयू सरकार ने हर तरफ़ लूट मचा रखी है. अब छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है. चंपारण के इकलौते रामेश्वर दास केडिया होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. यहां छात्रों का शुल्क देने के नाम पर आर्थिक दोहन किया जाता है और विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी जाती है. क्या कहती है यह विशेष रिपोर्ट...

इंतेज़ारुल हक़

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी-मुजफ्फरपुर मार्ग के एनएच 28 पर बरियारपुर के निकट स्थित चंपारण का इकलौता रामेश्वर दास केडिया होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन दिनों भ्रष्टाचार एवं प्रबंधन की आपसी गुटबाज़ी के कारण सुर्खियों में है. यहां खुलेआम मेडिकल काउंसिल के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. इस महाविद्यालय में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं का जहां एक तरफ़ शिक्षा शुल्क के नाम पर आर्थिक दोहन किया जाता है, वहीं इसका विरोध करने वाले छात्रों को प्राचार्य द्वारा तरह-तरह की धमकियां भी दी जाती हैं. उन्हें झूठे मुक़दमों में भी फंसा दिया जाता है, इसे देखकर किसी छात्र की हिम्मत नहीं होती कि वह विरोध कर पाए. आरोप यह भी है कि बीते दिनों महाविद्यालय के प्राचार्य वीरेंद्र कुमार प्रसाद द्वारा परीक्षा शुल्क के नाम पर 835 रुपये के बदले दो हज़ार एवं उपस्थिति दर्ज कराने के नाम पर पंद्रह हज़ार रुपये प्रति छात्र मांगी गई. जब छात्रों एवं महाविद्यालय के कुछ शिक्षकों ने इसका जमकर विरोध किया, तो उन पर महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने एवं उत्पात मचाने के आरोप में छतौनी थाना में मुक़दमा दायर (कांड संख्या 86/013) कर दिया गया. इसकी शिकायत छात्रों ने जिलाधिकारी विनय कुमार से करने के साथ ही प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकला. महाविद्यालय के भानू प्रताप सिंह, प्रदीप कुमार, रंजन पांडेय, वेणू प्रकाश, सुस्मिता, प्रशांत कुमार, संतोष कुमार, बीके सिन्हा, गौतम कुमार, रानी बंदना, निशात प्रवीण, कविता, नेहा, कुमारी मोनिका, अमित कुमार श्रीवास्तव समेत 52 छात्रों ने अवैध उगाही का आरोप प्राचार्य पर लगाया है. वहीं, दूसरी तरफ़ महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. ईश्वर चंद्र सिद्ध भी महाविद्यालय की इस रवैये पर सवाल खड़े कर चुके हैं और महाविद्यालय कोष में जमा राशि की अवैध निकासी का मामला (कांड संख्या 82/013) भी छतौनी थाना में 23 अप्रैल को दर्ज करा चुके हैं. उन्होंने महाविद्यालय के ट्रस्ट के दस्तावेजों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि महाविद्यालय कोष की राशि की निकासी के लिए अध्यक्ष एवं सचिव या कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के सचिव नारायण प्रसाद अग्रवाल, प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार प्रसाद, लिपिक रामप्रकाश पंडित एवं लेखपाल सिद्धार्थ प्रकाश की मिलीभगत से लाखों रुपये की निकासी कर राशि का गबन कर लिया गया है. डॉ. सिद्ध के अनुसार, राशि की निकासी के लिए सचिव एवं प्राचार्य के हस्ताक्षर मान्य नही हैं. उन्होंने भी छात्रों से शुल्क के नाम पर अधिक राशि वसुलने एवं कोई रसीद देने के बजाए सादे काग़ज़ पर लिख कर देने के मामले को सही क़रार दिया है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि रसीद मांगने वाले छात्रों को यहां तरह-तरह की धमकियां भी दी जाती हैं. कुल मिलाकर यह महाविद्यालय एवं अस्पताल भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र बना हुआ है और बेरोक-टोक छात्रों का आर्थिक दोहन किया जाता है. कॉलेज प्रशासन की इस रवैये से एक तरफ़ जहां छात्रों का भविष्य अधर में है, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया है. इस बीच महाविद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार प्रसाद ने पूछे जाने पर सभी आरोपों को बेबुनियाद क़रार दिया और बताया कि साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. दूसरी तरफ़ महिला पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष किरण शर्मा, नगर महिला प्रभारी कुमारी चिंता रानी, महिला प्रभारी तारा देवी एवं सुनीता देवी ने भी कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने एवं उनके आर्थिक दोहन का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से इस बात की शिकायत की और इस मामले की जांच अपने स्तर से करने एवं दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की है. ■

स्थापनाकाल से ही संस्था की ओर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाने लगा. इससे ज़िला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चर्चित पुपरी को पहचान मिली.

कंपनी के कई कर्मियों का लेवी के लिए नक्सलियों ने अपहरण किया. भारी वाहनों के फूंके जाने से कंपनी को अब तक करोड़ों का नुक़सान भी हो चुका है.

» एक नज़र «

जूही बनीं टॉपर

जिनमें प्रतिभा है, उन्हें बस प्रोत्साहन की ज़रूरत है. अगर उन्हें बेहतर मार्गदर्शन मिले, तो निश्चित तौर पर वे समाज में कोई मुकाम हासिल करने में सफल होंगे. इस उक्ति को शिवम क्लासेज, कुर्जी दीघा (पटना) में पढ़ने वाले पिछड़े इलाके के ग़रीब, दलित एवं अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं ने सही साबित किया है. तभी तो उक्त शिक्षण संस्थान के छात्र-छात्राओं ने इंटर साइंस-2013 की परीक्षा में शत-प्रतिशत प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करते हुए अपना परचम लहराया है. इस संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि इंटर साइंस 2013 बॉयलॉजी की बिहार टॉपर जूही भी इसी शिक्षण संस्थान की छात्रा है. प्रतिभा सम्मान समारोह 2013 का धूम-धाम के साथ आयोजन करते हुए जूही सहित सभी सफल छात्र-छात्राओं को ट्रॉफी मेडल किताब, कलम, फाइल, प्रमाण पत्र देकर संस्था के निदेशक एवं महंत हनुमान शरण कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बिमल नारायण आर्य, प्रसिद्ध कथाकार एवं मोटिवेटर डॉ. लालजी प्रसाद सिंह के कर-कमलों द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया. *– फ़रहाना आलमगीर*

योजना में लूट

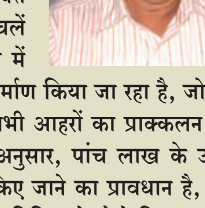

चतरा भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा योजनाओं की राशि में लूट का एक नया इतिहास रचा गया है. सांसद नामधारी ने उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश चतरा उपायुक्त मनोज कुमार को दिया है. बताते चलें कि इस विभाग द्वारा चतरा ज़िले में दस आहर (एकत्रित पानी) का निर्माण किया जा रहा है, जो लाभुक समिति द्वारा करवाया जाना है. सभी आहरों का प्राक्कलन लगभग बीस लाख रुपये है. सांसद के अनुसार, पांच लाख के ऊपर की योजनाओं को निविदा के तहत किए जाने का प्रावधान है, तो फिर इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट बिना निविदा के कैसे किया गया. इसी प्रकार भूमि संरक्षण विभाग चतरा द्वारा वर्ष 2008-09 में बिना काम के कई कूपों का निर्माण पूर्ण काग़ज़ पर किया जा चुका है. इसका ख़ुलासा भी सांसद ने किया. हंटरगंज प्रखंड में 20 फीट व्यास के कूप का निर्माण डुमरीकला में ओम प्रकाश साह के नाम से किया गया है, लेकिन गौरतलब है कि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है. इस तरह की लूट के यहां कई उदाहरण हैं.

दलालों के सहारे आंगनबाड़ी

चतरा ज़िले के विभागों में भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों का राज कायम है. यहां के समुल प्रतापपुर प्रखंड में बाल विकास परियोजना कार्यालय में एक दलाल शिव कुमार लाल है. लाल का पिछले 20 वर्षों से एकछत्र राज चल रहा है. दरअसल, उनके आगे किसी की भी नहीं चलती. प्रतापपुर प्रखंड के ज़िला परिषद सदस्या, भाग दो की रीना देवी बताती हैं कि यहां एक दलाल की चलती है. इस प्रखंड में दो सुपरवाइजर भी कार्यरत हैं, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी या कर्मचारी इस प्रखंड में काम नहीं कर सकते हैं. प्रति केंद्र पंद्रह सौ से दो हज़ार तक वसूली किया जाता है. रीना देवी ने प्रतापपुर प्रखंड में दलालों द्वारा भयदोहन किए जाने की लिखित सूचना चतरा उपायुक्त को दिया है. *– अमरेंद्र प्रताप सिंह*

अग्रणी इंफ्रा की दो नई स्कीम

अग्रणी इंफ्रा ने अपने नए वुड प्रोजेक्ट की प्री-लांचिंग के साथ दो नई स्कीम भी लांच की. कंपनी के सीएमडी शिव कुमार एवं ब्रांड एंबेसडर शेखर सुमन ने कहा कि अग्रणी इंफ्रा रियल गेन एवं अग्रणी इंफ्रा रॉयल मेंबरशिप आकर्षक योजनाएं हैं. प्रोजेक्ट में न्यूनतम निवेश की राशि 10 लाख रुपये हैं, जिसमें बाज़ार से 20 प्रतिशत कम पर भूखंड उपलब्ध होगा. सदस्य बनने पर 5 प्रतिशत अलग से छूट मिलेगी. आईआईटी के ठीक पीछे बन रही इस टाउनशिप में प्रि-लांचिंग के दौरान सिर्फ़ 241 प्लॉट ही बेचे जाएंगे. वुड प्रोजेक्ट विकसित फॉर्म हाउस के साथ 225 एकड़ के क्षेत्र में टाउनशिप की स्थापना करेगी. इसमें डिलक्स बंगला, बड़े-बड़े बंगलों, बड़े-बड़े विकसित प्लॉट, प्लॉट मॉल वाटर पार्क, फुड कोर्ट, एंटरटेनमेंट पार्क, कन्वेंशन हॉल जैसी सुविधाएं मिलेंगी. पूरे क्षेत्र में डेवलपर्स ख़ुद दो क्लब हाउस, मंदिर, प्राइमरी स्कूल, हेल्थ सेंटर एवं मेडिटेशन सेंटर बनवाएंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बूंद बूंद को तरसते रोहतासवासी

रोहतास ज़िले में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, प्रशासन जनता की समस्याओं से आंख बंद किए बैठी है. कब लेगी सुध प्रशासन?

ममता चौहान feedback@chauthiduniya.com

रोहतास ज़िला इन दिनों पेयजल की भारी संकट से जूझ रहा है. कैमूर पहाड़ी से लेकर मैदानी भाग तक लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. यहां के लोग सोन नदी का पानी पीकर जी रहे हैं. प्रशासन यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में भी नाक़ाम साबित हो रही है. दुख की बात यह है कि इस समस्या को लेकर सत्ताधारी और विरोधी दल दोनों राजनीति करने में व्यस्त हैं. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2009 की भीषण गर्मी में तापमान 50 डिग्री के आसपास जा पहुंचा था और पानी के लिए लोग तड़प रहे थे. उस वर्ष अकेले कैमूर पहाड़ी पर पांच हज़ार से ज़्यादा मवेशी पानी के अभाव में तड़प-तड़प कर मर गए थे. इस वर्ष भी मई के बीच में ही रोहतास ज़िले का तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है. कैमूर पहाड़ी और उसके आसपास बसे 139 गांवों के लोग धीरे-धीरे पानी के स्रोतों की ओर पलायन करने लगे हैं.

इधर, मैदानी भाग में जल स्तर का तेज़ी से नीचे खिसकना पेयजल के लिए बहुत बड़े ख़तरे की सूचना है. ज़िले के दौरे पर पहुंची लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी रोहतास ज़िले की पेयजल समस्या को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है. सासाराम के तीन, करगहर, कोचस और परसथुआ के तीन, डेहरी के दो और विक्रमगंज के लगभग एक दर्जन जल मीनार महीनों से बंद पड़े हैं. यह समस्या यहां हर वर्ष की है, लेकिन प्रशासन इससे सबक नहीं लेती और पहले से कोई तैयारी भी नहीं करती. आधी गर्मी बीत जाने के बाद प्रशासन को अब यहां के लोगों की सुध आई है. अब कहीं चापाकलों की मरम्मत का काम शुरू हुआ है, तो कहीं नए चापाकल लगाए जाने लगे हैं. हद तो तब हो गई, जब पानी की कमी के बीच प्रशासन ने एक ऐसा हास्यास्पद अभियान चला दिया, जिसमें जांच शुरू हुई कि सासाराम में कहां-कहां लोग अवैध कनेक्शन के साथ पानी का उपयोग कर रहे हैं.

लगे हाथ उन्हें पकड़कर कार्रवाई भी की जाने लगी. इस पर यहां के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि अपनी कमी को छुपाने के लिए प्रशासन अब इस स्तर पर उतारू है. एक तरफ़ लोग पानी के लिए छटपटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंतजाम की बात तो दूर, बल्कि लोगों को इससे वंचित करने का प्रयास भी किया जा रहा है. प्रशासन के इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ राजद के प्रदेश महासचिव ललन पासवान, भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद और भाजपा विधायक रामेश्वर प्रसाद चौरसिया प्रदर्शन कर रहे हैं. ■

पुपरी को स्टेडियम का इंतज़ार

... लेकिन वादे हैं, वादों का क्या

पुपरी अनुमंडल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज तक इस अनुमंडल को एक स्टेडियम भी मयस्सर नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ख़ुद वर्ष 2009 में यहां स्टेडियम बनाने का भरोसा दिलाया था. हालांकि उनके वायदे कोरे ही साबित हुए हैं. क्या है वायदों का सच?..

गोविंद कुमार feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी ज़िले में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में पुपरी अनुमंडल मुख्यालय की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है. यहां खेल कोटे से अब तक दर्जनों खिलाड़ी विभिन्न सरकारी सेवाओं में लग चुके हैं. इनमें संजीव कुमार झा, अभय कुमार मिश्र, संतोष कुमार ठाकुर, संजय कुमार, यतेंद्र कुमार द्विवेदी, मो. सईद, कैसर आलम, अरविंद कुमार सिंह एवं अतुल कुमार समेत कुछ और लोग भी शामिल हैं. लेकिन दुखद यह है कि अब तक पुपरी में एक स्टेडियम तक नहीं बन पाया है. अनुमंडल क्षेत्र में खेल प्रतिभा के विकास को लेकर 19 अप्रैल, 1989 को राजबाग युवा संस्थान की स्थापना की गई. स्थापनाकाल से ही संस्था की ओर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाने लगा. इससे ज़िला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चर्चित पुपरी को पहचान मिली. संस्थान की टीम में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट एवं भारोत्तोलन में बेहतर प्रदर्शन की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम नहीं होने के कारण विभिन्न खेलों के बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए दैनिक अभ्यास एक गंभीर चुनौती है. यहां कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां सभी अपने अभ्यास को गति दे सकें.

पिछले क़रीब डेढ़ दशक से संस्थान अनुमंडल मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण को लेकर प्रयासरत है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार ही नहीं है. प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं में मशगूल हैं, तो जनप्रतिनिधि राजनीति का झंडा बुलंद करने में व्यस्त हैं.सच तो यह है कि किसी को भी खेल प्रतिभाओं के विकास की परवाह ही नहीं है. वर्ष 2009 में विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुपरी में आगमन हुआ, तो खिलाड़ियों में कुछ उम्मीद जगी, क्योंकि ख़ुद मुख्यमंत्री ने पुपरी में सटेडियम निर्माण कराने का भरोसा खिलाड़ियों को दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा सकी है. नतीजतन, अब खिलाड़ियों का विश्वास दम तोड़ने लगा है. अनुमंडल समेत सीतामढ़ी ज़िले में खेल प्रतिभा के विकास को लेकर उक्त संस्थान ने स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य है सभी आयु वर्ग के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना. इसके अलावा नि:शुल्क प्रशिक्षण के साथ आवश्यक संसाधन मुहैया कराना भी लक्ष्य में शामिल किया गया है.

प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं में मशगूल हैं, तो जन प्रतिनिधि राजनीति का झंडा बुलंद करने में व्यस्त हैं. सच तो यह है कि किसी को भी खेल प्रतिभाओं के विकास की परवाह ही नहीं है. वर्ष 2009 में विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुपरी में आगमन हुआ, तो खिलाड़ियों में कुछ उम्मीद जगी

अब सबकी नज़र मुख्यमंत्री की अब तक साबित हो चुकी हवा-हवाई घोषणा पर टिकी है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल प्रतिभाओं के विकास को तरजीह देते हैं या चुनावी मंच से एक बार फिर पुरानी राग अलाप कर निकल जाते हैं. ■

अधर में डुमरिया-पटना सड़क निर्माण

डकार गए 313 करोड़ रुपये

गया ज़िले में घोर नक्सल प्रभावित डुमरिया से पटना तक सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2009 में सरकार ने 313 करोड़ रुपये का ठेका गैमन इंडिया कंपनी को दिया, लेकिन नक्सलियों के आतंक के कारण गैमन इंडिया यह कार्य पूरा नहीं कर पाई. आख़िर क्यों सरकार बिहार के विकास के लिए कंपनियों को उचित माहौल मुहैया कराने में असमर्थ साबित हो रही है? क्या है, पर्दे के पीछे का सच?

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

गया ज़िले के घोर नक्सल प्रभावित डुमरिया से पटना (रनिया तालाब) तक बनने वाली 153 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को जैसे ग्रहण लग गया है, क्योंकि यहां चार साल में अभी तक पचास फ़ीसदी काम भी नहीं हो पाया है. 313 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण कार्य जनवरी 2009 में शुरू हुआ था और इसका ठेका गैमन इंडिया कंपनी को दिया गया था, लेकिन गैमन इंडिया समय पर कार्य नहीं कर पाई. इसके एवज में कंपनी ने पांच करोड़ रुपये जुर्माना भी दिया, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है. चार सालों में गैमन इंडिया को यह सड़क बनाने के दौरान लेवी नहीं देने के कारण नक्सली संगठनों का अनेक बार शिकार होना पड़ा. सड़क निर्माण कार्य में लगे दर्जनों वाहनों को नक्सलियों ने चार साल के दौरान फूंक डाला. सच तो यह है कि कंपनी के कई कर्मियों का लेवी के लिए नक्सलियों ने अपहरण भी किया. भारी वाहनों के फूंके जाने से कंपनी को अब तक करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है.

डुमरिया से गया ज़िले के शेरघाटी तक 60 किलोमीटर लंबी सड़क इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. दरअसल, यहीं से काफ़ी समय से जदयू के उदय नारायण चौधरी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं. कहा जाता है कि वह नक्सली क्षेत्र में कई बार हमले कर अब तक दर्जन भर सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार चुके हैं. राज्य सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में सबसे बड़े बाधक नक्सली ही हैं. सरकार चाहती तो पर्याप्त सुरक्षा देकर इस महत्वाकांक्षी सड़क का निर्माण कार्य पूरा करा सकती थी, लेकिन इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक पेंच भी है. नक्सलियों को या फिर नक्सली संगठनों को किसी न किसी रूप में राजनीतिक संरक्षण ज़रूर प्राप्त है, तभी नक्सली इस सड़क निर्माण कार्य को बाधित कर रहे हैं. इस सड़क पर दो बार नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाकर विस्फोट करने का प्रयास भी किया. हालांकि संयोग से दोनों बार विस्फोट नहीं हो पाया और सड़क का विशेष नुक़सान होने से बच गया.

वर्ष 2009 में जब डुमरिया से पटना रनिया तालाब तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो घोर नक्सल प्रभावित और पिछड़े शेरघाटी अनुमंडल के लोगों को बहुत खुशी हुई थी. मालूम हो कि डुमरिया से राजधानी पटना की यात्रा मात्र ढाई-तीन घंटे में पूरी होने की बात से ही लोग रोमांचित हो उठे थे, लेकिन चार साल गुजर जाने के बाद भी इस क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा नहीं हो सका. डुमरिया से इमामगंज के बीच इस सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है. आने वाले बरसात के मौसम में डुमरिया का यातायात संपर्क भंग हो जाने की संभावना है. पिछले बरसात में भी डुमरिया के लोगों को इस सड़क के जर्जर रहने के कारण काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी. दरअसल, आम दिनों में भी इस सड़क पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. डुमरिया से इमामगंज तक लोग भगवान भरोसे ही यात्रा करते हैं. डुमरिया से शेरघाटी तक 60 किलोमीटर तक में पुल-पुलिया के निर्माण के लिए 72 डायवर्जन अप्रोच को कच्चा छोड़ दिया गया है. गुरारू से अहियापुर तक 13 किलोमीटर सड़क की हालत बहुत ख़राब है. सड़क कच्ची होने के कारण नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंगों के प्लांट किए जाने की संभावना भी अधिक बनी रहती है. सच तो यह है कि डुमरिया से पटना के रनिया तालाब तक जाने वाली यह सड़क बरसात में चलने के काबिल भी नहीं रह जाएगी. अब आप सोच सकते हैं कि नक्सल प्रभावित दक्षिण बिहार के इलाक़े को राजधानी पटना से जोड़ने वाली 153 किलोमीटर राज्य के इस महत्वाकांक्षी सड़क (प्रोजेक्ट) की जब यह स्थिति है, तो नक्सल क्षेत्रों की अन्य सड़कों का हाल क्या होगा? वह भी तब, जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी करते हैं. दरअसल, इस क्षेत्र में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है, इसलिए सरकार के लाख चाहने के बाद भी इस क्षेत्र के लोग नक्सलियों के रहम ओ-करम पर जीते हैं. ■

» एक नज़र «

एकता परिषद का धरना

रामगढ़वा प्रखंड परिसर के समक्ष एकता परिषद के बैनर तले भूमिहीनों ने धरना दिया और सरकार की जनविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की. घर बनाने के लिए 10 डिस्मिल ज़मीन देने समेत अपनी अन्य आठ सूची मांगों को लेकर आयोजित धरने पर परिषद के सैकड़ों महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता क़रीब एक सप्ताह तक डटे रहे. मौक़े पर परिषद के सचिव नंदलाल प्रसाद, संयोजक ईमरान आलम, हरिशंकर सिंह, मनोज साहनी, राम आशिष बैठा, राधा देवी, शांति देवी, कृष्णावती देवी, मीना सिंह, बद्री साह तथा रामाश्रय पासवान सहित कुछ और लोग शामिल थे. *– डीएन कुशवाहा*

टॉपर बनीं अपराजिता

कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो.......इसे चरितार्थ किया है. सीबीएसई प्लस टू की वार्षिक परीक्षा में नरकटियागंज की अपराजिता कुमारी ने. पिता प्रभू प्रसाद वर्णवाल की मृत्यु के बाद से अपराजिता को उसके दो भाइयों आविष्कार एवं अनुज का प्यार मिलता रहा. उसकी प्रतिभा को पहचाना शिक्षक नवीन कुमार श्रीवास्तव ने. अपराजिता ने जवाहर नवोदय वृंदावन की प्रतियोगिता परीक्षा पास कर नामांकन कराया, फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. उसने सीबीएसई 2013 की प्लस टू परीक्षा में टॉप किया. यहां के लोग अपराजिता की इस सफ़लता से काफ़ी खुश हैं कि उसने पश्चिमी चंपारण का नाम रोशन किया. नरकटियागंज नया टोला प्रकाश नगर निवासी अपराजिता ने बताया कि उसका लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना है. *– अवधेश शर्मा*

राष्ट्रीय मंत्री बनने पर बधाई

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मोतिहारी निवासी अब्दुल रहमान को अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर ज़िले के भाजपा नेताओं में हर्ष है. रहमान के मनोनयन पर पार्टी नेताओं ने कहा कि उनके संगठन को मजबूती प्राप्त होगी. साथ ही अल्पसंख्यकों में पार्टी के प्रति आस्था भी बढ़ेगी. बधाई देने वालों में सांसद राधामोहन सिंह, रमा देवी, डॉ. संजय जायसवाल, विधायक रामचंद्र साहनी, अवनिश कुमार सिंह, डॉ. अजय सिंह, प्रमोद कुमार, कृष्णनंदन पासवान, सचींद्र सिंह, राजेंद्र गुप्ता, सुनील मणि तिवारी, पं. चंद्र किशोर मिश्र, रामलोचन यादव, अखिलेश कुमार सिंह, श्याम बाबू यादव, प्रमोद शंकर सिंह, अनिल राय, डॉ. लालबाबू प्रसाद, बसंत मिश्रा, राजा ठाकुर, सुभाष कुशवाहा, ई. चंद्रिका जायसवाल, संगीता चित्रांश, मनोज पासवान, प्रकाश अस्थाना, निर्मला साहनी, विंटी शर्मा, सुनील वर्मा, अमित तिवारी, गणेश कुमार सिंह, संध्या चौधरी, ध्रुव प्रसाद, मो. कलाम, रेयाज मुस्तफा, विवेकानंद पांडेय, आनंद सिंह, सूर्यदेव राम, पवन राज, नुर आलम सैफी, संजय चौधरी, योगेंद्र प्रसाद, हरजीत सिंह, बसंत सिंह, पप्पू पांडेय, अरुण कुशवाहा, नीतीश्वर सिंह, विजय गुप्ता, प्रभावती देवी, प्रमोद गिरी, वसीम आलम, अवध पटेल, हरिदयाल कुशवाहा समेत अन्य नेता शामिल थे. *– इंतेज़ारुल हक़*

शिक्षक एवं शिक्षिका का नियोजन रद्द

गोगरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय इमादपुर लतामबाड़ी में कार्यरत शिक्षक राजीव कुमार एवं शिक्षिका रूबी कुमारी के नियोजन को जिला शिक्षक नियोजन प्राधिकार खगड़िया ने अवैध क़रार दे दिया है. साथ ही विद्यालय शिक्षा विभाग के आदेश से नियोजन रद्द करने का आदेश दे दिया गया है. पंचायत के मुखिया वकील प्रसाद यादव ने बताया कि विद्यालय की स्थापना के पूर्व ही निवर्तमान उपमुखिया के मिलीभगत से शिक्षक एवं शिक्षिका विद्यालय नियोजन का दावा कर रहे थे. मामले की जांच कर शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार ने शिक्षक राजीव कुमार एवं शिक्षिका रूबी कुमारी का नियोजन रद्द कर दिया है.

योजना में धांधली

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में टैक्स दरोगा के पद पर कार्यरत गोपीनाथ पांडे उर्फ मुन्ना पांडे एवं बिचौलियों की मिलीभगत से वार्ड नं.-14 के गणेश कुमार साह और नरेश सिंह समेत तीन जीवित लोगों को मृत घोषित कर कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि की निकासी कर बंदरबांट किया गया है. भाजपा की ज़िला मंत्री रत्नमाला देवी ने बताया कि नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में भ्रष्टाचार का बोल-बाला है, यहां जीवित व्यक्ति को मृत कर सरकारी राशि का निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाता है. वैसे, मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई है.

अवैध उगाही

अनुमंडल गोगरी सेवा के अधिकार काउंटर पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र मुहैया कराने के नाम पर अवैध राशि की मांग की जा रही है. राज किशोर कुमार, दीपक कुमार, शेषमणी कुमार, नंदन कुमार एवं पवन कुमार समेत अन्य छात्रों ने बताया कि अनुमंडल के आरटीपीएस काउंटर पर उपस्थित युगेश नाम के कर्मी पंजी पर जाति एवं आवास का क्रमांक अंकित करने के लिए अवैध राशि की मांग करते हैं और पैसा नहीं देने पर काउंटर से लोगों को भगा दिया जाता है. ■ *– उधव कुमार*

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

शॉर्ट न्यूज़

शिविर का आयोजन

गोगरी अनुमंडल के पीएल शिक्षा निकेतन मथुरापुर में स्वास्थ्य जांच सह जागरूकता शिविर के तहत लगभग दो सौ बच्चों के दांतों को जांच कर उनके बीच ब्रश एवं टुथपेस्ट वितरित किया गया. मौक़े पर विद्यालय के संस्थापक ई. दिवाकर झा, डॉ. जेपी यादव, डॉ. नूतन आनंद, डॉ. दीपक, प्रबंध निदेशक पुष्पलता झा एवं प्राचार्य डीके झा समेत दर्जनों बच्चे उपस्थित थे.

राशि का वितरण

गोगरी के मदरसा नुरूल उलूम गोगरी में मुख्यमंत्री बालक-बालिका साइकिल एवं पोशाक राशि योजना के अंतर्गत प्रधानाध्यापक मो. जरीउद्दीन कासमी के नेतृत्व में 96 छात्र और 187 छात्राओं के बीच पच्चीस सौ रुपये की दर से 7 लाख, 7 हजार एवं 5 सौ एवं नवम वर्ग के 187, दसम वर्ग के 157 छात्राओं के बीच एक-एक हज़ार रुपये की दर से 34 हज़ार, 4 सौ रुपये की राशि का वितरण किया गया. मौक़े पर मो. काजी अरशद मौलाना, सौम्या खातून, आयशा प्रवीण, रुखसाना खातून, अब्दुल रहमान, सोहेब आलम सहित दर्जनों शिक्षक एवं छात्र-छात्रा उपस्थित थे. *–उधव कुमार*

पोशाक राशि का वितरण

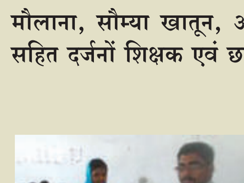

ज़िले के अलौली प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय परिसर में प्रधानाध्यापक मनोज कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक राशि योजना के तहत 205 छात्राओं के बीच 2 लाख, 51 हज़ार राशि का वितरण किया गया. प्रधानाध्यापक कुमार ने कहा कि इस विद्यालय के छात्र एवं छात्रा हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो कर विद्यालय का नाम रोशन करते आए हैं. इस अवसर पर शिक्षक राजेश कुमार, अनील कुमार, पुस्तकालय अध्यक्ष मो. नाजीम हाशमी, रवि कुमार जयंत, प्रवीण कुमार, स्नेहा कुमारी, नेहा कुमारी, दीपशिखा कुमारी, शिल्पी कुमारी, अन्नु कुमारी, अल्का कुमारी, बबीता कुमारी समेत दर्जनों छात्र उपस्थित थे.

प्रतिमा का अनावरण

अलौली प्रखंड अंतर्गत मेघौना पंचायत में पंचायत के पूर्व मुखिया सह कम्युनिष्ट पार्टी के नेता स्व. लक्ष्मी नारायण यादव की प्रतिमा का अनावरण सीपीआईएम के केंद्रीय सचिव मंडल सदस्य हन्नान मोल्ला ने किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है. मौक़े पर उपेंद्र महतो, अशोक कुमार, जगदीश बसु, संजय कुमार एवं हेराम चौधरी समेत दर्जनों सीपीआईएम नेता उपस्थित थे. *– सतीश कुमार*

स्थानीय लोगों को रोजगार

प्रिसटाइन मेगा फुड पार्क में खगड़िया ज़िले के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. उक्त बातें निदेशक प्रेमव्रत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि खगड़िया ज़िले में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर खाने का सामान तैयार किया जाएगा. वहीं आशीष कुमार झा ने बताया कि यहां के किसानों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में लाभ मिलेगा. *– नंद किशोर शर्मा*

सिंचाई की समस्या

सीतामढ़ी ज़िले के रीगा प्रखंड अंतर्गत कुसमारी पंचायत के इफरौलिया गांव में किसानों के लिए सिंचाई की समस्या गंभीर बनी हुई है. लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1982 में निर्मित लिफ्ट एरिगेशन के तहत नलकूप पूर्णत: खराब हालत में पड़ी हुई है. स्थापना काल में तक़रीबन 7 साल तक स्थानीय किसानों को सिंचाई में सहयोग मिला, जिससे क़रीब 1 सौ एकड़ ज़मीन की सिंचाई की जाती थी. वर्ष 1989 के बाद उक्त सुविधा को ग्रहण लगा और धीरे-धीरे सिंचाई परियोजना का उक्त भवन भी खंडहर में तब्दील हो गया. विभागीय उदासीनता एवं प्रशासनिक लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने लगाए गए मशीनरी तक को ग़ायब कर दिया, लेकिन अब तक उक्त योजना को चलाया नहीं जा सका है. किसान अर्जुन राय, पिंकु राय, मुन्हाई दास, पारसनाथ सिंह, राम जनम गिरी, मोहन राम, दिनेश कुमार सिन्हा, राम कैलाश सिंह एवं डॉ. रवींद्र कुमार समेत अन्य ने सरकार एवं प्रशासन से उक्त योजना को पुन: चालू कराने की मांग की है. किसानों ने कहा है कि अगर यह योजना शीघ्र चालू नहीं हुई, तो पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के ख़िलाफ़ आंदोलन किया जाएगा. *– नीरज कुमार*

अनुमंडलीय अस्पताल बदहाल

शिवहर ज़िले में दशकों पूर्व स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर स्थापित अनुमंडलीय अस्पताल अब आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है. आलम यह है कि अस्पताल परिसर में संचालित रक्त संग्रह केंद्र भी अब लोगों को सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहा है. उक्त भवन में फिलहाल जांच कार्य किया जा रहा है. एक्स-रे समेत अन्य सुविधाओं के लिए भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कार्यरत कर्मियों के सेवा कार्य में उपलब्ध नहीं रहने के कारण भी मरीजों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है. ख़ासकर, एक्स-रे के लिए लोग घंटों इंतज़ार करने को विवश हैं. ■ *– हेमंत कुमार*

कैंसर लाईलाज नहीं
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
डॉ अहमद अब्दुल हई
कई बार देखा जाता है कि मरीज अपनी बीमारी के बारे में जान कर हिम्मत हार जाते हैं और जो बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है वह भी काफी भयानक रूप ले लेती है। डॉ. अहमद अब्दुल हई पटना जाने माने सर्जन हैं। डॉ. हई कहते हैं कि है गॉल ब्लाडर कैंसर को अगर शुरूआती दौर में पकड़ लिया जाए तो इससे आसानी से ठीक किया जा सकता है।
गॉल ब्लाडर में गोलस्टोन हटा देने से गॉल ब्लाडर कैंसर से बचा जा सकता है। यह बीमारी खाने के तेल में मिलावट या फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अक्सर बाहर की चीजें खाने से ऐसा होता है। इसलिए बाहर की चीजें खाने से परहेज करें।
कैंसर के लास्ट स्टेज में दर्द बहुत होता है। डा. हई कहते हैं कि मरीज को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट स्टेज आने से पहले ही यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक करा लें।
ASRFEN-P Acedofenac+Paracetamol Serratiopeplidase Tab.
ECTALOPAM Escilalopram oxalate & Clonazepam Tablets
SILIPLEX Silymarin, Vitamin B-Complex & Lactic acid, Calcium, Bacillus Cap/Syp
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma
फरहाना आलमगीर

बालमुकुन्द डायमंड टी.एम.टी. IS:1786
नं01 छड़ बालमुकुन्द
इसमें है दम यही है नम्बर 1
Website : www.balmukundtmt.com
Email : bconcast@yahoo.com
भारत में पहली बार Q & Q कर हर बंडल के साथ

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY शर्तें लागू
Contact : 9386595926, 9334115955

Mahindra powerol Engines & DG sets
powered efficiently
World Class Silent DG Sets
- Zero-Leak engines
- Most fuel efficient in its class
- Manual & AMF Power
- Available on DGS & D Rate Contract
- Range 2.5 kVA to 500kVA
- Finance Available
- 24 x 7 Service
SATYA ENTERPRISES
Land Development Bank Building
Budh Marg, Patna-800001
Mob. : 9431011863
Email : info@satyaenterprises.org; Website : www.satyaenterprises.org

तीनों कुशवाहा यहां कुशवाहा जाति को अपने अपने पाले में करने की कवायद में जुट गए हैं. इसके बाद यादव सहित अन्य जातियों को गोलबंद करने की रणनीति भी ये बना रहे हैं.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

वाल्मीकि कुमार
feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी : भारत के पैसे से चल रहा है, नेपाली एफएम चैनल

कौन करेगा नुक़सान की भरपाई

तक़रीबन ढाई दशक पूर्व सीतामढ़ी में अल्प शक्ति दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता का आलम यह है कि अब तक उक्त केंद्र को अपना भवन भी नहीं मिल सका है. क्या है कारण, पढ़िए चौथी दुनिया की यह रिपोर्ट...

सरकारी राजस्व में बढ़ोत्तरी को लेकर सरकार एवं प्रशासनिक तंत्र कितना सक्रिय है, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है. अब देखिए, तक़रीबन ढाई दशक पूर्व सीतामढ़ी में अल्प शक्ति दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई, लेकिन आश्चर्य कि बात तो यह है कि अब तक उक्त केंद्र को अपना भवन भी नसीब नहीं हो सका है. भारतीय प्रसार निगम के केंद्र प्रसार भारती की हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि येन-केन प्रकारेण संचालन की कवायद पूरी की जा रही है. विभागीय स्तर पर कुल 13 कर्मियों की कमी बताई गई है, लेकिन केंद्र का संचालन महज 7 कर्मियों की बदौलत ही की जा रही है. केंद्र के हालात से विभाग के आलाधिकारी अवगत ज़रूर हैं, लेकिन समुचित कार्रवाई की दिशा में अब तक आवश्यक पहल ही नहीं की जा सकी है. केंद्र की ओर से न केवल मासिक प्रतिवेदन विभागीय अधिकारियों को समय पर भेज कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है, बल्कि समस्या के निदान के लिए गुहार भी लगाई जा रही है, लेकिन केंद्र को बदहाली से निजात दिलाने की दिशा में कोई कारगर पहल अभी तक नहीं गई है.

गौरतलब है कि बाज़ार समिति परिसर में संचालित यह केंद्र वर्षों से कर्मियों की कमी का दंश झेल रहा है. केंद्र में कार्यरत कर्मियों की मानें तो वर्ष 1988 में सीतामढ़ी में अल्प शक्ति दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कराई गई थी. बेल कंपनी के सौ वाट के ट्रांसमीटर की बदौलत केंद्र का संचालन 1989 में शुरू कर दिया गया. क़रीब दो दशक बाद वर्ष 2007 में बाद 5 सौ वाट का ट्रांसमीटर लगाया जा सका, लेकिन ज़िले में आम-अवाम को केंद्र का समुचित लाभ दिलाने को लेकर 10 वाट के ट्रांसमीटर की दरकार बताई जा रही है. ऐसे में केंद्र द्वारा संचालित एफएम चैनल महज यहां दिखावा बन कर रह गया है. बताया गया है कि केंद्र से डीडी-1 के अलावा पटना से रिजनल चैनल का प्रसारण अलग-अलग समयों पर किया जा रहा है. एक ट्रांसमीटर नहीं रहने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है. नतीजतन ज़िले की सीमा में भी सही तरीक़ेसे प्रसारण संभव नहीं हो पा रहा है. इसका लाभ भारत-नेपाल सीमावर्ती नेपाली क्षेत्र में रक्तबीज की भांति खुल रहे एफएम चैनल आसानी से उठा रहे हैं. इसलिए प्रति वर्ष करोड़ों रुपये राजस्व का भारतीय क्षेत्र में जहां नुक़सान हो रहा है, वहीं नेपाली क्षेत्र में एफएम संचालकों की चांदी कट रही है. कार्यरत कर्मियों की मानें, तो सीतामढ़ी प्रसारण केंद्र को अगर अत्याधुनिक संसाधन मुहैया करा दिया जाए, तो भारतीय क्षेत्र में नेपाली एफएम की बजाए जनप्रिय विविध भारती की गूंज ही सुनाई पड़ेगी. साथ ही भारत सरकार को प्रति माह लाखों रुपये राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा. केंद्र के वरीय अभियांत्रिक सहायक एके चौधरी का मानना यह है कि इस वक्त केंद्र का आधुनिकीकरण आवश्यक है.

वर्ष 1998 में पटना से एक टीम भी आई थी, लेकिन उस वक्त केंद्र की स्थापना के लिए महज 3 एकड़ ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो सका था. नतीजतन टीम के सदस्य लौट गए थे. साथ ही सीतामढ़ी के लिए विभागीय स्तर पर स्वीकृत केंद्र का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया. दुख की बात तो यह है कि अब तक इस केंद्र को बदहाली से उबारने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है. केंद्र के संबंध में पूर्व सांसद नवल किशोर राय का कहना है कि वर्ष 1996-97 में सूचना प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रवि शंकर प्रसाद के पास था. काफ़ी प्रयास के बाद एफएम प्रसारण केंद्र की स्वीकृति दिलाई गई. विकास को लेकर भी प्रयास किया गया, लेकिन बाद में हालात बदलने के साथ ही सब कुछ पुराना पड़ गया. बावजूद इसके नवल किशोर राय ने वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी से एक बार फिर मिल कर केंद्र की बदहाली दूर करने के लिए आग्रह किया. वहीं सूबे के पर्यटन मंत्री सह सीतामढ़ी के भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि ज़िला पदाधिकारी से इस संबंध में बात कर जल्द ही आवश्यक पहल की जाएगी. उपलब्ध केंद्र का लाभ ज़िले की जनता को मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.

केंद्र के संबंध में पूर्व सांसद नवल किशोर राय का कहना है कि वर्ष 1996-97 में सूचना प्रसारण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रवि शंकर प्रसाद के पास था. काफ़ी प्रयास के बाद एफएम प्रसारण केंद्र की स्वीकृति दिलाई गई. विकास को लेकर भी प्रयास किया गया, लेकिन बाद में हालात बदलने के साथ ही सब कुछ पुराना पड़ गया. बावजूद इसके नवल किशोर राय ने वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी से एक बार फिर मिल कर केंद्र की बदहाली दूर करने के लिए आग्रह किया. वहीं सूबे के पर्यटन मंत्री सह सीतामढ़ी के भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि ज़िला पदाधिकारी से इस संबंध में बात कर जल्द ही आवश्यक पहल की जाएगी.

इधर, पूर्व सांसद सीताराम यादव का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र की योजना को नक़ारा साबित करने पर तुली है. केंद्र की बदहाली के लिए राज्य सरकार और ज़िला प्रशासन समान रूप से ज़िम्मेदार है. ज़िला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला का कहना है कि राज्य की वर्तमान सरकार की उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही के कारण केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण इकाई दम तोड़ने के क़गार पर पहुंच गई है. शुक्ला ने कहा कि अगर ज़िला प्रशासन ने ज़मीन उपलब्ध कराया होता, तो आज प्रसारण केंद्र की स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती. प्रदेश युवा राजद महासचिव दिलीप राय का कहना है कि राज्य सरकार विकास का ढोंग कर रही है, क्योंकि पूर्व से संचालित केंद्र बदहाली का पर्याय बन गया है. इसे बचाने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है. वहीं युवा सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश कुमार सिंह एवं राजीव कुमार राजू का कहना है कि उक्त केंद्र के विकास की दिशा में राज्य एवं केंद्र सरकार को समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है. वैसे क्या होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि समय रहते अगर इस केंद्र के विकास को लेकर आवश्यक पहल नहीं की गई, तो लाखों की लागत से संचालित केंद्र महज एक दिखावा बन कर रह जाएगा. ज़रूरत है इसके सही कार्यान्वयन कि जिससे कि आम जनों को सीधा लाभ हो और सरकारी राजस्व में हो रहे नुक़सान की भरपाई हो सके. ■

उजियारपुर लोकसभा सीट

कुशवाहा नेताओं में जंग

देखें, किसमें कितना है दम

प्रमोद प्रभाकर
feedback@chauthiduniya.com

उजियारपुर में सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं. जातीय समीकरण का यहां बोलबाला है. दरअसल, यहां से तीन प्रत्याशी कुशवाहा समाज से ही हैं. तीनों ही इस जाति को अपने पाले में करने की जुगत में लगे हुए हैं. देखते हैं, आख़िर यह बिरादरी किस पर भरोसा दिखाती है!

समस्तीपुर ज़िले में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है. दरअसल, यहां उजियारपुर लोकसभा में कुशवाहा नेताओं के बीच घमासान के आसार बन रहे हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में अश्वमेघ देवी ने आलोक कुमार मेहता को लगभग 25 हज़ार मतों से पराजित किया था. गौरतलब है कि इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर वैशाली ज़िले के एक विधानसभा क्षेत्र पातेपुर को जोड़ दिया गया है. अब इस लोकसभा में मोरवा, उजियारपुर, पातेपुर, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर सहित कुल छह विधानसभा से लगभग 14 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. अब यदि इस क्षेत्र के जातीय समीकरण पर प्रकाश डालें, तो हम पाएंगे कि यहां यादव तीन लाख, कुशवाहा दो लाख, वैश्य 50 हज़ार, मुसलमान 1 लाख, दलित 1 लाख, महादलित 1.5 लाख एवं अति पिछड़ा 1 लाख, 50 हज़ार मतदाता हैं. चुनाव अधिकारी के अनुसार, चुनाव के पूर्व एक बार फिर मतदाता सूची की समीक्षा होगी. अब देखना यह है कि राजद और जदयू के बीच तीसरे मोर्चे के बैनर तले नागमणि क्या गुल खिलाते हैं.

अश्वमेघ देवी

आलोक मेहता

नागमणि

जाति समीकरण को मानें, तो आलोक कुमार मेहता, अश्वमेघ देवी और नागमणि तीनों कुशवाहा जाति से आते हैं. तीनों कुशवाहा यहां कुशवाहा जाति को अपने अपने पाले में करने की कवायद में जुट गए हैं. इसके बाद यादव सहित अन्य जातियों को गोलबंद करने की रणनीति भी ये बना रहे हैं. हार-जीत किसी की हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि नागमणि के मैदान में आने के बाद चुनाव में रंग आ जाएगा और वह परिणाम की दिशा को किसी भी तरफ घूमा देने का काम कर सकते हैं. अब नागमणि जीतें या हारें, लेकिन आलोक मेहता और अश्वमेघ देवी के लिए सिरदर्द तो साबित होंगे ही. नागमणि कहते हैं कि मैं फिलहाल तीसरे मोर्चे के गठन में लगा हूं. बिहार की जनता लालू और नीतीश दोनों से ऊब चुकी है. इसलिए एनसीपी का प्रयास है कि बिहार की जनता को नया विकल्प दिया जाए. जहां तक उजियारपुर का सवाल है, एक तरह से यहां के लोग मुझे काफ़ी पसंद करते हैं. आलोक मेहता का मानना है कि पूरे सूबे में नीतीश विरोध की एक तरह से लहर चल रही है. यहां तीसरे मोर्चे का कोई वजूद नहीं है, इसलिए लालू प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन होने वाला है. आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता राजद के पक्ष में मतदान करेगी. ■

चौथी दुनिया
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

10 जून-16 जून 2013
www.chauthiduniya.com

मुसलमानों का सच्चा हितैषी कोई नहीं

वर्ष 2014 के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां बढ़-चढ़ कर यही बताने कीकोशिश में लगी हुई हैं कि वे मुसलमानों के सच्चे हितैषी हैं. लेकिन विकास की बात आते ही, सभी पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हो जाती हैं. इस मसले पर राज्य सरकार का आरोप हैं कि केंद्र अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात तो करती हैं, लेकिन समय से पैसा नहीं देती है. वहीं केंद्र सरकार का कहना हैं कि राज्य सरकार उससे जुड़ीं केंद्रीय योजनाओं को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है. ऐसे हालात में वर्ष 2014 के चुनाव में मुस्लिम सियासत की रणनीति क्या होगी, इसी विषय पर फोकस हैं यह विशेष रिपोर्ट...

अजय कुमार
feedback@chauthiduniya.com

प्रदेश में काम कम, बातें ज़्यादा हो रही हैं. दरअसल, लोकसभा चुनाव की आहट ने काम का माहौल यहां बिल्कुल ख़राब कर दिया है. सभी दलों के दिग्गजों द्वारा अपने-अपने हिसाब से राजनीतिक बिसातें बिछाई जा रही हैं. यह हम सभी जानते हैं कि सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गढ़ है, वहीं दूसरी ओर कई केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता भी राज्य इकाई को दरकिनार करके यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं. और भाजपा नरेंद्र मोदी के सहारे हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने के प्रयास में लगी है. क़रीब-क़रीब सभी राजनीतिक दलों के नेता यही चाहते हैं कि वे आम चुनाव में सपा के ख़िलाफ़ मुख्य मुक़ाबले में रहें, तभी उनको फ़ायदा हो सकता है. सपा की तुष्टिकरण की राजनीति के ख़िलाफ़ जब भाजपा ने हिंदुत्व का अलख जलाया, तो एक बार लगा कि आम चुनाव में मुख्य मुक़ाबला भाजपा-सपा के बीच होगा, लेकिन दूसरे ही पल सपा और बसपा प्रोन्नति में आरक्षण के बाद ब्राह्मण कार्ड खेल कर आगे निकलने की फ़िराक़ में जूझते दिखे. वैसे, हकीकत में अब कांग्रेसी और समाजवादी नेता मुस्लिम आरक्षण के नाम पर अपनी-अपनी रोटियां सेंकने मे लगे हैं.

अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, इसे लेकर अदालत में मुक़दमा विचाराधीन है. लेकिन सच्चर कमेटी के बहाने कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता एक-दूसरे पर गोले दाग़ रहे हैं. अल्पसंख्यकों में ख़ुद को बड़ा हितैषी बताने की होड़ लगी है, पार्टियों में. हैरानी की बात तो यह है कि अपनी ढपली, अपना राग की तर्ज पर अपनी ही पीठ थपथपाई जा रही है. केंद्र का रोना है कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है. वहीं केंद्र राज्य सरकार का आरोप यह है कि केंद्र अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात तो करती है, लेकिन समय से पैसा नहीं देती है. दरअसल, सपा और कांग्रेस जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक के लिए जूझ रहे हैं और भाजपा इसे लेकर दोनों दलों के प्रति तल्ख तेवर अपनाए हुए है, इससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के मुख्य मुक़ाबले में मुस्लिम सियासत का हीबोलबाला रहेगा. बहरहाल, मामला जब मुस्लिम सियासत का हो और इसके लिए दो बड़े दलों (जिनकी यूपी और दिल्ली में हुकूमत भी है) में होड़ मची हो, तो अक्सर ऐसे मौक़े आ जाते हैं, जब दोनों दलों के नेताओं को मजबूरीवश ही सही, साथ बैठना पड़ ही जाता है. ऐसे मौक़ों पर काफ़ी रस्साकशी भी होती है. ख़ुद को बड़ा रहनुमा साबित करने के लिए नेताओं को जुबान से, यानी कुछ बोल कर हमला करना ही पड़ता है. केवल यही नहीं, काग़ज़ी रूप से भी काफ़ी मजबूत रहना पड़ता है. ऐसा ही नज़ारा हाल ही में लखनऊ में देखने को मिला. जब अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रहमान ख़ान लखनऊ पधारे. रहमान का यह दौरा सरकारी ज़रूर था, लेकिन सियासत के रंग में वह पूरी तरह से डूबे नज़र आए. उन्होंने राज्य सरकार पर अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शब्दों के बाण चलाए, तो प्रदेश अल्पसख्ंयक मंत्री आजम खां केंद्र के लिए जहर उगलने की पूरी कोशिश की. केंद्र और यूपी के मंत्रियों की तरफ़ से शब्दों के बाण चले, तो कूटनीति का सहारा भी लिया गया, लेकिन सद्भावना दिखाने की कोशिशों के बीच रिश्तों की तल्खी भी दिखी. यह तल्खी भरा नज़ारा मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिला, जहां सपा एवं कांग्रेस नेता यूपी एवं केंद्र सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में मुसलमानों के हितों के लिए मिलकर काम करने की बात बताने मीडिया से मुखातिब हुए. तल्खी की शुरुआत तब हुई, जब केंद्रीय मंत्री के रहमान ख़ान ने अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के ठीक से अमल न होने की बात कही थी. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खां शायद इस बात से नाराज़ थे. प्रेस कांफ्रेंस में जब अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री एन ईरिंग ने कहा कि वे लोग यूपी में योजनाओं पर बात करने आए हैं, तो आजम खां ने खामियों पर तुरंत ऐतराज जता दिया.

केंद्रीय मंत्री के रहमान ख़ान ने सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि अधिकांश सिफारिशें मान ली गई हैं. तब आजम खां ने बीच में टोकते हुए तल्ख अंदाज़ में कहा कि मुसलमानों के आरक्षण की पहल तो केंद्र को करनी ही चाहिए, क्योंकि आरक्षण ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रूह (आत्मा) है. आरक्षण के बिना यह सिफारिश ऐसे शरीर की तरह है, जिसकी आत्मा न हो. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण लागू है, केंद्र सरकार कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की तर्ज पर आरक्षण देना चाहती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार है. रहमान ने कहा कि बदकिस्मती से मुसलमान को एक पिछड़ा सामाजिक समूह मानने के बजाए उसे धार्मिक समूह मान कर बर्ताव किया जा रहा है. मुसलमानों को आरक्षण देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया है. इस बात को समझने की ज़रूरत है. इस पर आजम खां ने राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गिनाकर नंबर बढ़ाने का प्रयास किया.

खैर, कांग्रेस और सपा के साथ टकराव के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी यूपी में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए केंद्र से भेजी गई रक़म से होने वाले कार्यों पर नजर रखने की तैयारी में जुट गई है. यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के नेता अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाने जा रहे हैं. कमेटी को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय कुछ अधिकार भी देगा. अल्पसंख्यकों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र से प्रदेश को क़रीब 1100 करोड़ रुपये भेजे गए थे, लेकिन अब तक केवल 70 फ़ीसदी पैसा ही ख़र्च हो सका है. दरअसल, तमाम योजनाएं अल्पसंख्यकों तक पहुंचीं ही नहीं. कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मारूफ ख़ान बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यकों की योजनाएं ज़िलों तक न पहुंचने से निराश हैं. वह जल्द ही मंत्रालय की ओर से स्वयंसेवी और गैरसरकारी लोगों की कमेटी बनाने जा रहे हैं. इस कमेटी में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के ज़िलों के लोग भी शमिल होंगे. कमेटी सभी 75 ज़िलों में बनाई जाएगी. यह कमेटी ज़िलों में भेजी जाने वाली छात्रवृत्ति और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आंगनबाड़ी कार्यक्रमों पर नज़र रखेगी.

मामला जब मुस्लिम सियासत का हो और इसके लिए दो बड़े दलों (जिनकी यूपी और दिल्ली में हुकूमत भी है) में होड़ मची हो, तो अक्सर ऐसे मौक़े आ जाते हैं, जब दोनों दलों के नेताओं को मजबूरीवश ही सही, साथ बैठना पड़ ही जाता है. ऐसे मौक़ों पर काफ़ी रस्साकशी भी होती है. ख़ुद को बड़ा रहनुमा साबित करने के लिए नेताओं को जुबान से, यानी कुछ बोल कर हमला करना ही पड़ता है.

केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात करके अल्पसंख्यकों के सपा प्रेम की गहराई नापने की भी कोशिश की. वह शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक और कांग्रेस से नाराज़ चल रहे कल्बे जव्वाद समेत ईदगाह के ईमाम खालिद रशीद फरंगी से भी मिले. कल्बे सादिक सहित क़रीब-क़रीब सभी धर्मगुरुओं ने कांग्रेस पर ही तोहमत लगा दी. वैसे, केंद्रीय मंत्रियों से इन लोगों की क्या बात हुई, इस बात की जानकारी किसी पक्ष ने नहीं दी, लेकिन यह उम्मीद ज़रूर की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री रहमान 2014 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने के लिए इन धर्मगुरुओं की चौखट पर गए थे. हालांकि कांग्रेस के प्रति इन धर्मगुरुओं ने कोई खास झुकाव नहीं दिखाया. केंद्रीय मंत्री द्वारा जहां एक ओर शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक को संतुष्ट करने के लिए उनकी कई मांगों का समर्थन किया गया, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात का भी विश्वास दिलाया गया कि अगर प्रदेश सरकार ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉपोरेशन को पुन: चालू करने के लिए कुछ नहीं किया, तो केंद्र सरकार सहकारी बैंक के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट की व्यवस्था करेगी. वहीं मजलिस-ए- उलेमा-ए-हिंद के महासचिव कल्बे जव्वाद ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के रहमान को दिल्ली में शाह-ए-मर्दा की जमीन पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एवं सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल द्वारा कब्जा किए जाने की बात पर नाराज़गी जताई. रहमान ने यहां भी आश्वासन देकर काम चलाया. ईदगाह के ईमाम खालिद फरंगी ने भी कांग्रेस सरकार को कई मसलों पर कटघरे में खड़ा किया. पूरे दौरे के दौरान रहमान मुस्लिम वोटों के लिए जद्दोजहद करते दिखे, लेकिन उनके सामने समस्या यह भी खड़ी हुई कि उनके युवराज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं से तमाम तरह के वायदे किए थे, वे भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं. इसलिए मुस्लिम धर्मगुरु कांग्रेस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं.

इधर, सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को यथास्थितिवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी क़रार दिया, जिसके राज में भ्रष्टाचार और महंगाई का ग्राफ बढ़ता ही गया है. उदारीकरण के दौर ने देश की संपूर्ण नैतिक व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी हैं. केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए प्रदेश में भाजपा ने बाबरी मस्जिद ध्वंस किया. गौरतलब है कि जातीयता और सांप्रदायिकता की ताक़तों ने कांग्रेस की शह पर ही अपना विस्तार किया है. समाजवादी पार्टी ने उनके ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष किया है. इसके फल: स्वरूप ही केंद्र में सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता में नहीं आ सकीं. सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष और खादी ग्रामोद्योग राज्यमंत्री हाजी रियाज अहमद ने भी कांग्रेस और केंद्र सरकार पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया. हाजी रियाज अहमद ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के रहमान ख़ान के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी, जिसमें उन्होंने सच्चर कमेटी की 92 फ़ीसदी सिफारिशें लागू करने का दावा किया था. उन्होंने कहा कि रहमान ख़ान ग़लतबयानी कर रहे हैं. सच्चर कमेटी पर वह हवा में बातें कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री बताएं कि किस मंत्रालय में सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू हुईं? ख़ुद उनके महक़मे में सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल नहीं हो पाया. उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि मुस्लिम कांग्रेस नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के चुनावी बयानों के झांसे में आने वाला नहीं है. भाजपा ने सपा और कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति पर क़रारा प्रहार करते हुए कहा कि सपा-बसपा और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल हैं. सपा-कांग्रेस साथ-साथ होने पर एक स्वर में बोलते हैं और अलग होते ही एक दूसरे पर दोषारोपण करने लग जाते हैं. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं. न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, की नीति के आधार पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं. यूपी के मुसलमानों से गुजरात के मुसलमान बेहतर स्थिति में हैं. केंद्रीय मंत्री के रहमान ख़ान और मुख्यमंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक पाठक ने कहा कि ये दोनों ही दल मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं. ■

चौथी दुनिया

नई टीम के गठन के बाद पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ज़रूर कुमाऊं और गढ़वाल की यात्राएं शुरू कीं, लेकिन राजनाथ सिंह ने प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को पहली प्राथमिकता दी.

चौथी दुनिया

बकरी के घर में घुसने को लेकर हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बुलहवा मीट टोला के रहने वाले शमीम का अपने पड़ोसी अली हसन से विवाद था.

ग्रामीण शिक्षा को बेहतरीन बनाने की कवायद

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता के साथ रोजगार सृजन की भी आवश्यकता है. प्रदेश में शिक्षा के विकास की अपार संभावनाएं हैं. इसी के मद्देनज़र सपा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दे रही है. यही नहीं, हमने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण क़दम उठाए हैं. कन्या विद्या धन, बेकारी भत्ता एवं लैपटॉप वितरण जैसे कार्यों की शुरुआत इसी उद्देश्य को लेकर हुई है.

मुख्यमंत्री यादव गत दिवस लखनऊ में बख्शी का तालाब स्थित ज्यूरिस लॉ कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कॉलेज के संस्थापक एवं श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन समिति के अध्यक्ष जगजीवन प्रसाद को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के साथ पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए बधाई देते हुए उन्हें हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद में इस बार किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई. न बोरों की कमी हुई और न ही घटतौली की शिकायतें मिलीं. किसानों को समय से खाद, कर्ज़ माफ़ी और मुफ्त सिंचाई आदि सुविधाएं भी मिलीं. ऐसी सुविधाएं किसी अन्य सूबे में नही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में बहुत बदलाव आया है. समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनते ही हमारे सामने बड़ी ज़िम्मेदारियां एवं चुनौतियां थीं. पांच साल के बसपा राज में लूट मची हुई थी. विकास के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री केवल पत्थर और अपनी प्रतिमाएं लगवाती रहीं. समाजवादी पार्टी ने जनहित में जो योजनाएं बनाई हैं, उनकी देश भर में सराहना हुई है. उन्होंने कहा कि बिजली संकट हमने पैदा नहीं किया. यह बिजली संकट बसपा सरकार से विरासत में मिला है. प्रदेश पर बिजली क्षेत्र का 25 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज लदा है. उस समय ट्रांसफॉर्मर लगते ही फुंक गए थे. अब ऊर्जा उत्पादन और बिजली के नए कारखाने लगाने पर तेजी से काम हो रहा है. उक्त बिजली कारखाने 2014-2017 तक तैयार हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और बिजली की खपत यहां लगातार बढ़ रही है. सपा सरकार मांग के अनुसार आपूर्ति के लिए बड़े फ़ैसले कर रही है और विद्युत संकट से निजात जल्दी ही मिल जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में बहुत बदलाव आया है. समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनते ही हमारे सामने बड़ी ज़िम्मेदारियां एवं चुनौतियां थीं. पांच साल के बसपा राज में लूट मची हुई थी. विकास के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री केवल पत्थर और अपनी प्रतिमाएं लगवाती रहीं. समाजवादी पार्टी ने जनहित में जो योजनाएं बनाई हैं, उनकी देश भर में सराहना हुई है.

इससे पहले कॉलेज के संस्थापक जगजीवन प्रसाद एवं प्रबंधक कृष्ण मुरारी ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया. श्री दुर्गा शिक्षा निकेतन समिति के अध्यक्ष राम शंकर यादव ने समिति द्वारा संचालित अन्य कॉलेजों के बारे में जानकारी दी. इस अवसर पर पूर्व सांसद भगवती सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और कारागार एवं खाद्य रसद मंत्री राजेंद्र चौधरी, सांसद श्रीमती सुशीला सरोज, प्रदेश सचिव एसआरएस यादव, राज्यमंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, विधायक शारदा प्रताप शुक्ला, महिला आयोग की अध्यक्ष जरीना उस्मानी, एमएलसी डॉ. मधु गुप्ता, राम शंकर यादव, डॉ. फिदा हुसैन अंसारी, विजय यादव, मोहम्मद एबाद, रामकृपाल सिंह, समिति द्वारा संचालित विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य/प्रधानाचार्य, समिति के सचिव दिनेश सिंह एवं को-ऑर्डिनेटर एस सी पांडेय की उपस्थिति उल्लेखनीय रही. ■

अयोध्या की रामलीला पर ग्रहण

राकेश कुमार यादव feedback@chauthiduniya.com

अयोध्या शोध संस्थान के तुलसी स्मारक भवन में बीते नौ वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन हो रहा है, लेकिन अब इस पर ग्रहण लग गया है. दरअसल, यहां रामलीला मंडलियों एवं कथा व्यासों का भुगतान बीते कई सालों से लंबित पड़ा है. 1 करोड़, 60 लाख रुपये का पिछला बकाया न मिलने से कथा व्यास और रामलीला मंडलियों का परिवार परेशान है. आखिर क्यों नहीं मिल रहा है इन्हें समय पर भुगतान?

अयोध्या शोध संस्थान का नियमित सालाना बजट 1 करोड़, 10 लाख रुपये है. साथ ही सरकार 1 करोड़, 60 लाख रुपये विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को सांस्कृतिक प्रशिक्षण शिविर के नाम पर अयोध्या शोध संस्थान को देती रही है. बीते साल यह सारा धन कुंभ मेला और सैफई महोत्सव के आयोजन में ख़र्च कर दिया गया. नतीजतन, अयोध्या शोध संस्थान बजटविहीन हो गया और उसकी तमाम सांस्कृतिक गतिविधियां ठप होने के कगार पर आ गईं. [illegible]

[illegible]

कलाकारों को कला के प्रदर्शन के लिए अवसर सुलभ कराना और उन्हें रोज़गार देना ही इस योजना का ध्येय है. [illegible]

[illegible] दो खंडों में एक लाख रुपए में छपकर तैयार हैं. लेकिन बजट के अभाव में प्रकाशक को पुस्तक का लागत मूल्य भुगतान कर पाने में अयोध्या शोध संस्थान पूरी तरह असमर्थ है. पुस्तक प्रकाशन मद का बजट सरकार देगी या नहीं, यह भविष्य के गर्भ मे छिपा है. लाखों रुपए फंस जाने से लेखक और प्रकाशक भी परेशान हैं. संस्थान की माली हालत बेहद ख़राब है. इसलिए शासन से संस्थान को आर्थिक मदद वर्ष 2010-11 का 80 लाख एवं वर्ष 2011-12 का 80 लाख रुपये का बजट प्रयाग कुंभ मेले का 50 लाख रुपये का बजट और सैफई महोत्सव का 45 लाख रुपये का बजट भी नहीं मिला है. धन न मिलने से 16 दिसंबर, 2012 से अप्रैल 2013 तक रामलीला मंडलियों का लगभग 10 लाख रुपये और रामकथा करने वाले कथा व्यासों का 5 लाख, 20 हजार रुपये की रक़म के साथ मई माह का भी बक़ाया हो गया है. रामलीला मंडलियों और कथा व्यासों के बक़ाया धनराशि की मांग किए जाने से संस्थान आयोजन को आगे बढ़ा पाने में खुद को असमर्थ पा रही है. यही वजह है कि यहां नववर्ष पर होने वाला समारोह भी नहीं किया जा सका. ■

अविनाश कुमार (अयोध्या शोध संस्थान व्यवस्थापक)

अयोध्या शोध संस्थान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है. अनवरत रामलीला और रामकथा प्रवचन चलाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है. प्रदेश के मनोरंजन कर राज्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक तेजनारायण पांडेय उर्फ पवन के इस आश्वासन पर कि रामलीला मंचन एवं रामकथा अनवरत चलाई जाए और इसके लिए वह प्रदेश सरकार से बजट दिलाएंगे, तीन अप्रैल से दोनों आयोजनों को पुन: शुरू कर दिया गया. हमारे स्तर से रामलीला मंडलियों और कथा व्यासों को आश्वासन दिया गया है कि बकाया बजट आते ही उन्हें तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा.

अयोध्या शोध संस्थान की प्रमुख योजनाएं...

- 20 मई, 2004 से अनवरत रामलीला का प्रतिदिन तुलसी स्मारक भवन में नि:शुल्क मंचन, अब तक लगभग 200 रामलीला मंडलियों ने प्रदर्शन किया है. इसमें देश की सभी पारंपरिक रामलीला मंडलियों ने भागीदारी की है.
- यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत (रामलीला) का अब तक देश के 60 जिलों त्रिनीनाड, सूरीनाम, गयाना, फिजी, थाईलैंड, इंडोनेशिया की रामलीलाओं पर वृहद शोध सर्वेक्षण किया जा चुका है, इसमें 75 हजार छाया चित्र, सीड़ी, तथा अन्य सामग्री शामिल हैं. यह सभी के अवलोकन तथा शोध छात्रों के लिए उपलब्ध है.
- विभिन्न देशों से सांस्कृतिक संबंध विकसित करने की परंपरा में अयोध्या-कोरिया, अयोध्या-थाईलैंड, अयोध्या-ट्रिनिडाड से विशेष सांस्कृतिक संबंध विकसित किए गए, शोध संदर्भ इनके संस्थान में उपलब्ध हैं.

कुशीनगर

अपने ही बने ख़ून के प्यासे

एक सगे भाई ने अपने ही भाई को मार डाला, वहीं पड़ोसियों द्वारा हमले में घायल एक व्यक्ति ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दोनों ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं एक अन्य मामले में दो सगे देवरों ने अपनी ही भाभी का गला काटकर हत्या कर दी...

विद्याधर तिवारी feedback@chauthiduniya.com

हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मलहिया में नथुनी, राम अवतार, सुख्खल गौड़ पुत्र विगन गौड़ बहुत दिनों से अलग घर बनाकर रह रहे थे. सुख्खल मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा इकट्ठा कर घर बनवा रहा था. एक दिन बालू लदी ट्रॉली राम अवतार के दरवाजे पर रखे बखार (धान रखने वाला) के खंभे से हल्का सा टकरा गया. राम अवतार अगले दिन शाम को शराब के नशे में धुत्त घर लौट कर अपने सगे छोटे भाई को गाली देने लगा. लोगों ने बीच बचाव किया, फिर कुछ देर बाद वह अपने भाई को गाली देने लगा. बात बढ़ती गई और राम अवतार ने अचानक ईंट से सुख्खल पर हमला कर दिया. पहला ईंट उसे नहीं लगा, लेकिन दूसरा ईंट उसके सिर के पिछले हिस्से में जा लगा और वह वहीं पर गिर पड़ा. फिर वह उठकर प्रधान के दरवाजे की तरफ दौड़ा और वहीं गिरकर दम तोड़ दिया. उस वक्त राम अवतार ने अफसोस जताते हुए कहा कि शराब ने उसकी बुद्धि ख़त्म कर दी थी. जिस भाई को वह कभी परेशान नहीं देख सकता था, उसे ही मार डाला. सुख्खल के तीन छोटे बच्चे 10 वर्ष की सपना, 8 वर्ष का राहुल और 6 वर्ष के नीरज का रो-रोकर बुरा हाल है. पत्नी ऊषा देवी का भी बुरा हाल है. ऊषा देवी के तहरीर पर पुलिस मुक़दमा अपराध सं. 124/13 धारा 302 दर्ज कर फरार हत्यारे की तलाश में जुटी है.

बकरी के घर में घुसने को लेकर हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बुलहवा मीट टोला के रहने वाले शमीम का अपने पड़ोसी अली हसन से विवाद था. बताया जाता है कि अली हसन ने शमीम के चाचा से खेत रेहन पर ले रखा था. शमीम अरब में काम करने लगा और उसने खेत छुड़ा लिया. इससे अली हसन खार खाए बैठे थे. दोनों पक्षों में अंदर ही अंदर आक्रोश था. 10 मई को दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और शमीम बाज़ार से घर आए, तभी पहले से तैयार बैठे अली हसन अपने घर वालों के साथ मिलकर शमीम पर टूट पड़े. इसमें शमीम सहित कई लोग घायल हो गए. शमीम को सर में ज़्यादा चोटें लगीं. उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा पहुंचाया गया. वहां से उसकी हालत बिगड़ती देख ज़िला अस्पताल रेफर किया गया फिर वहां से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहां भी हालत बिगड़ने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर ले जाया गया. वहां भी हालत में किसी तरह की सुधार नहीं हुई, फिर परिजनों ने घायल शमीम को दिल्ली के भगत चंद्र अस्पताल में दाखिल कराया. वहां इलाज के दौरान 14/15 की रात शमीम की मौत हो गई. 17 मई को शव गांव पहुंचा. मृतक का एकमात्र पुत्र अपने अब्बू को ढूंढ रहा है. पुलिस ने पहले से दर्ज मुकदमा सं. 119/13 में दर्ज धारा 308,323,504,506 भा.द.वि. में संशोधन करते हुए धारा 302 जोड़ दिया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

पिछले 12 अप्रैल, 2013 को कुशीनगर के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के गांव केशव पट्टी में दो सगे देवर विरुद्दीन एवं रियाजुद्दीन ने दिन में ही अपनी भाभी नूरजहां उम्र 30 वर्ष की झोपड़ी में गए और विदेश गए अपने बड़े भाई का फोन नंबर मांगने लगे. वह जब मोबाइल लेने अंदर गई, तभी पीछे से आकर दोनों देवरों ने उसे पकड़ लिया. कुर्बानी देने वाले छूरे से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी और फ़रार हो गए. देवर अपने भाभी से इसलिए नाराज थे, क्योंकि वह बड़े भाई की कमाई अपने पास रख लेती थी. टोना टोटका करके उन्हें परेशान करती थी, जबकि उनकी भाभी ने ही उन्हें पाला था. हनुमानगंज पुलिस ने अतत: उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा अपराध सं. 102/13 में धारा 302 के तहत जेल भेज दिया.

एक अन्य घटना में 20/21 जनवरी, 2012 को जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र भैसहां गांव में एक पति ने अपनी 22 साल की पत्नी सरिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी. शव नारायणी में डाल दी. बाद में हत्यारा पति को जेल भेज दिया गया. 25.01.2012 को जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र बहोर छपरा गांव में एक नवविवाहिता की हत्या के आरोप में पति समेत वकील ससूर को जेल जाना पड़ा. 25.03.2012 को खड्डा थाना क्षेत्र के ही चतुर छपरा गांव में एक 19 वर्षीय युवती की हत्या दिन में ही सगी मां और भाई ने कर दी. मामला प्रेम प्रसंग का था. घर वालों ने शव को जमीन में दफन कर दिया था. बाद में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद लाश बरामद हुई. मां-बाप और भाई जेल चले गए. यह तो मामले की बानगी भर है, जनपद के कई जगहों पर रिश्ते का कत्लेआम हुआ है. ■

उत्तराखंड/ ख़बरें

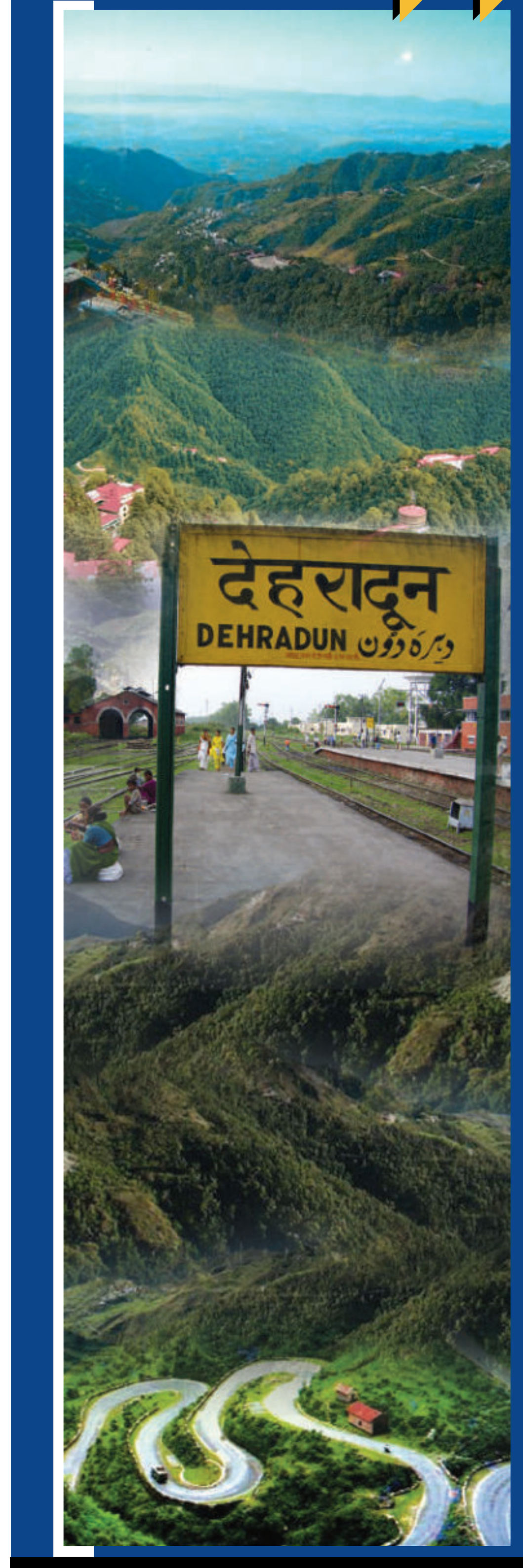

टीम तीरथ पर राजनाथ की सहमति

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2014 की सफलता के लिए तीरथ सिंह रावत की नकेल कसनी शुरू कर दी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने काफ़ी मंथन के बाद टीम तीरथ पर अपनी मुहर लगाई है. साथ ही टीम को कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए, ताकि प्रदेश में भाजपा का ग्राफ पहले के मुक़ाबले और ज़्यादा बढ़ सके. नई टीम के गठन के बाद पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ज़रूर कुमाऊं और गढ़वाल की यात्राएं शुरू कीं, लेकिन राजनाथ सिंह ने प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने को पहली प्राथमिकता दी. हालांकि इस दिशा में अब तक कोई ठोस रणनीति पार्टी के वरिष्ठ नेता अब तक नहीं बना पाए हैं, जिससे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है. स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह राज्य की जनता ने भाजपा को सम्मान दिया, उससे कहीं न कहीं भाजपा में एक अहंकार पैदा हो गया है. यही वजह है कि इस सफलता को टीम तीरथ ने अपनी सफलता मान ली है. पार्टी हाईकमान ने अपने आगामी मिशन की सफलता के लिए अपना जनाधार बढ़ाने के अलावा, हर जनपद में सभाएं करने की योजना भी बनाई है. हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे लेकर गंभीर नहीं हैं. हाईकमान की योजना को फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है. पार्टी को प्रदेश में सशक्त बनाने के मक़सद से प्रदेश प्रभारी थावर चंद्र गहलोत की जगह राधा मोहन सिंह को नया प्रभारी बनाया गया है.

यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि नई टीम के गठन के बाद अब तक प्रदेश की मिनी कोर ग्रुप की बैठकें भी नहीं हो पाई हैं, ताकि पार्टी अपनी भविष्य की रणनीति पर चिंतन कर सके. पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं में निकाय चुनाव के दौरान दिखाई पड़ा, वह उत्साह नई टीम के गठन होने के बाद नहीं दिख रहा है. वहीं इस मसले पर संघ का मानना है कि टीम तीरथ को आगामी लोकसभा चुनाव की मजबूत ज़मीन तैयार करने के लिए प्लानिंग बनाकर ही काम करना होगा. और यह तभी संभव हो पाएगा, जब पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता

एक साथ बैठकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए टिप्स पर विचार-विमर्श करने के बाद ठोस रणनीति बनाकर प्रदेश में कार्य करें. ■

गैरसैंण के मुद्दे पर आपस में भिड़े दिग्गज

राजकुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

राजधानी गैरसैंण का नारा अब विजय बहुगुणा सरकार के गले का फांस बन गया है. इस मामले में प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के साथ बहुगुणा के धुर विरोधी हरीश रावत गुट ऐंड कंपनी हाईकमान के अनुशासन के पाठ को तार-तार कर सरकार को बेनक़ाब करने के खेल में लग गई है. इसकी मुख्य वजह यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राजधानी गैरसैंण को लेकर अपनी पहल को खुद ही कमज़ोर कर दिया है. सरकार पहले तो गैरसैंण में विधानभवन के निर्माण की घोषणा कर आम जनता की आंखों में राजधानी के सपने दिए, फिर देहरादून में विधानसभा भवन और सचिवालय के निर्माण की शुरुआत कर दी. इसे लेकर अब कांग्रेसी नेताओं के बीच आपस में ही तलवारें खिंच गई हैं. गैरसैंण के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में घमासान कम होता नहीं दिख रहा है. इन नेताओं की बयानबाज़ी से यह बात साफ़ हो गई है कि कांग्रेस हाईकमान का अंकुश अपने वरीय नेताओं पर फ़िलहाल नहीं है. गैरसैंण हो या कोई और मुद्दा उनका इस्तेमाल पार्टी के गुट एक दूसरे को लंगड़ी मारने और कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं. स्थायी राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर भयंकर मतभेद हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान वरिष्ठों को चेतावनी दे चुका है कि राजधानी का मसला काफ़ी संवेदनशील है और इस पर पार्टी का बड़ा नेता कोई टिप्पणी नहीं करे. हाईकमान की चेतावनी के बावजूद पार्टी के कई बड़े नेता टिप्पणी करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं. इस मामले में हरीश रावत का कहना है कि दरअसल, उन्हें इन दिनों स्वयं हाईकमान होने का भ्रम हो गया है, जिससे प्रदेश के लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि गैरसैंण पर पार्टी का असली स्टैंड क्या है.

ग़ौरतलब है कि राज्य आंदोलन के समय गैरसैंण हिमालयी जनता में सर्वमान्य रूप से प्रदेश की राजधानी के रूप में उभरी थी. उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान देने वाले हर उत्तराखंडी के मन में राजधानी गैरसैंण एक सपना था, जो राज्य गठन के बाद लगभग टूट गया. समय की मांग और व्यवहारिकता को देखते हुए फ़ौरी तौर पर देहरादून को अस्थायी राजधानी बना दिया गया. स्थायी राजधानी का सवाल उठा, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने इस मसले को दीक्षित आयोग के हवाले कर दिया. बाद में भाजपा की सरकार दीक्षित आयोग को लगातार विस्तार देती रही. अब फिर से स्थायी राजधानी का मसला तब गरमाया है, जब प्रदेश की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश का एक ताज़ा बयान यह आया कि रायपुर में ही नया विधानभवन एवं सचिवालय बनेगा. असल में उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है. कुछ माह पहले सीएम विजय बहुगुणा रायपुर में बनने वाले नए विधानभवन की नींव भी रख चुके हैं. इससे पहले सीएम ने साफ़-साफ़ कहा था कि विधानसभा का एक सत्र गैरसैंण में और दूसरा देहरादून में चलेगा. वैसे, कैबिनेट की एक बैठक भी गैरसैंण में हो चुकी है. वित्त मंत्री के उस बयान के बाद अल्मोड़ा के सांसद प्रदीप टम्टा स्थायी राजधानी के नाम पर उखड़ गए और उन्होंने यह कहा कि वित्त मंत्री को कैबिनेट के फ़ैसले के बाद ही इस तरह का बयान देना चाहिए. टम्टा राजधानी के अलावा भ्रष्टाचार पर भी विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का समर्थन करते हुए बोल गए कि भ्रष्टाचार से प्रदेश में भय का वातावरण बना हुआ है. टम्टा को वैसे भी हरीश के भोंपू के रूप में जाना जाता है.

बहरहाल, गैरसैंण स्थायी राजधानी बने, इसकी तमन्ना यहां के लोगों को काफी पहले से है. गैरसैंण यहां के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री के गैरसैंण में कैबिनेट बैठक करने के बाद प्रदेश के लोगों में उम्मीद बंधी कि अब गैरसैंण में स्थायी राजधानी का सपना पूरा हो जाएगा. हालांकि अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, इससे साफ़ है कि स्थायी राजधानी की पहल खुद कांग्रेस खोती जा रही है और यही मुद्दा कांग्रेस के दिग्गजों में कलह का कारण बन गई है. ■

प्रदेश अध्यक्ष पद की जुगत में हरक सिंह रावत

दो लाभ के पदों पर रहने के कारण मंत्री हरक सिंह रावत का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. फ़ैसला अगर उनके ख़िलाफ़ आया, तो दोनों ही पद उनसे छीन सकते हैं. ऐसे में अब मंत्री जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जुगत में लग गए हैं. लेकिन इस रेस में पहले से ही गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी हैं...

जबर सिंह वर्मा feedback@chauthiduniya.com

हरक सिंह रावत दो लाभ के पदों, उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम एवं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर काबिज रहने के कारण मुश्किल में फंस गए हैं. अब हरक सिंह रावत उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी क़ब्ज़ाने की होड़ में शामिल हो गए हैं. इसके लिए उन्होंने बाक़ायदा दिल्ली में डेरा भी डाल दिया है. अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का समर्थन हासिल होने का दावा कर रहे हरक सिंह अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सिंह समेत केंद्रीय नेतृत्व को अपने पाले में खड़ा करने की जुगत भिड़ा रहे हैं.

दरअसल, उत्तराखंड सरकार हरक सिंह रावत दो लाभ के पदों पर आसीन होने के कारण मुख्य विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर आ गए थे. ख़ासकर, पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने उनके ख़िलाफ़ मोर्चा भी खोल रखा है. भाजपा ने राज्यपाल अजीज कुरैशी से भी हरक सिंह से लाभ के पद छीनने और विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए कई बार दबाव बनाया था. हरक के इस निर्णय को नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई आगामी 11 जून को होनी है. चारों तरफ़ से बढ़ते दबाव और सरकार-संगठन की फ़ज़ीहत कराने के बाद रावत को दोनों लाभ के पद छोड़ने पड़ गए थे, लेकिन भाजपा अब भी उनकी विधानसभा की सदस्यता छीनने पर तुली है. इसके लिए पार्टी ने बाक़ायदा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. हाईकोर्ट का फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया, तो उनका मंत्री पद भी छिन सकता है. ऐसे में संकट से घिरे मंत्री जी यदि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं, तो वे हाईकोर्ट का फ़ैसला आने से पहले ही मंत्री पद से इस्तीफ़ा देकर पूरे झंझट से छुटकारा पा सकते हैं. ऐसा करने के बाद यदि उनकी विधायकी भी चली जाती है, तो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलने से इसकी भरपाई हो जाएगी. दरअसल, पार्टी भी इस संकट से उबरना चाहती है.

प्रदेश अध्यक्ष पद की फेहरिस्त में अभी तक गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम ही चर्चाओं में रहा है. पर अब हरक सिंह रावत के इस होड़ में शामिल होने से मुक़ाबला दिलचस्प हो गया है. इससे पहले उनके ख़ासमख़ास और सांसद प्रदीप टम्टा का नाम भी अध्यक्ष पद की फेहरिस्त में प्रमुखता से शामिल था, जबकि इस समय नैनीताल से पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल का नाम भी चर्चा में है. दोनों दिग्गज कुमांऊ क्षेत्र से आते हैं. वर्तमान में सीएम विजय बहुगुणा का विधानसभा क्षेत्र भी कुमांऊ होने से पार्टी रणनीतिकार अध्यक्ष गढ़वाल से ही बनाया जाए, इस पर ज़ोर दे रहे हैं. वैसे भी कुमांऊ क्षेत्र से यशपाल आर्य लगातार दो बार अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज रह चुके हैं. सांसद सतपाल महाराज अध्यक्ष बनने को लेकर शुरू से ही ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि सुरेंद्र सिंह नेगी मंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं दिखते. वैसे, यशपाल आर्य पर पार्टी के अंदर ही प्रदेश अध्यक्ष या मंत्री में से एक पद पर रहने के लिए लंबे समय से दबाव रहा है. ऐसे में यह तय है कि आने वाला प्रदेश अध्यक्ष किसी दूसरे पद पर आसीन नहीं रहेगा. नेगी के लिए यही बड़ी समस्या है, क्योंकि हरक सिंह रावत गढ़वाल से आते हैं और उनके मंत्री पद पर वैसे ही तलवार लटकी हुई है. इसलिए वह अब अध्यक्ष पद की कुर्सी क़ब्ज़ाने की होड़ में पूरी तरह जुट गए हैं. उनके इर्द-गिर्द घूम रहे संकट को देखते हुए संभव है कि प्रदेश संगठन और दिल्ली हाईकमान एक राय बनाकर हरक सिंह रावत को अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दे. बहरहाल, रावत की ओर से दावेदारी पेश करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जंग काफ़ी रोचक हो गई है. ■

जनगणना 2011

उत्तर प्रदेश के दस साल

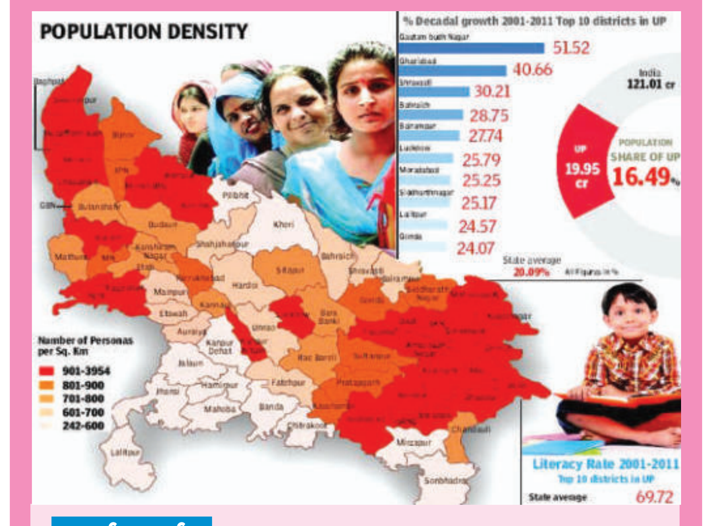

दर्शन शर्मा feedback@chauthiduniya.com

2011 की जनगणना के अनुसार, 71 ज़िलों वाले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 314 पहुंच गई है. इसमें 312 तहसील, 915 नगर और 1,06,774 गांव हैं. गांवों में निवास करने वालों की संख्या 77.7 फीसदी और नगरीय क्षेत्र की आबादी 22.3 फीसदी है. जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी है. वर्ष 2001 में राज्य में स्त्री-पुरूष अनुपात 898 था, जो 2011 में बढ़कर 912 हो गया है. प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 20.7 फीसदी है. पिछले दस सालों में शहर तो बढ़े, लेकिन 678 गांव घट गये हैं. राज्य में एक जिला, 12 तहसीलें और 211 नगर बढ़ गये हैं. 20 करोड़ का आंकड़ा छूने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां दस सालों में 20.20 फीसदी आबादी का इजाफा हुआ है. संयुक्त निदेशक (जनगणना) प्रदीप कुमार के अनुसार, प्रदेश के शहरों की आबादी में 28.8 फीसदी की बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं ग्रामीण आबादी 18 फीसदी के हिसाब से बढ़ी है. इसका मुख्य कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन है. गांवों में किसान घटे और मजदूरों की संख्या ज्यादा है. कुल 6 करोड़ 58 लाख 14 हजार 715 कामगारों में 1 करोड़ 90 लाख 57 हजार 888 किसान ही रह गये हैं. दस वर्ष पहले कुल कामगारों में 41.1 फीसदी किसान थे, जो घटकर अब 29 फीसदी ही रह गए हैं.

2001 और 2011 के बीच प्रदेश में 6 साल के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है. समाज के जानकार इसे सीमित परिवार की सोच या कन्या भ्रूण हत्या मानते हैं. प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बलरामपुर में 950 और सबसे कम 841 बागपत जिले का है. ग्रमीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात बलरामपुर और सबसे कम गौतमबुद्ध नगर में 826 है. नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात मऊ में 954 और सबसे कम 848 मेरठ व गाजियाबाद में है. प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला इलाहाबाद (जनसंख्या 59,59,798) और कांशीराम नगर में सबसे कम जनसंख्या 14,38,156 है. ■

प्रदेश के बड़े-छोटे और सुदूर स्थानों तक पर्यटक आसानी से भ्रमण कर सकेंगे. लघु वायु सेवा से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

लालबत्ती का मोह नहीं त्याग पाए सूचना आयुक्त

जबर सिंह वर्मा feedback@chauthiduniya.com

लालबत्ती पावर का प्रतीक है. ऐसे में इसका मोह सूचना आयोग के अधिकारी छोड़ नहीं पा रहे हैं. यहां तक कि कुछ दिन पहले देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर विनोद चमोली की गाड़ी से परिवहन विभाग ने लालबत्ती उतरवा दी, तब उन्होंने अपने समर्थकों के साथ इतना हंगामा किया कि सरकार को उनकी गाड़ी में लालबत्ती लगाने के लिए पुन: मजबूर होना पड़ा.

प्रदेश का सूचना आयोग लालबत्तियों का मोह छोड़ नहीं पाया है. 12 मार्च, 2012 की अपनी गाड़ियों से लालबत्ती उतारने के फ़ैसले को पलटते हुए सूचना आयुक्तों ने एक बार फिर लालबत्ती लगाने का निर्णय लिया है. इससे पहले देहरादून नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर विनोद चमोली का लालबत्ती प्रेम भी सुर्खियों में आ चुका है. चमोली की गाड़ी पर लगी लालबत्ती परिवहन विभाग ने उतरवाई, तो राजधानी में बखेड़ा खड़ा हो गया. घटना पर मेयर साहब आगबबूला हो गए. जनता के सारे दुख-दर्द भूलकर उन्होंने समर्थकों के साथ इतना हंगामा काटा कि सरकार को उनकी गाड़ी की छीनी हुई लालबत्ती वापस लगाने को मजबूर होना पड़ा.

अब दूसरा वाकया सूचना आयोग का चर्चे में है. प्रदेश सरकार की ओर से गनर वापस लेने के बाद राज्य सूचना आयोग ने मार्च, 2012 में अपने वाहनों पर लालबत्तियां और नेम प्लेट नहीं लगाने का फ़ैसला लिया था. इसके लिए बक़ायदा मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर संकल्प भी पारित किया गया था, लेकिन बीती 22 मई को एक बैठक कर यह संकल्प वापस ले लिया गया. माना जा रहा है कि तब गनर छीनने की प्रतिक्रिया के रूप में सूचना आयुक्तों ने लालबत्ती उतारने का फ़ैसला लिया था. संभवत: उम्मीद यह की जा रही थी कि इस निर्णय के बाद सरकार गनर वापस देने के फ़ैसले पर पुनर्विचार करेगी, लेकिन शासन स्तर पर इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई. ऐसे में, आयुक्त गनर और नेम प्लेट के साथ ही लालबत्ती से भी हाथ गंवा बैठे थे. अब अपने ही संकल्प को पलटते हुए आयुक्तों ने लालबत्ती लगाने का निर्णय लिया है. जिस दिन यह संकल्प वापस लिया गया, उस दिन देहरादून स्थित आयोग के कार्यालय में आरटीआई से जुड़े दर्जन भर कार्यकर्ता अचानक पहुंचे और आयुक्त विनोद नोटियाल समेत कइयों की गाड़ियों में लालबत्तियां लगा दीं. हालांकि बाद में ये लालबत्तियां उतरवा दी गईं. इस अजीबोगरीब घटनाक्रम पर आयुक्त का कहना था कि लालबत्ती लगाने के लिए दो दर्जन से अधिक लोग पहुंच गए थे, जिससे मौक़े पर उनका विरोध करना संभव नहीं था. कार्यकर्ताओं के जाने के बाद लालबत्तियां उतार दी गई थीं.

सरकार द्वारा गनर छीनने के बाद अचानक लालबत्ती नहीं लगाने का संकल्प पारित करना और फिर कुछ ही महीनों बाद अचानक कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं का आयोग के कार्यालय में पहुंचकर आयुक्तों के वाहनों पर लालबत्ती लगाना, उसके बाद आयुक्तों का उनके बचाव में बयानबाजी करना और उसी दिन देर शाम को मुख्य सूचना आयुक्त की मौजूदगी में पारित अपने ही संकल्प प्रस्ताव को वापस लेकर लालबत्ती लगाने का फ़ैसला लेना.

इसमें मजेदार बात यह है कि घटना के तुरंत बाद उसी दिन मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आयुक्तों की बैठक हुई और पूर्व में पारित संकल्प पलटते हुए निर्णय लिया गया कि जो आयुक्त लालबत्ती लगाना चाहते हैं, वह लगा सकते हैं. हालांकि आयुक्त प्रभात डबराल इस फ़ैसले के विरोध में हैं, जबकि दूसरे आयुक्त अनील शर्मा भी दोबारा लालबत्ती लगाने से इनकार कर रहे हैं. बहरहाल, शासन से यह भी पूछा जा रहा है कि वर्तमान में आयुक्तों को लालबत्ती लगाने की अनुमति है या नहीं. बता दें कि 20 जून, 2011 को शासन ने ही आयुक्तों को लालबत्ती लगाने के अधिकार का आदेश जारी किया था.

दरअसल, सरकार द्वारा गनर छीनने के बाद अचानक लालबत्ती नहीं लगाने का संकल्प पारित करना और फिर कुछ ही महीनों बाद अचानक कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं का आयोग के कार्यालय में पहुंचकर आयुक्तों के वाहनों पर लालबत्ती लगाना, उसके बाद आयुक्तों का उनके बचाव में बयानबाजी करना और उसी दिन देर शाम को मुख्य सूचना आयुक्त की मौजूदगी में पारित अपने ही संकल्प प्रस्ताव को वापस लेकर लालबत्ती लगाने का फ़ैसला लेना. यह साफ़ जाहिर करता है कि सूचना आयुक्त का लालबत्ती से नफरत और फिर मोह कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं का गाड़ियों पर लालबत्ती लगाना आदि सब कुछ दबाव के लिए सुनियोजित ढंग से किया गया ड्रामा ही था. आयुक्तों की इसके पीछे की मंशा कुछ खोने की नहीं, बल्कि और अधिक पाने की ही थी. ■

लघु हवाई सेवा से उड़ान भरेगा यूपी टूरिज्म

एक क्रांतिकारी क़दम

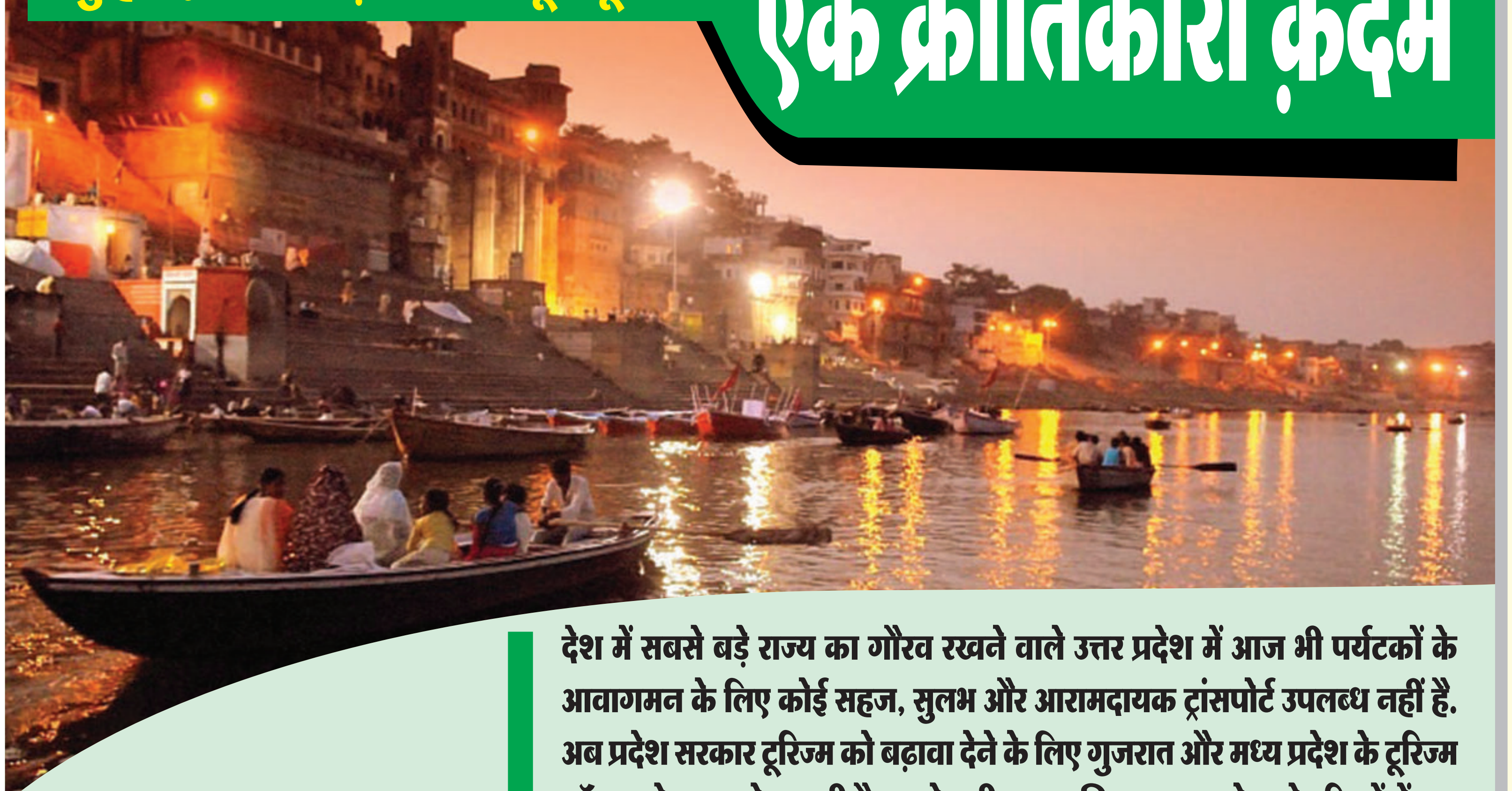

देश में सबसे बड़े राज्य का गौरव रखने वाले उत्तर प्रदेश में आज भी पर्यटकों के आवागमन के लिए कोई सहज, सुलभ और आरामदायक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है. अब प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के टूरिज्म मॉडल को अपनाने जा रही है. इससे यूपी भ्रमण की चाहत रखने वाले टूरिस्टों में एक नई उम्मीद जगी है... आइए जानते हैं कि कैसे संभव होगा यह?

संजय सक्सेना feedback@chauthiduniya.com

देश में सबसे बड़े राज्य का गौरव रखने वाले उत्तर प्रदेश में आज भी पर्यटकों के आवागमन के लिए कोई सहज, सुलभ और आरामदायक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है. अब प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के टूरिज्म मॉडल को अपनाने जा रही है, इससे यूपी भ्रमण की चाहत रखने वाले टूरिस्टों में एक नई उम्मीद जगी है... आइए जानते हैं कि कैसे संभव होगा यह?

प्रदेश सरकार पर्यटन के मानचित्र पर नई ऊंचाइयां छूना चाहती है और दरअसल, इसीलिए वह गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की तर्ज पर अपने यहां भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई क़दम उठाने जा रही है. इसी क्रम में जल्द ही प्रदेश के क़रीब-क़रीब सभी छोटे-बड़े तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों जैसे मोहब्बत की नगरी आगरा, औद्योगिक शहर कानपुर आदि को लघु हवाई मार्ग से आपस में जोड़ दिया जाएगा. इससे विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आसानी से पर्यटक आ-जा सकेंगे. इससे न केवल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी, बल्कि सरकार का ख़ज़ाना भी बढ़ेगा. समाजवादी सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना अगर अमलीजामा पहन लेती है, तो यूपी के लिए यह एक क्रांतिकारी क़दम होगा. बात वर्तमान की करें, तो इसे राज्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज़ादी के 65 वर्षों के बाद भी देश के सबसे बड़े राज्य का गौरव रखने वाले उत्तर प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के आवागमन के लिए कोई सहज, सुलभ और आरामदायक ट्रांसपोर्ट साधन उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते कुछ पर्यटक तो यूपी आना ही पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि इस ओर अभी तक किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं सोचा. देर आए, दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए अखिलेश सरकार यदि राज्य में लघु हवाई मार्ग बना देती है, तो पर्यटन के इतिहास में यह सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. प्रदेश के बड़े-छोटे और सुदूर स्थानों तक पर्यटक आसानी से भ्रमण कर सकेंगे. एक ओर जहां, लघु वायु सेवा से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर इसका फायदा व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी मिलेगा.

बहरहाल, इसका सबसे अधिक फ़ायदा सेवा बुद्धिस्ट सर्किट पर आने वाले पर्यटकों को होगा. इसके अलावा झांसी, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ तथा पर्यटक स्थल और बाद में खजुराहो आदि को भी लघु हवाई मार्ग से जोड़ा जा सकता है. इस संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन का कहना है कि यह प्रस्ताव विचाराधीन है. अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी पर्यटकों को लघु वायु सेवा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तेजी से बनाई जा रही है, जिसका नोडल अधिकारी पर्यटन विभाग को नामित किया जाएगा.

रंजन ने कहा कि लघु वायु सेवा संचालित करने के संबंध में वायु सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया, शर्तें, आधार आदि निर्धारित करने तथा चयन की कार्यवाही करने के लिए प्रमुख सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पर्यटन, नागरिक उड्डयन, वित्त नियोजन, न्याय एवं औद्योगिक विकास आदि विभागों के सचिव/प्रमुख अथवा उनके प्रतिनिधि सचिव को सम्मिलित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में वायु सेवा के विस्तार एवं यातायात की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए हवाई सेवा संचालित किए जाने के लिए प्रदेश के 14 रूटों का चयन किए जाने पर विचार किया जाएगा. इसमें मेरठ-इलाहाबाद, लखनऊ-मेरठ, वाराणसी-आगरा, आगरा-इलाहाबाद, वाराणसी-कुशीनगर, लखनऊ-कुशीनगर, वाराणसी-चित्रकूट, लखनऊ-चित्रकूट, आगरा-चित्रकूट, आगरा-कानपुर, लखनऊ-आगरा, मेरठ-कानपुर, बरेली-इलाहाबाद, लखनऊ-वाराणसी तथा लखनऊ-इलाहाबाद जैसे तमाम वायु मार्ग हो सकते हैं. ■

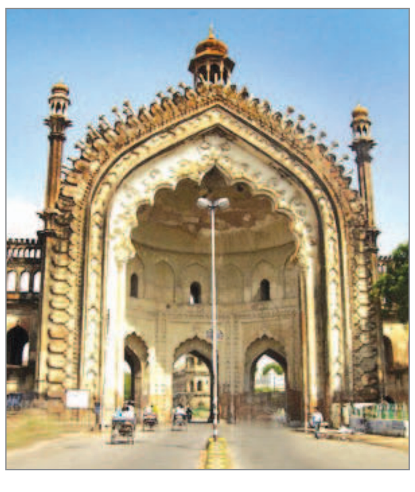

तीसरा विकल्प बनने का सपना हक़ीक़त से कोसों दूर

एक तरफ़ समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में हुए निकाय चुनावों में कुल 69 में से एक सीट जीतने पर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है. वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के बाहर के प्रत्याशी को टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मजबूरी यह साबित करता है कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने का सपना वास्तव में अभी हक़ीक़त से कोसों दूर है...

जबर सिंह वर्मा feedback@chauthiduniya.com

समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड इकाई हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में कुल 69 में से एक सीट जीतने के बाद अपनी खूब पीठ थपथपाई. मैदानी क्षेत्रों में पार्टी समर्थित दो-तीन निर्दलियों की जीत को भी ख़ूब हवा दी गई.इतना ही नहीं, उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार हाशिए पर रहे सपा नेता अचानक अति उत्साहित होकर प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने का दम भरते नज़र आए, लेकिन वह यह भूल गए कि निकाय चुनाव में एक सीट जीतने वाली पार्टी टिहरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर पाई थी. पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से प्रत्याशी खड़ा करने की अपील भी की गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली. केंद्र में कांग्रेस के पाले में खड़ी सपा के स्थानीय नेताओं को यहां भी चुनाव लड़ रहे सीएम पुत्र साकेत बहुगुणा के समर्थन में हथियार डालने पड़े. मालूम हो कि सितारगंज विधानसभा उपचुनावों में भी सपा ने विजय बहुगुणा को समर्थन दे रखा था.

इन तीनों चुनावों से निपटने के बाद समाजवादी पार्टी अब लोकसभा चुनावों में कुछ कर गुजरने का दम भर रही है. प्रदेश की मात्र चार लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सपा की अंदरूनी हालत यह है कि उसे चुनाव लड़वाने के लिए भी यूपी से प्रत्याशी आयात करने पड़ रहे हैं. टिहरी लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सहारनपुर के नीरज चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण सचान ने जब मीडिया से नीरज का परिचय कराया, तो सपा की राजनीतिक ग़रीबी ख़ुद ही सामने आ गई. बायोडाटा देखकर जब उस चयन का अर्थ पूछा गया, तो प्रदेश अध्यक्ष का जवाब था कि नीरज युवा और संघर्षशील नेता हैं. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उनका जन्म उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ है और उनका परिवार कई साल पहले सहारनपुर जाकर बस गया था. उनका कारोबार भी वहीं है. नीरज चौहान ने भी जोड़ा कि अब वह वास्तव में सहारनपुर के हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि जब हरिद्वार और सहारनपुर केवल एक विधानसभा सीट थी, तब उनके दादा महावीर सिंह राणा यहां के दो बार विधायक भी रहे थे. बहरहाल, उत्तराखंड के बाहर के प्रत्याशी को पहाड़ी बाहुल्य टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की मजबूरी साबित करता है कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने का सपना वास्तव में अभी हक़ीक़त से कोसों दूर है. यह हाल तब है, जबकि पड़ोसी राज्य यूपी में सपा की ही सरकार है. जाहिर है, राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पार्टी नेताओं को न सिर्फ़ कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि उत्तराखंड के जनमानस का दिल भी जीतना होगा, जो फिलहाल सपा नेताओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. ■

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366